राष्ट्रीय संस्करण
वर्ष 8 अंक 67
मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 15 अगस्त, 2024
दैनिक जागरण
www.jagran.com
पृष्ठ 14

शुभकामना

आजादी का यह उत्सव हम सब को राष्ट्र के समग्र उत्थान के प्रति सजग-सक्रिय-सचेत करे और सर्वत्र सद्भाव एवं राष्ट्र गौरव की भावना का संचार हो, इस आकांक्षा के साथ 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना।

-प्रधान संपादक

स्वतंत्रता के सारथी

गुरुजन शिक्षा संग सहेज रहे संस्कारों की पाठशाला

कानपुर : शिक्षा के साथ संस्कारों और देशोत्थान का ज्ञान भी मिल जाए तो नई पीढ़ी के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़ता है। इसी तरह का प्रयास कानपुर में किया जा रहा है। ● पेज-7

संपादकीय

और सुगम हो राष्ट्र निर्माण का पथ : भविष्य हमारा है, पर तभी जब हम अपने हिस्से के दायित्वों का निर्वाह करते हुए नए भारत के निर्माण में समुचित सहयोग करेंगे। **गिरीश्वर मिश्र** का दृष्टिकोण।

सदा स्मरण रहे स्वतंत्रता की महत्ता : हमें स्वाधीनता सेनानियों के साथ उनका भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने विभाजन की पीड़ा देखी-भोगी। **आरके सिन्हा** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर देश : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज जब हम देश की साढ़े सात दशक की यात्रा को देखते हैं तो पाते हैं कि इस दौरान देश ने तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। **राजकुमार जैन** का आलेख।

राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका : हमारी आर्थिकी में एमएसएमई क्षेत्र का व्यापक योगदान है। फिर भी इनमें से अनेक उद्यम कई कारणों से कुछ वर्षों के उपरांत ठप हो जाते हैं, लिहाजा इनके लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। **मनोहर मनोज** का दृष्टिकोण। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

सुरक्षित होगा यूपीआइ पेमेंट!

हेल्थ पर नजर बनाए रखते हैं ये गैजेट्स ● पेज-13

इतिहास को याद रखने वाला देश ही बनता है शक्तिशाली : शाह पेज>>6

आतंकी गतिविधियों से निपटने की व्यवस्था चाक चौबंद करें : राजनाथ पेज>>7

राज्य वसूल सकते हैं खनन भूमि व खनिज पर 2005 से बकाया टैक्स

सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8 :1 के बहुमत से दिया फैसला

▸ राज्यों को एक अप्रैल, 2005 के बाद से ही मिलेगी रायल्टी और कर

1 अप्रैल, 2026 से 12 वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से शुरू होगा भुगतान

25 जुलाई, 2024 से पूर्व के बकाया टैक्स पर जुर्माना या ब्याज नहीं होगा देय

माला दीक्षित ● जागरण

नई दिल्ली : खनिज समृद्ध राज्यों को वित्तीय लाभ पाने का बड़ा मौका मिला है। राज्यों को खनन भूमि और खनिज पर कर लगाने का अधिकार देने वाला सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनन कंपनियों से खनन भूमि और खनिज का बकाया टैक्स वसूलने की इजाजत दे दी है, हालांकि संतुलन कायम रखने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। यह फैसला बुधवार को नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से दिया। इसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत खनन कंपनियों की 25 जुलाई के फैसले को फैसले की तिथि से (प्रोस्पेक्टिव) लागू करने की मांग खारिज कर दी। फैसले के बाद खनन कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है।

कोर्ट के इस फैसले से खनिज व खदान संपन्न राज्यों जैसे, ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा होगा। उनके लिए खनन कंपनियों से पुराना बकाया वसूलने की राह खुल गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ऋषिकेश राय, अभय एस. ओका, जेबी पार्डीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुइयां, सतीश चंद्र शर्मा और अगस्टीन जार्ज मसीह ने बहुमत से यह फैसला दिया है। जबकि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि उन्होंने 25 जुलाई का मूल फैसला बहुमत से असहमति जताते हुए दिया था। जस्टिस नागरत्ना ने माना था कि राज्यों को खनिज या खनिज भूमि पर रायल्टी या टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है।

बुधवार को प्रधान न्यायाधीश ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य पिछले टैक्स की फिर से मांग कर सकते हैं, लेकिन यह एक अप्रैल, 2005 के पहले हुए लेनदेन पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा बकाया टैक्स का भुगतान अगले 12 वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा जो कि एक अप्रैल, 2026 से शुरू होगा। साथ ही 25 जुलाई, 2024 से पहले के बकाया टैक्स पर जुर्माना या ब्याज नहीं वसूला जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पट्टा धारकों पर 25 जुलाई, 2024 के पहले के बकाया पर ब्याज और पेनाल्टी माफ कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने जब 25 जुलाई को राज्यों को खनन भूमि और खनिज पर टैक्स या रायल्टी लगाने का अधिकार देने वाला फैसला दिया था, उसी समय केंद्र सरकार और सरकारी उपक्रमों व खनन कंपनियों की ओर से फैसले को प्रास्पेक्टिव लागू करने की मांग की गई थी। केंद्र ने कहा था कि अगर खनिज पर लगाई गई रायल्टी वापस करने का आदेश 1989 से लागू हुआ तो उसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सार्वजनिक उपक्रमों का खजाना खाली हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती मोटे अनुमान के मुताबिक यह रकम 70,000 करोड़ रुपये बनती है।

विस का यह विशेषाधिकार कि वे बकाये को भुला दें

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को बहुमत के फैसले में कहा था कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि व खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी शक्ति है। कोर्ट ने 1989 के इंडिया सीमेंट मामले में रायल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले तीन दशक पुराने फैसले को खारिज कर दिया था। मध्य प्रदेश व राजस्थान जैसे कुछ राज्यों द्वारा बकाया टैक्स वसूलने की इच्छा नहीं जताने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि यह विधानसभाओं का विशेषाधिकार है कि वे बकाये को भुला दें।

राज्यों के कानून की वैधानिकता पर नियमित पीठ करेगी सुनवाई पेज>>3

स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू

नई दिल्ली : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और पैनेसिया बायोटेक ने भारत में डेंगू की वैक्सीन विकसित करने के लिए पहली बार तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया है। पैनेसिया बायोटेक ने भारत की स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन 'डेंगीआल' को बनाया है। इस परीक्षण में पहले प्रतिभागी को आज रोहतक में टीका लगाया गया। (पेज-5)

भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है बांग्लादेश

ढाका : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है और द्विपक्षीय सहयोग में विकास करना चाहती है। लेकिन हाल ही में दिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान इस लिहाज से सकारात्मक नहीं है। यह बात अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रभारी मुहम्मद तौहीद हुसैन ने कही है। (पेज-11)

कोलकाता में प्रशिक्षु डाक्टर से सामूहिक दुष्कर्म की आशंका

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई दरिंदगी की खौफनाक तस्वीर

महिला चिकित्सक हत्याकांड

▸ चोटों के निशान बता रहे अपराध में शामिल थे एक से ज्यादा लोग, पीड़िता के शरीर में मिला 150 मिलीग्राम वीर्य

▸ सीबीआइ ने शुरू की आरजी कर अस्पताल की डाक्टर से दरिंदगी की जांच, मौके का किया मुआयना

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डा. सुवर्ण गोस्वामी ने दावा किया है कि मृतका के शरीर पर चोटों के निशानों से पता चलता है कि इस जघन्य अपराध में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। डाक्टर ने कोलकाता पुलिस के शुरुआती दावों का खंडन किया है, जिसमें पुलिस का कहना था कि अपराध में केवल एक व्यक्ति ही शामिल था। आल इंडिया फेडरेशन आफ गवर्नमेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के अतिरिक्त महासचिव डा. सुवर्ण ने पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम वीर्य मिलने का दावा किया है। यह बात मृतका के माता-पिता ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष कही थी। डा. गोस्वामी का कहना है कि इतना वीर्य एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आशंका है कि एक से अधिक लोगों ने दुष्कर्म किया था। मृतका के शरीर पर चोट के कई निशान थे, जो एक क्रूर और हिंसक हमले का संकेत देते हैं।

शव दिखाने के लिए मां को तीन घंटे बिठाए रखा : महिला डाक्टर की मां ने मीडिया को बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। विनती की कि वह मुझे मेरी बेटी को देखने दें। हमें तीन घंटे बाद दोपहर दो बजे उसका शव दिखाया। मेरे साथ एक रिश्तेदार भी था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पीड़िता ने उस रात अपनी मां को फोन किया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 12 सदस्यीय टीम ने पीड़िता के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।

पैर और धड़ को जोड़ने वाली हड्डी के टूटने की आशंका : घटना के बाद मौके पर पहुंचे एक रिश्तेदार ने बताया कि मृतका के पैर 90 डिग्री पर अलग-अलग थे। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पेल्विक गर्डल टूट न जाए। पेल्विक गर्डल दरअसल हड्डियों की बेसिन के आकार की संरचना है जो पैर और धड़ को जोड़ती है। पीड़िता के माता-पिता ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि रिकार्ड में ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि उनकी बेटी की गला घोंटकर हत्या में कम से कम तीन व्यक्ति शामिल थे।

25 अधिकारियों की टीम कर रही जांच : सीबीआइ ने बुधवार को घटना की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सीबीआइ के अधिकारियों के साथ एम्स की मेडिकल टीम व फोरेंसिक विशेषज्ञ भी कोलकाता पहुंचे। 25 अधिकारियों की टीम तीन भागों में बंटकर जांच कर रही है। एडिशनल डायरेक्टर टीम को लीड कर रहे हैं। सीबीआइ की टीम जांच पूरी होने तक वहीं रहेगी। टीम उस सेमिनार हाल में भी गई जहां चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। दो अधिकारियों ने मंगलवार को ही हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही देर बाद कोलकाता पुलिस से इस केस से जुड़े कुछ दस्तावेज ले लिए थे। सीबीआइ ने दिल्ली में दुष्कर्म व हत्या समेत चार धाराओं में मामला दर्ज किया है।

कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या के बाद बुधवार को जांच के लिए पहुंचे सीबीआइ अधिकारी व अन्य। प्रेट्र

राहुल ने कहा- आरोपितों को बचाने की हो रही कोशिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोलकाता में जूनियर डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपितों को बचाने की कोशिश हो रही है। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महिला डाक्टर के साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुल कर सामने आ रही है, उससे डाक्टरों और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं।

ममता ने की सीबीआइ से 18 अगस्त तक जांच पूरी करने की मांग पेज>>5

बंगाल में आधी रात को सड़कों पर उतरीं महिलाएं पेज>>5

उत्तराखंड में नर्स से दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद हत्या, पत्थर के कूच दिया चेहरा पेज>>5

बलिदानी कर्नल मनप्रीत समेत चार को कीर्ति चक्र

▸ अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत हुए थे बलिदान

▸ सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 103 जवानों को मिले वीरता पुरस्कार

कर्नल मनप्रीत सिंह। सौ. सेना

रवि कुमार। सौ. सेना

मल्ला राम गोपाल नायडू। सौ. सेना

हुमायूं मुजम्मिल भट। सौ. सेना

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले साल सितंबर में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान में अग्रिम मोर्चे पर नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तीन अन्य सुरक्षा कर्मियों- राइफलमैन रवि कुमार (मरणोपरांत), मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और जम्मू-कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं मुजम्मिल भट (मरणोपरांत) को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।

कर्नल सिंह को 19 राष्ट्रीय राइफल्स के अपने कार्यकाल के दौरान सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। हुमायूं मुजम्मिल भट ने भी उसी आपरेशन में अपना बलिदान दिया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कुल 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। चार कीर्ति चक्र के अलावा वीरता पुरस्कारों में 18 शौर्य चक्र (चार मरणोपरांत), एक बार टू सेना मेडल, 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और छह वायुसेना मेडल शामिल हैं।

शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं में आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल पवन सिंह, पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) की 21वीं बटालियन के मेजर सीवीएस निखिल, सिख लाइट इन्फैंट्री के मेजर आशीष धोंचक (मरणोपरांत), आर्मी सर्विस कोर/राष्ट्रीय रायफल्स की 34वीं बटालियन के मेजर त्रिपतप्रीत सिंह और आर्टिलरी रेजिमेंट/राष्ट्रीय रायफल्स की 34वीं बटालियन के मेजर साहिल रंधावा शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर राइफल्स की पांचवीं बटालियन के सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया, आर्टिलरी रेजिमेंट/राष्ट्रीय राइफल्स की 56वीं बटालियन के नायब सूबेदार पी पाबिन सिंघा, सिख लाइट इन्फैंट्री/राष्ट्रीय राइफल्स की 19वीं बटालियन के सिपाही प्रदीप सिंह (मरणोपरांत), जम्मू-कश्मीर पुलिस के अब्दुल लतीफ और भारतीय नौसेना जहाज कोलकाता के कमांडिंग आफिसर कैप्टन शरद सिंसुवाल को भी शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है।

अन्य शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं में नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव, वायुसेना के विंग कमांडर वर्नोन डेस्मिंड कीन, वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, सीआरपीएफ के पवन कुमार (मरणोपरांत) और सीआरपीएफ के देवन सी (मरणोपरांत) शामिल हैं। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट लखवीर, सीआरपीएफ के राजेश पांचाल और सीआरपीएफ के ही मलकीत सिंह को भी शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा।

माफिया अतीक के बेटे को ढेर करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पदक पेज>>3

ग्रामीण बैंक कर्मियों को 1993 से मिलेगी पेंशन

कानपुर : ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को जल्द ही 1993 से पेंशन और कंप्यूटर वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान होगा। सुप्रीम कोर्ट में वित्त मंत्रालय द्वारा शपथ-पत्र दिए जाने के बाद कोर्ट ने 12 अगस्त को निर्देश जारी कर बकाये का बड़ा हिस्सा दीपावली से पहले देने को कहा है। आदेश का लाभ 60 हजार लोगों को पेंशन के रूप में और 12 हजार को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। (पेज-6)

विनेश फोगाट की अपील खेल पंचाट ने खारिज की

नई दिल्ली : पेरिस ओलिंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय के विरुद्ध भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील को खेल पंचाट ने बुधवार को खारिज कर दिया। पिछले सप्ताह विनेश को ओलिंपिक में 50 किग्रा फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश ने इसके विरुद्ध अपील दायर कर उन्हें संयुक्त रूप से रजत पदक देने की मांग की थी। (पेज-12)

डोडा मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, कैप्टन बलिदान

कैप्टन दीपक सिंह। (फाइल) सौ : सेना

जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ स्थल के निकट बुधवार को तैनात जवान। प्रेट्र

▸ घेरे में फंसे तीन अन्य आतंकियों के सफाये के लिए 'आपरेशन अस्सर' जारी, एक वीडीजी सदस्य भी घायल

▸ देहरादून के रहने वाले कैप्टन दीपक ने गोली लगने के बावजूद नहीं छोड़ा मोर्चा, साथियों को करते रहे प्रेरित

व्हाइट नाइट कार्प्स के सभी रैंक कैप्टन दीपक सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। हम शोक संतप्त परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। -व्हाइट नाइट कार्प्स, एक्स

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर

स्वतंत्रता दिवस से पहले डोडा जिले के अस्सर में बुधवार को हुई भीषण मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। इस आपरेशन में आतंकियों का डटकर मुकाबला करते हुए सेना की 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। वह देहरादून के रहने वाले थे। उन्होंने गोली लगने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा और लगातार अपने जवानों को आतंकियों को मार गिराने के लिए प्रेरित करते रहे। मुठभेड़ में ग्राम रक्षा समूह (वीडीजी) का एक सदस्य भी घायल हुआ है। एक अन्य आतंकी के जख्मी होने की सूचना है। फिलहाल, घेरे में फंसे तीनों आतंकियों को मार गिराने के लिए 'आपरेशन अस्सर' जारी है। मुठभेड़ स्थल से अमेरिका निर्मित एम-4 कार्बाइन व एके-47 राइफल और खून से सने चार बैग के साथ अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इससे पहले भी डोडा में हुई मुठभेड़ में आतंकियों से एम-4 कार्बाइन मिलती रही है।

जम्मू के पर्यटनस्थल पत्नीटाप की पहाड़ियों के साथ लगते डोडा के अस्सर में अकार के जंगलों में यह मुठभेड़ ऐसे समय चल रही थी, जब जम्मू संभाग में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं के कारगर जवाब के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, रक्षा सचिव से लेकर खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हुए। राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को भी दिल्ली में चुनाव आयोग की केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक हुई। बताते हैं कि जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार देर शाम आपरेशन शुरू किया था। रातभर घेराबंदी के बाद बुधवार तड़के आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान सुरक्षाबलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सेना के कैप्टन दीपक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां वह वीरगति को प्राप्त हुए।

एक अन्य आतंकी के घायल होने या मारे जाने की भी सूचना है, लेकिन सेना ने अभी एक आतंकी के ही मारे जाने की पुष्टि की है। इस बीच, एडीजीपी आनंद जैन ने मुठभेड़ स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।

मंथन

देशभर से आईं महिला सरपंचों की राष्ट्रीय कार्यशाला में 'सरपंच पति' प्रथा पर जताई गई चिंता, पंचायतीराज सचिव ने कहा- पंचायत सीरीज में सच देखकर हुआ दुख, बदलनी होगी व्यवस्था

पंचायतीराज व्यवस्था में 'फुलेरा' जैसी फांस, प्रधान पति क्यों प्रभावी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पंचायत वेब सीरीज में प्रधान मंजू देवी के होते हुए भी पंचायत के निर्णयों में प्रधान पति ब्रजभूषण का दखल इस सीरीज या सीन को भले ही 'हिट' कर रहा हो, लेकिन इसमें दिखाया गया सच पंचायतीराज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की अधूरी सफलता की कहानी कहता है। फुलेरा (सीरीज में ग्राम पंचायत का नाम) जैसी फांस किस हद तक चुभ रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देशभर से आमंत्रित की गईं पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय कार्यशाला में 'सरपंच पति' प्रथा को विषय के रूप में शामिल कर मंथन किया गया।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने अपने पति व राज्यों के अधिकारियों के साथ दिल्ली पहुंचीं महिला सरपंच, ब्लाक पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत अध्यक्षों की राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि देशभर की लगभग ढाई लाख पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44 प्रतिशत है। इसके बावजूद नेतृत्व को लेकर जारी चुनौती पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दिनों एक कंपनी के अधिकारी ने पूछा कि 'पंचायत' वेब सीरीज देखी है या नहीं। इसलिए अवकाश लेकर पूरी सीरीज देखी। इसमें दिखाया गया है कि प्रधान महिला है मगर सारा काम उसका पति संभालता है। सचिव ने कहा कि यह व्यवस्था बदलने के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की अलग व्यवस्था का भी विचार है।

दूसरे सत्र में मंत्रालय की संयुक्त सचिव ममता वर्मा, मिजोरम सरकार की सचिव टेरेसी वनलालहुरई और केरल सरकार की प्रमुख सचिव डा. शर्मिला मैरी जोसेफ के अलावा गुजरात की राजकोट जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीनाबेन संजयभाई रंगानी, लखनऊ के मलिहाबाद की अटारी ग्राम पंचायत प्रधान संयोगिता सिंह चौहान ने अपने अनुभव साझा किए। उनकी बातों का निचोड़ था कि महिलाएं चुनाव में चेहरा होती हैं, लेकिन फिर पति ही काम संभालते हैं।

राजस्थान के झुंझनू से ग्राम पंचायत लांबी अहीर की प्रधान नीरू यादव ने इससे सहमति जताई, जो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब वह सरपंच बनीं तो गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सरपंच यानी पति को बुला दो। बहुत प्रयास के बाद गांव वालों को समझा सकीं कि वह खुद प्रधान हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को महिला सरपंचों की राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करतीं किरण बेदी। प्रेट्र

महिला प्रधानों को सरकार दिलाए स्कूटी : किरण बेदी

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की संस्थापक पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि पंचायतों से उनका लगाव गहरा है। वह पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटने के बाद से सपना पाले हैं कि ग्राम प्रधान बनें। वह मानती हैं कि महिलाओं के लिए अब भी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग तरह की हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी तय करें, लक्ष्य निर्धारित करें। बेदी ने मंत्रालय के अधिकारियों से आग्रह किया कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए मोबिलिटी और विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। महिला प्रधान यदि महीने में 25 दिन अपनी पंचायत में भ्रमण करने का संकल्प लें तो सरकार उन्हें अनुदान पर या किसी योजना से इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध कराए।

****

1 से 15 सितंबर तक राजधानी के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी, नगर निगम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूलों में स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 अगस्त, 2024

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
15 अगस्त	33.0	26.0
16 अगस्त	32.0	26.0
नोएडा		
15 अगस्त	32.0	25.0
16 अगस्त	33.0	25.0
गुरुग्राम		
15 अगस्त	31.0	26.0
16 अगस्त	32.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

अग्निशमनकर्मियों को सेवा पदक व राष्ट्रपति पदक से किया जाएगा सम्मानित

नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस पर अग्निशमन विभाग के छह कर्मियों को सेवा पदक व राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक ने बताया कि दिल्ली के नागरिकों के जीवन और संपति को बचाने में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर वीरता के लिए तीन अग्निशमन सेवा पदक (जीएम), विशिष्ट सेवा के लिए एक राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) और सराहनीय सेवा के लिए दो अग्निशमन सेवा पदक (एमएसएम) प्रदान किया गया है। (जासं)

सिसोदिया का पदयात्रा कार्यक्रम कल से

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के चलते पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा कार्यक्रम टाल दिया है। ग्रेटर कैलाश से 14 अगस्त को उनका पदयात्रा कार्यक्रम शुरू होना था जो स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों से निरस्त कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 16 अगस्त से शुरू होगा। सिसोदिया आबकारी घोटाले मामले में 17 माह बाद जमानत पर जेल से छूट कर आए हैं। (राब्यू, जागरण)

लूटपाट करने वाले दंपती को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली : उत्तरी जिले की बाड़ा हिंदू राव पुलिस की टीम ने बंटी-बबली की तर्ज पर लूटपाट करने वाले दंपती को गिरफ्तार किया है। चोरी का मोबाइल बरामद करते हुए आरोपितों को रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुरुष आरोपित का दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज डकैती, झपटमारी, नाइट सैंधमारी, चोट, चोरी और आर्म्स एक्ट के 30 आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है। (जासं)

जमीन से आसमान तक रहेगा कड़ा पहरा

चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा ▶ बुधवार देर रात 12 बजे दिल्ली की सभी सीमाएं कर दी गईं सील

लाल किला के चारों तरफ की सड़कों पर अर्द्ध सैनिक बल व दिल्ली पुलिस तैनात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। राजधानी में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी तरह के नापाक मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर हर तरह की सतर्कता बरती जा रही है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर लाल किले तक सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। लालकिला के चारों तरफ व प्रधानमंत्री समेत सभी वीवीआइपी मेहमानों के आने जाने वाले रूटों पर जगह-जगह पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। हवाई हमले से निपटने के लिए वायु सेना के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा दिया जा रहा है। बुधवार रात ही राजधानी को सुरक्षाकर्मियों ने अपने हवाले ले लिया। बुधवार देर रात 12 बजे दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गईं। दिल्ली की सीमाओं में व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। केवल निजी वाहनों को ही सघन तलाशी के बाद दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत दी गई।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कड़ी निगरानी करते सीआइएसएफ के जवान। ध्रुव कुमार

दोनों विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव व मधुप तिवारी ने अपने-अपने जोन में कई जगहों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था में सेना के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी व एयरफोर्स को भी लगाया गया है। बृहस्पतिवार तड़के तीन बजे से ही दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी अपने-अपने इलाके में गश्त करना शुरू कर देंगे। प्रमुख आयोजन स्थल लाल किला सहित आसपास के इलाके मध्य दिल्ली व नई दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लालकिला के आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर कई दिन पहले सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए थे। वे तेज क्षमता वाली दूरबीन से ऊंचाईयों से हर शख्स पर नजर रख रहे हैं। स्पेशल सेल की सर्विलांस टीम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। लाल किला के 10 किलो मीटर की परिधि में जगह-जगह मचान व मोर्चा बनाए गए हैं, जहां एलएमजी व एमपी 5 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस अर्द्ध सैनिक बलों के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। सभी जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मियों से कहा गया है कि वे लगातार सड़कों पर गश्त करते रहें और हर शख्स पर नजर रखें।

मानव बम बनकर आत्मघाती हमला कर सकते हैं दहशतगर्द

स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा में जुटी दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि दहशतगर्द मानव बम बनकर आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अलर्ट में बताया गया है कि दहशतगर्द मानव बम के जरिये वीवीआइपी को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ, लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के जरिये इस तरह की हरकत कराने के फिराक में है। कुछ दिन पहले सेल ने आइएसआइएस के एक आतंकी को बाहरी दिल्ली से गिरफ्तार भी किया था। उसकी योजना भी दिल्ली को दहलाने की थी। इस तरह के इनपुट मिलने के बाद लाल किले व वीवीआइपी के आने जाने वाली रूटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपित जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को तत्काल अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं, वे याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया। मामले को 23 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने ये आदेश केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जारी किए। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं। एक में दिल्ली हाई कोर्ट के सीबीआइ गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले आदेश को चुनौती दी गई है और दूसरी में जमानत मांगी है। केजरीवाल को जमानत दिए जाने की अपील करते हुए सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए कानून में उन्हें जमानत दिए जाने के कोर्ट के तीन आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद निचली अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी, लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। जबकि पीएमएलए में धारा-45 शामिल है जो सीबीआइ के केस में नहीं है।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला

▶ शीर्ष कोर्ट ने कहा- अभी वे सीबीआइ को जारी कर रहे याचिका पर नोटिस

अरविंद केजरीवाल। फाइल

आप को भरोसा, सुप्रीम कोर्ट से सीएम को मिल जाएगी जमानत

राज्य ब्यूरो, जागरण. नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी एसजी ने खारिज नहीं की है। बुधवार की सुनवाई में उसने सिर्फ 23 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। हर कोई जानता है कि यह एक फर्जी मामला है, जिसमें किसी भी आप नेता के खिलाफ कोई बरामदगी या सुबूत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी।

निगम ने नोटिस पर कोचिंग मालिक के खिलाफ क्यों नहीं की कार्रवाई

कोचिंग सेंटर हादसा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोचिंग सेंटर हादसे में बेसमेंट के चार सह-मालिकों ने अपनी जमानत याचिका पर दलील दी कि उनका तीन छात्रों की मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। मामले की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने सवाल किया कि नगर निगम ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सुरक्षा उपायों को लेकर एक छात्र ने दिल्ली सरकार के पोर्टल पर राव आइएएस स्टडी सर्किल के मालिक के खिलाफ शिकायत की थी। छात्र ने शिकायत की थी बेसमेंट में कोई सुरक्षा उपाय नहीं है जिससे भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि, कारण बताओ नोटिस पर कोचिंग सेंटर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही निगम की ओर से कोई कार्रवाई की गई।

अदालत ने बेसमेंट मालिकों से सवाल किया कि आपकी जमीन पर बेसमेंट में पुस्तकालय चल रहा था। क्या किरायेदार ने आपको इस बारे में सूचित नहीं किया। यह चिंता का विषय है। अदालत ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि इसे 48 घंटे के भीतर बंद किया जाना चाहिए फिर भी अधिकारी चुप क्यों बैठे थे? आरोपितों की ओर से पेश अधिवक्ता अमित चड्ढा अदालत को बताया कि निगम अधिकारी एक साल तक इंतजार करने के बजाय बेसमेंट को सील कर सकते थे। कोर्ट में अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

अधिवक्ता अमित चड्ढा ने दलील दी कि बीएनएस की धारा 105 (गैरइरादतन हत्या) लगाने के लिए जानकारी के साथ-साथ मौत का इरादा भी होना चाहिए। उपहार सिनेमा अग्निकांड के फैसले का जिक्र करते हुए, जिसमें आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 304ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत दोषी ठहराया था, अधिवक्ता ने दलील दी कि सिनेमा हाल के मालिकों को जानकारी थी (लेकिन इरादा नहीं था)।

अस्पतालों में वरिष्ठ फैकल्टी ने जूनियर को दिया समर्थन, मरीजों को हुई परेशानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की फैकल्टी एसोसिएशन ने जूनियर डाक्टरों की हड़ताल को समर्थन दिया है। एम्स में बुधवार शाम को फैकल्टी के सदस्यों ने जूनियर डाक्टरों के साथ मार्च निकाला। हालांकि इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पतालों के बाहर मरीज और तीमारदार पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने पहले से नंबर लिया था, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें लौटना पड़ा।

कोलकाता के अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फैकल्टी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया है।

एम्स की फैकल्टी एसोसिएशन ने कहा कि वह स्पष्ट रूप से अमानवीय कृत्य की निंदा करती है जिसने एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने वाली एक होनहार युवा डाक्टर की जान ले ली। इस घटना ने न केवल संभावनाओं से भरे भविष्य को चकनाचूर कर दिया, बल्कि पूरे चिकित्सा समुदाय को भी गहरा आघात पहुंचाया है। इस त्रासदी के जवाब में आरजी कर मेडिकल कालेज प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता से निराश हैं।

अधिकारियों से सभी डाक्टरों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाना चाहिए। ऐसा कानून यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा पेशेवर बिना किसी डर के और हिंसा के ऐसे जघन्य कृत्यों का शिकार हुए बिना अपने मरीजों का इलाज कर सकें। उन्होंने कहा, रेजिडेंट डाक्टरों के पूर्ण समर्थन में हैं। आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डाक्टरों ने सुरक्षित माहौल देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे विरोध स्वरूप हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। जबतक ऐसा नहीं होता है, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

डाक्टरों की हड़ताल के दौरान ओपीडी बंद होने पर लोकनायक अस्पताल के बाहर बीमार बच्चे को लेकर बैठी महिला। चंद्र प्रकाश मिश्र

सलमान खुर्शीद ने जीता आइआइसीसी अध्यक्ष का चुनाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर (आइआइसीसी) के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आइआइसीसी में 20 साल बाद यह बदलाव हुआ है। खुर्शीद के पहले लगातार चार बार व्यापारी सिराजुद्दीन कुरैशी अध्यक्ष थे। वैसे, बोर्ड आफ ट्रस्टी के सदस्य के रूप में वह चुनाव जीतकर आइआइसीसी में वह इस बार भी बने रहेंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही बोर्ड आफ ट्रस्टी के सात सदस्य तथा कार्यकारी समिति के चार सदस्यों के लिए 11 अगस्त को मतदान हुआ था। कुल 13 पदों के लिए 75 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके लिए मतगणना 12 अगस्त से आरंभ थी। तीसरे दिन बुधवार की शाम परिणाम आया।

आइआइसीसी के कुल पड़े 1,662 मतों में से सलमान खुर्शीद को 721 मत मिले। वहीं, मो.फुरकान कुरैशी 362 वोट से उपाध्यक्ष चुने गए हैं। खुर्शीद का पैनल विजयी रहा।

मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद लव जिहाद में युवती को फंसाने पर केस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

मेडिकल की पढ़ाई कर विदेश से लौटी थी युवती, पहले उसे साजिश के तहत जलाया, फिर खुद के मतांतरण का नाटक कर की शादी, बेटा हुआ तो आरोपित ने नाम रखा अली

मेडिकल की पढ़ाई कर विदेश से भारत लौटी एक युवती को नोएडा में साजिश के तहत उसके संपर्क में आए मुस्लिम युवक ने जलाया, जिससे कि उससे कोई दूसरा व्यक्ति शादी न कर सके। इसके बाद खुद का मतांतरण करने का ढोंग कर आरोपित ने उससे शादी कर ली गई। मतांतरण के फर्जीवाड़े की पोल उस वक्त खुली जब युवती ने पुत्र को जन्म दिया और आरोपित ने इस्लामिक मान्यता के तहत सुन्नत कराकर अली नाम रख दिया। युवती की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाल ही में शिकायत की तो कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह मूलतः ओडिशा के भुवनेश्वर की रहने वाली हैं। वर्ष 2016 में उनकी बेटी विदेश से पढ़ाई कर नोएडा में उनके साथ रहने आई। आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग और प्राइवेट जाब भी करने ली। इस दौरान उसके संपर्क में शाहजहांपुर का रहने वाला अब्दुर्र रहमान आ गया, जो उसको लव जिहाद में फंसाना चाहता था। वह नहीं फंसी तो 17 नवंबर 2017 को उसको नोएडा सेक्टर- 71 में जब युवती अकेली थी, तब आरोपित ने उसे जला दिया। वह 28 प्रतिशत तक जल गई। इस मामले में नोएडा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2018 में युवती को लेकर आरोपित गाजियाबाद आ गया और उसको धोखा देने की नीयत से अपना मतांतरण करने का ढोंग कर आर्य समाज मंदिर के पुजारी और हिंदू महासभा के पदाधिकारी के साथ षड्यंत्र करकर एक ही दिन मे अपना मतांतरण कर शादी की और शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इसकी जानकारी युवती के माता-पिता को नहीं दी। मामले की जानकारी होने पर इस मामले में गाजियाबाद पुलिस से युवती के स्वजन ने शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने निष्पक्ष विवेचना करने के बजाय केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी।

युवती ने वर्ष 2021 में पुत्र को जन्म दिया तो आरोपित ने इस्लाम के तहत सुन्नत कराकर उसका नाम अली रख दिया। वर्तमान में युवती और बच्चे को लेकर वह मेरठ में रहता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी किसी और से शादी न कर सके, इसलिए पहले उसको जलाया गया फिर मतांतरण का नाटक कर उससे शादी की। आरोपित मतांतरण के बाद भी मुस्लिम मान्यताओं में विश्वास करता है और उसने बेटी का जीवन नर्क बना दिया है। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तब युवती के स्वजन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बेटी को लव जिहाद के चंगुल से बाहर निकलवाने और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

बांसुरी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भ्रष्ट आचरण के आधार पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देने वाली आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बांसुरी स्वराज से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने स्वराज को नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह कहते हुए मामले की पक्षकार सूची से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का नाम हटा दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया है। भारती ने याचिका में कहा है कि आनंद ने 2024 का लोस चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे।

पिछली सुनवाई पर अदालत ने याचिका में की गई गलतियों को संशोधित कर दोबारा दायर करने को कहा था। भारती ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान स्वराज व उनके चुनाव एजेंट की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाया गया है।

विधायक निधि पर उप राज्यपाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

विधायक निधि का उपयोग नहीं होने पर कांग्रेस नेता ने लगाए थे आरोप

एलजी वीके सक्सेना ने विधायक निधि पर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने एलजी से मुलाकात कर विधायक निधि का उपयोग नहीं होने को लेकर आरोप लगाए थे। इस पर कार्यवाही करते हुए एलजी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

एलजी की विशेष सचिव हरलीन कौर की ओर से लिखे गए पत्र में अभिषेक दत्त के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि दत्त की ओर से एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को लेकर चिंता जाहिर की गई है। शहर के लिए जरूरी सीवेज ड्रेन और जलापूर्ति पाइपलाइन आदि पर इन्हें खर्च नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इसे देखते हुए इस फंड को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

रिपोर्ट में इस बात की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि विधायक निधि किन योजनाओं पर खर्च की गई है। उन योजनाओं का उद्देश्य, जरूरत मापदंड और दिशानिर्देश क्या रहे। जिन परियोजनाओं में फंड को लगाया गया है, वे कौन-कौन सी हैं और उन पर अभी तक क्या प्रगति हुई है। इसके साथ-साथ विधायक निधि से होने वाले खर्च की निगरानी का क्या तंत्र निर्धारित किया गया है और अभी तक हुए काम पर इसकी क्या रिपोर्ट है। इन सभी मुद्दों पर पांच दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

वीके सक्सेना। फाइल

दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए एलजी आफिस हर चाल चल रहा-आप

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि एलजी एमएलए फंड की जांच कराके और सार्वजनिक कार्यों को रोककर दिल्ली के विकास को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आप ने कहा है कि एलजी के कार्यालय द्वारा दिल्ली राज्य में सभी विकास कार्यों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप ने दावा किया कि दिल्ली में बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याएं पैदा करने के लिए पहले दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के धन का उपयोग रोककर उसे पंगु बना दिया गया। भले ही पानी और सीवर कार्यों के लिए डीजेबी को 4,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन एलजी के पसंदीदा अधिकारियों द्वारा जटिलताएं पैदा की गईं।

दिल्ली हाई कोर्ट

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में तीन वर्षों से जेल में बंद युवक को मिली जमानत, युवक के मुस्लिम मत अपनाने से इन्कार पर पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

जेल में अपराधी बनकर बाहर आने की संभावना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित युवक को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जमानत देते हुए कहा कि नाबालिग किशोरी से प्यार करने वाले युवा लड़कों से जुड़े मामलों में कानून के दुरुपयोग पर ध्यान देना होगा। अदालत ने दर्ज किया कि रिश्ते से स्वजन की आपत्ति के कारण युवक जेलों में बंद हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के भविष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यदि वह जेल में रहता है तो उसके एक खूंखार अपराधी के रूप में बाहर आने की संभावना बहुत अधिक है। मामले में किशोरी की मां ने प्राथमिकी इसलिए कराई थी क्योंकि याचिकाकर्ता युवक ने मुस्लिम मत अपनाने से इन्कार कर दिया था।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने नोट किया घटना के समय पीड़िता लगभग 17 वर्ष की थी और याचिकाकर्ता आरोपित लगभग 21 वर्ष का था। पीठ ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 20 वर्ष से कुछ बड़े लड़कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाए जाते हैं, जबकि एक नाबालिग लड़की द्वारा दी गई सहमति कानून की नजर में वैध सहमति नहीं है। इस कारण यह परेशानी सामने आती है।

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में लड़की की मां ने अपनी बेटी के संबंध में गुमशुदमी दर्ज कराई थी, जो कि याचिकाकर्ता के साथ रह रही थी। शिकायतकर्ता ने शुरू में कहा कि वह स्वेच्छा से अपने प्रेमी (याचिकाकर्ता) के साथ गई थी और उससे शादी की। इससे वह गर्भवती भी हुई लेकिन बाद में अपने रुख से मुकर गई। इस कारण युवक के जेल की हवा खानी पड़ी।

पीठ ने कहा कि यह मामला एक प्रेम प्रसंग का है और अदालत इस पर सवाल पर नहीं जा रही है कि याचिकाकर्ता ने पाक्सो के तहत अपराध किया है या नहीं।

अभी अदालत केवल इस बात को लेकर चिंतित है कि पिछले तीन वर्षों से जेल में बंद एक युवा को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, जबकि पीड़िता ने अपना बयान बदल लिया है। उसका मानना है कि किशोरी अदालत ने आगे कहा कि पहले भी याचिकाकर्ता दो बार अपने घर से भाग चुकी थी और डाक्टरों को दिए गए उसके बयान के अनुसार उसकी मां को इस रिश्ते के बारे में पता था। इस कारण उसके रिश्ते में परेशानी सामने आई। बाद में युवक को जेल हुई।

****

तलाक देने से पति-पत्नी व परिवार पर नहीं लग सकता कलंक : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, जागरण. नई दिल्ली: तलाक की अपील याचिका को मंजूर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि तलाक देने से पति-पत्नी या उनके परिवार का न तो अपमान होता है और न ही इससे कलंक लग सकता है।

तलाक देने से परिवार पर कलंक लगने के पति के तर्क को ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष शिक्षित हैं और यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि तलाक देने से उन पर या उनके परिवार पर कलंक लगेगा। न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष 10 साल से अलग रह रहे हैं और रिश्ते में सुधार की कोई संभावना नहीं है। शादी को जारी रखने से दोनों पक्षों को तकलीफ होगी और यह मानसिक क्रूरता बढ़ाएगी। ऐसे में अपीलकर्ता महिला और प्रतिवादी को तलाक मंजूर किया जाता है।

जिस किशोरी को मृत मान चुका था परिवार, पुलिस को वह जिंदा मिली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विजय विहार थाना पुलिस ने किशोरी को पंचकूला से किया बरामद

माता-पिता ने जिस बेटी को मृत समझकर अंतिम श्रद्धांजलि दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने उस किशोरी को हरियाणा के पंचकूला से जिंदा बरामद कर उनके परिवार को सौंप दिया। 16 वर्षीय इस किशोरी के माता-पिता की शिकायत पर विजय विहार थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने किशोरी के एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि किशोरी व आरोपित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई। जिसके बाद आरोपित किशोरी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बीते 18 जुलाई को किशोरी के लापता होने की सूचना मिली थी। पुलिस जांच कर ही रही थी कि केस में एक नया मोड़ आ गया।

फोटो व कपड़े देख माता-पिता ने की थी शव की शिनाख्त : इस बीच नौ अगस्त को उप्र के संभल जिला स्थित थाना राजपुरा से थाना विजय विहार को एक सूचना मिली कि उनके अधिकार क्षेत्र में एक किशोरी का अज्ञात शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके हाथ व पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जो विजय विहार थाना क्षेत्र से लापता किशोरी से मिलता जुलता है। जिसके बाद 10 अगस्त को थाना विजय विहार की एक टीम पीड़ित परिवार के साथ राजपुरा पहुंची, जहां संभल पुलिस ने परिवार को बताया कि 27 जुलाई को एक किशोरी का उन्हें शव मिला था।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में राजनीतिक लोकतंत्र की प्रगति पर दिया जोर, कहा–

समावेशी साधन के रूप में आरक्षण जरूरी : राष्ट्रपति

आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव नहीं होने का दिया साफ संदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्र को संबोधित किया। एएनआइ

राष्ट्रपति ने यह भी कहा

- पिछले एक दशक में भारत ने खेलों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे एथलीटों ने वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उनकी हालिया उपलब्धियां भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी।
- न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों पर दृढ़ रहकर हम यह सुनिश्चित करने के मिशन से आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विश्व मंच पर अपना गौरवपूर्ण स्थान पुनः प्राप्त करे।
- युवा मन को विकसित करना और नई मानसिकता बनाना जो पारंपरिक व समकालीन ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करे, हमारी प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहले ही परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किए जाने की मजबूत पैरोकारी करते हुए साफ कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र की निरंतर प्रगति के लिए समावेशी साधन के रूप में सकारात्मक पहल (अफरमेटिव एक्शन) को मजबूत किया जाना चाहिए। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने संविधान निर्माता बाबासाहेब आंबेडकर के कथन 'राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो' का जिक्र कर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के छेड़छाड़ की गुंजाइश का रास्ता बंद करने का स्पष्ट संदेश दिया।

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और इसमें उपवर्गीकरण यानि कोटे के भीतर कोटा पर राज्यों को गौर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में राष्ट्रपति की यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। आंबेडकर के कथन का सहारा लेकर द्रौपदी मुर्मु ने वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रभावी बनाने के सरकार के इरादों पर मुहर लगा दी। राष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र की निरंतर प्रगति से सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में की गई प्रगति की पुष्टि होती है। समावेशी भावना, हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। समावेश के साधन के रूप में, अफरमेटिव एक्शन को मजबूत किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि संविधान में आरक्षण शब्द का सीधे जिक्र नहीं है और इसे अफरमेटिव एक्शन ही कहा गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में कथित सामाजिक स्तरों के आधार पर कलह को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों को खारिज करना होगा। उन्होंने एससी-एसटी वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हाल में हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ वोटरों के ऐतिहासिक कीर्तिमान का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस सबसे बड़े चुनाव के सुचारू और त्रुटिरहित संचालन के लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना वस्तुतः लोकतंत्र की विचारधारा का प्रबल समर्थन है और इससे पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों को ताकत मिलती है। राष्ट्रपति ने 2021 से 2024 के बीच आठ प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर हम काफी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है ताकि लोगों को पुनः गरीबी में जाने से रोका जा सके। अन्नदाता किसानों ने उम्मीदों से बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया है। हाल के वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा मिला है। सड़कों और राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों का जाल बिछाने में मदद की है। इन सभी बदलावों ने अगले दौर के आर्थिक सुधारों और आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार कर दिया है जहां से भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी समेत देश के प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण करते हुए नागरिकों से जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए जीवनशैली में प्रभावी बदलाव कर योगदान देने का अनुरोध किया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने को औपनिवेशिक युग के एक और अवशेष को हटाने के रूप में चित्रित किया। महिला सशक्तीकरण को महत्व देने की सरकार की पहल से हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि इससे न केवल श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़ी है, बल्कि जन्म के समय बेटियों के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की नागिरकों, सैनिकों, पुलिसकर्मियों आदि को बधाई देते हुए एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने को उचित ठहराते हुए कहा कि हम आज उस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी को याद कर उन परिवारों के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं जो विभाजन के समय छिन्न-भिन्न कर दिए गए थे।

प्रधानमंत्री मोदी के 'हर घर तिरंगा' अभियान ने महिलाओं के लिए खोली नई राह

हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को पुंछ में निकाली गई रैली। प्रेट्र

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान महिलाओं के लिए एक सफल घरेलू उद्योग बन गया है। देशभर में हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। उक्त बातें इस अभियान का समन्वय करने वाले संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहीं। गोविंद मोहन ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान साल 2022 में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के मौके पर शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी पहल थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। उनके संबोधनों से प्रेरित होकर लोगों ने दफ्तरों, स्कूलों, कालेजों के साथ साथ अपने-अपने घरों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संकल्प लिया है।

खास बात ये कि इस पहल ने जमीनी स्तर पर महिलाओं द्वारा संचालित एक नए उद्योग को जन्म दे दिया है। इसका व्यापक असर हुआ। बड़े बिजनेस ग्रुप पर तिरंगा झंडे के निर्माण की निर्भरता कम हो गई। आज स्व-सहायता समूह राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता बन गए हैं। गोविंद मोहन बताते हैं महिला स्वयं सहायता समूहों ने तेजी से ध्वज उत्पादन का काम अपने हाथ में ले लिया। इससे केंद्र सरकार की ओर से आपूर्ति किए जाने वाले राष्ट्रीय झंडों की मांग कम होकर करीब 2.5 करोड़ रह गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल निकला। उत्तर प्रदेश ने 2022 में सरकार से 4.5 करोड़ झंडे खरीदे थे लेकिन स्वयं सहायता समूहों की आत्मनिर्भरता के चलते 2023 में कोई खरीदारी नहीं की।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की इस पहल का व्यापक सकारात्मक परिणाम भविष्य के लिए भी अच्छे संकेत हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया
- देशभर में हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए

मणिपुर में 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हजारों युवाओं ने बुधवार को इंफाल से मोइरांग तक 40 किलोमीटर लंबी बाइक रैली में हिस्सा लिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर पुलिस और खेल विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग चार हजार युवाओं ने भाग लिया। वहीं, सीआरपीएफ ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत शिलांग में 'तिरंगा यात्रा' का आयोजन किया।

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में भाजपा की तिरंगा रैली को दी मंजूरी

मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य में भाजपा की 'तिरंगा रैली' को मंजूरी दी और साथ ही तमिलनाडु सरकार को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर मोटरसाइकिल तथा साइकिल से रैली निकालने अथवा पैदल मार्च करने जैसी किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन के लिए कई शर्तें भी रखीं जिनमें राष्ट्रीय ध्वज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना भी शामिल है।

माफिया अतीक के बेटे को ढेर करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पदक

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

- उप्र पुलिस के 17 कर्मियों को आज राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपित व माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मुहम्मद गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराने वाली एसटीएफ की टीम में शामिल दो पुलिस उपाधीक्षकों समेत छह पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय व राज्य बलों के लिए 1037 पुलिस पदकों की घोषणा की गई है।

स्वतंत्रता दिवस पर इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल 17 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक मिलेगा, इनमें तीन अन्य मुठभेड़ में कुख्यातों को मार गिराने वाले 11 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। एडीजी एसके भगत समेत चार पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा तथा 70 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक दिया जाएगा।

प्रयागराज में 24 फरवरी, 2023 को माफिया अतीक अहमद के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के गवाह उमेश पाल उर्फ कृष्ण कुमार पाल व उनकी सुरक्षा में तैनात दो गनर की दिनदहाड़े हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस दुस्साहसिक वारदात में शामिल फरार आरोपितों की तलाश में एसटीएफ को भी लगाया गया था। एसटीएफ ने 13 अप्रैल, 2023 को झांसी में पारीक्षा बांध के पास हुई मुठभेड़ में असद व गुलाम को मार गिराया था।

बिकरू कांड के आरोपित को ढेर करने वालों को भी वीरता पदक : कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के आरोपित को ढेर करने वालों को भी वीरता पदक दिया जाएगा। बिकरू कांड में शामिल रहे विकास दुबे गिरोह का प्रवीण दुबे उर्फ बउवा नौ जुलाई, 2020 को इटावा में स्विफ्ट डिजायर कार लूटकर भाग रहा था। थाना सिविल लाइन के तत्कालीन प्रभारी उपनिरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह व आरक्षी विपिन कुमार ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया था। बउवा बिकरू गांव में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला बोलने वालों में शामिल था। इस हमले में सीओ समेत आठ पुलिसकर्मी बलिदान हो गए थे।

असम में पहली बार सीएए के तहत बांग्लादेशी को मिली नागरिकता

गुवाहाटी, प्रेट्र : बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच असम के सिलचर के 50 वर्षीय दुलोन दास असम में सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेश के पहले प्रवासी बन गए हैं। भारत के गृह मंत्रालय ने दुलोन दास को मंगलवार को नागरिकता मिलने की सूचना दी है। सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें गुवाहाटी में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाने के लिए कहा गया है।

दुलोन दास के वकीलों के अनुसार, उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की मदद से एक अप्रैल 2024 को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। दुलोन का जन्म 1974 में बांग्लादेश के सिलहट जिले में हुआ था और उनके परिवार ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से त्रस्त होकर 1988 में असम में शरण ले ली थी। वकीलों ने मंगलवार को मीडिया को बताया '1986 में दास के पिता ने बांग्लादेश के सिलहट जिले के एक गांव में आठ हजार टका (बांग्लादेश की मुद्रा) खर्च करके जमीन खरीदी थी लेकिन उसके तुरंत बाद उन पर कई हमले हुए और वे देश छोड़कर चले आए।'

प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराएंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस अवसर पर अपने संबोधन में वह अपनी सरकार का एजेंडा रखते हैं, रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। इसके साथ ही देश के सामने ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात भी करते हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर अपने तीसरे कार्यकाल के पहले संबोधन में वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ देंगे। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 के दौरान लाल किले की प्राचीर से 10 बार तिरंगा फहराया था। इस मामले में मोदी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। नेहरू को यह सम्मान 17 और इंदिरा गांधी को 16 बार मिला था। विकसित भारत का विषय उनके संबोधन में प्रमुखता से छाया रह सकता है। माना जा रहा है कि वह अपने संबोधन में बांग्लादेश में संकट की स्थिति, विशेष रूप से अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का उल्लेख भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता कि कई हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है और उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाओं का विरोध सड़क पर उतर कर किया है। मोदी इस बात पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में शुरू किए गए सुधारों, विकास कार्यक्रमों ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। संबोधन में इस बात पर भी रहेगी कि क्या वह किसी नई पहल की घोषणा करते हैं या लागू कल्याणकारी कार्यक्रमों के दायरे का क्या विस्तार करते हैं।

- लालकिले की प्राचीर से संबोधन में देते हैं अपनी सरकार के एजेंडा का संकेत

नरेन्द्र मोदी। फाइल

नीट-एसएस नहीं कराने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस साल नीट-सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) आयोजित नहीं करने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि परीक्षा स्थगित करना पूरी तरह न्यायसंगत था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि एनएमसी को नीट-एसएस के कार्यक्रम पर जल्द फैसला लेना चाहिए, जो अगले साल की शुरुआत में आयोजित की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कार्यक्रम की घोषणा आज से 30 दिनों के भीतर की जाएगी। एनएमसी की इस दलील से पीठ सहमत थी कि हर साल नीट-एसएस में शामिल होने वाले लगभग 40 प्रतिशत परीक्षार्थी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के वर्तमान बैचों से संबंधित होते हैं। एनएमसी के वकील ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम, जो कोरोना के कारण 2021 के बजाय 2022 में शुरू हुए थे, जनवरी 2025 में समाप्त होंगे। यदि इस वर्ष नीट-एसएस आयोजित किया जाता है तो उस बैच के छात्र इस परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे।

वरिष्ठ आइएएस अधिकारी गोविंद मोहन बनाए गए नए गृह सचिव

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को नया गृह सचिव बनाया है। वह मौजूदा गृह सचिव अजय भल्ला की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। बुधवार को सरकार ने आदेश जारी कर दिया। नए केंद्रीय गृह सचिव 1989 सिक्किम कैडर के आइएएस अधिकारी हैं। आइआइटी बीएचयू से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर चुके मोहन अक्टूबर 2021 से संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर तैनात हैं। वह मूलत उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।

राहुल नवीन नियुक्त किए गए ईडी का निदेशक : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन को बुधवार को जांच एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी नवीन की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए है। पिछले साल 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म होने के बाद नवीन को ईडी का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया था।

गोविंद मोहन। फाइल

राजनयिक पी हरीश होंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक पार्वथनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र (न्यूयार्क) में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वह जून में सेवानिवृत्त हुईं राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज की जगह लेंगे। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) अधिकारी हरीश वर्तमान में जर्मनी में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पी हरीश के जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

सुप्रीम फैसले से खनन उद्योग पर पड़ सकता है दो लाख करोड़ तक का बोझ

नई दिल्ली, प्रेट्र : खनन रायल्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय खनन उद्योग पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा क्योंकि खनन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि टैक्स का बकाया 1.5 से दो लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि ने कहा कि पूर्व प्रभाव से कराधान की काली छाया भारत पर एक बार फिर से मंडरा रही है। उन्होंने कहा कि कानूनों को व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य द्वारा भी संपत्ति के अधिग्रहण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना चाहिए। खान मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फैसले का खनन, इस्पात, बिजली और कोयला कंपनियों पर बहुत बड़ा वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के निवेश पर भी असर पड़ेगा। भारतीय खनिज उद्योग संघ के अतिरिक्त महासचिव बीके भाटिया ने कहा कि खनन क्षेत्र पहले ही दुनिया में करों की सबसे अधिक दरों से परेशान है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विभिन्न कर और शुल्क लगाने के राज्यों को असीमित अधिकार दे दिए हैं।

राज्यों के कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ करेगी सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इन कानूनों से राज्यों को मिला था खनन पर कर लगाने का अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले के कारण स्थगित हो गए थे राज्यों के कानून

सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को राज्यों को खनन भूमि और खनिज अधिकार पर लगाए गए कर का बकाया वसूलने की सशर्त इजाजत दे दी। लेकिन अभी भी विभिन्न राज्यों के कर कानूनों की वैधानिकता का मुद्दा कोर्ट में लंबित है जिस पर नियमित पीठ सुनवाई करेगी। संविधान पीठ ने कानूनी प्रश्न तय करते हुए कहा कि विभिन्न मामलों को जल्द ही नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगाया जाएगा।

राज्यों के खनिज खनन पर कर लगाने वाले कानूनों की वैधानिकता का मुद्दा झारखंड और ओडिशा की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने उठाया। द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट को राज्य कानूनों की वैधानिकता भी तय करनी चाहिए। इस फैसले के बाद उन कानूनों को रिवाइव होना चाहिए क्योंकि राज्य कानून के आधार पर ही कर वसूल सकते हैं। लेकिन विभिन्न कंपनियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि अभी तुरंत यह मुद्दा तय नहीं हो सकता, उसमें कई और पहलू शामिल हैं। इस पर द्विवेदी ने कानूनों की वैधानिकता के मामलों को जल्द सुनवाई पर लगाने की मांग की। संविधान पीठ की अगुआई कर रहे प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बाकी मामलों को जल्द ही नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाया जाएगा।

कोर्ट का बुधवार का जो फैसला आया है, उससे राज्यों के लिए तो राजस्व के रास्ते खुलते हैं, लेकिन बकाया वसूलने का अधिकार दिए जाने से खनन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर भारी आर्थिक भार आएगा। इसका उदाहरण इसी से जाना जा सकता है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई के फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू करने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उस पर विभिन्न राज्यों की करीब 3,000 करोड़ की डिमांड पुनर्जीवित हो जाएगी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को इंडिया सीमेंट के 1989 के जिस फैसले को रद किया था, वह फैसला करीब 35 वर्ष लागू रहा और विभिन्न राज्यों के खनन पर कर लगाने के कानून इंडिया सीमेंट के फैसले में तय व्यवस्था के आधार पर स्थगित हो गए थे। केसोराम इंडस्ट्री मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने बंगाल के कानून को सही ठहराया था। यह फैसला 2004 का था, जिसे गत 25 जुलाई के फैसले में नौ जजों की पीठ ने बहुमत से सही ठहराया था। केसोराम के फैसले के बाद कई राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने भी कानून बनाए जिन्हें हाई कोर्ट ने सही भी ठहराया। द्विवेदी बताते हैं कि झारखंड का कानून हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सभी मामले यहां हैं। विभिन्न राज्यों के कानूनों की वैधानिकता का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसे तय होना है।

भारत में रामसर साइट की सूची में शामिल हुए तीन नए वेटलैंड

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तीन नए रामसर स्थलों (साइट) की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से देश में रामसर साइट की कुल संख्या 85 हो गई है। ये तीन नए स्थल हैं तमिलनाडु के नांजारायन पक्षी अभयारण्य और काझुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। इन स्थलों को जोड़ने से भारत की समृद्ध जैवविविधता और आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रयासों को एक और नई ऊंचाई मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह बताते हुए रोमांचित हूं कि हमने अपने नेटवर्क में तीन रामसर साइटों को जोड़ा है। अब हमारे देश में रामसर साइट की संख्या को 85 हो गई है। यह क्षेत्र 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। यह उपलब्धि पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर दिए गए जोर को दर्शाती है। उन्होंने हमारे आर्द्रभूमियों को 'अमृत धरोहर' कहा है और उनकी संरक्षण के लिए निरंतर कार्य किया है। रामसर साइट का एलान रामसर कन्वेंशन के तहत किया जाता है। यह एक अंतर-सरकारी संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

- देश में रामसर साइट की कुल संख्या 85 हो गई, दो तमिलनाडु और एक मप्र का वेटलैंड शामिल

भूपेंद्र यादव। फाइल

सुप्रीम कोर्ट ने बांसुरी सहित 39 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बांसुरी स्वराज सहित 39 वकीलों और एडवोकेट आन रिकार्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया। पूर्ण अदालत की एक बैठक में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने 14 अगस्त 2024 से उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया, जिनमें से 10 महिलाएं हैं।

बांसुरी स्वराज के अलावा, नलिन कोहली, अभिमन्यु भंडारी, अनिंदिता पुजारी, शादान फरासत, अपर्णा भट्ट, परमेश्वर के, ऋषि मल्होत्रा, अशोक पाणिग्रही, गौरव शर्मा उन वकीलों में शामिल हैं, जिन्हें वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, केवल एडवोकेट आन रिकार्ड के रूप में नामित वकील ही सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर कर सकते हैं।

आसियान देशों के 50 छात्रों को प्रतिवर्ष मिलेगी फेलोशिप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लांच की आसियान-भारत फेलोशिप

भारत एवं आसियान देशों के बीच कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए परस्पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके लिए भारत ने पहल करते हुए आशियान देशों के 50 छात्रों को कृषि से जुड़े क्षेत्रों में मास्टर डिग्री के लिए प्रतिवर्ष फेलोशिप देने की घोषणा की है। इसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से शुरू किया जा रहा है। परियोजना पांच साल के लिए है। फेलोशिप की शुरुआत दिल्ली स्थित पूसा में गुरुवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस दौरान कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर व भागीरथ चौधरी समेत आसियान देशों के उच्चायुक्त भी मौजूद थे। आसियान भारत की दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की नीति एवं इस पर निर्मित 'इंडो-पैसिफिक विजन' की आधारशिला है। भारत आसियान एकता का समर्थन करता है।

योजना के लिए केंद्र सरकार ने आसियान-भारत कोष के तहत वित्त पोषण की मंजूरी पहले ही दे दी है। चयनित छात्रों को फेलोशिप, प्रवेश शुल्क, रहने का खर्च एवं आकस्मिकता खर्च दिया जाएगा। इसके तहत भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले मास्टर्स प्रोग्राम छात्रों को अत्याधुनिक शोध से परिचित कराएंगे। उन्हें भविष्य के नवाचारों के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही दीर्घकालिक डिग्री कोर्स शोधकर्ताओं को लंबे समय तक जुड़े रहने में मदद कर सकता है। आसियान तथा भारत को कृषि से संबंधित मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है।

****

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं पंजाब में। कांग्रेस के चार विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर रंधावा, डा. राजकुमार चब्बेवाल व आप के पूर्व कैबिनेट मंत्री मीत हेयर लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 अगस्त, 2024

ऐलनाबाद से चुनाव लड़ चुके गोबिंद कांडा भाई की पार्टी हलोपा से बेटे को मैदान में उतारेंगे

खुद के लिए भाजपा से रानियां, ऐलनाबाद व फतेहाबाद से मांग रहे टिकट, सिरसा से गोपाल की तैयारी

विधानसभा चुनाव से पहले दबाव की राजनीति करना चाहते हैं दोनों भाई

जागरण संवाददाता सिरसा

गोपाल कांडा। फाइल

गोविंद कांडा। फाइल

'पार्टी ऐलनाबाद, रानियां व फतेहाबाद से मैदान में उतार सकती है'

वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने कहा कि भाजपा जहां से भी उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ऐलनाबाद, रानियां या फतेहाबाद से चुनाव मैदान में उतार सकती है। रानियां से हलोपा के टिकट पर धवल कांडा चुनाव लडेंगे। हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा 18 अगस्त को रानियां अनाज मंडी में हलोपा कार्यालय का उदघाटन करने के साथ-साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। जबकि सुबह वे कालांवाली में कार्यालय का शुभारंभ करेंगे।

हरियाणा में भाजपा की सहयोगी एक विधायक वाली हरियाणा लोकहित पार्टी (हलोपा) ने रानियां से धवल कांडा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। धवल कांडा भाजपा नेता गोबिंद कांडा के पुत्र हैं। गोबिंद कांडा भाजपा की टिकट पर ऐलनाबाद उपचुनाव लड़ चुके हैं। जबकि उनके भाई और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हरियाणा की भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं।

रोचक बात है कि भाजपा में होते हुए गोबिंद कांडा अपने भाई की पार्टी हलोपा के उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और जबकि उस विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा बिजली मंत्री रणजीत सिंह विधायक थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होकर विधायक पद से इस्तीफा दिया। दूसरी ओर गोबिंद कांडा ने पार्टी बर्कर मीटिंग में भी ये बात कही कि पार्टी उन्हें ऐलनाबाद, रानियां या फतेहाबाद से चुनाव मैदान में उतार सकती है।

सीएम ने मिलकर साथ चलने की कही थी बात : हलोपा नेता आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा गठबंधन के साथ पांच सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक संदेश नहीं गया। बीते दिनों सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा में आए तो विधायक गोपाल कांडा के महल में गए। तब मीडिया से बातचीत में सीएम ने गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात को घुमा दिया और कहा कि हम मिलकर चले गए। जबकि भाजपा नेता गोबिंद कांडा फतेहाबाद से भी चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। वहां पर वे कई दौरे कर चुके हैं। फतेहाबाद से मौजूदा समय से भाजपा के विधायक दूड़ाराम बिश्नोई हैं। गोबिंद कांडा ऐलनाबाद से भी दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पर मौनू बैनीवाल भी मजबूत दावेदार हैं।

2009 में कांग्रेस को समर्थन देकर बने थे गृह मंत्री : हलोपा की स्थापना गोपाल कांडा ने 2014 में की थी। गोपाल कांडा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत 2009 के विधानसभा चुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर शुरू की थी। तब उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्मण दास अरोड़ा को हराया था। इसके बाद वे कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री बने। लेकिन एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड कांड की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और जेल जाना पड़ा। जेल से जमानत पर आने के बाद 2014 में बाहर तो आ गए, लेकिन गोपाल कांडा सिरसा से और गोबिंद कांडा रानियां से हार गए। गोबिंद कांडा 2019 का विधानसभा चुनाव हलोपा की टिकट पर दोबारा रानियां से लड़े और फिर हार गए। 2021 में ऐलनाबाद उपचुनाव हुआ, जिसमें गोबिंद कांडा ने भाजपा ज्वाइन की और पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए।

2027 में भाजपा 50 से अधिक विस सीटें जीती तो राजनीति छोड़ दूंगा: अवधेश

जासं, अयोध्या : उत्तर प्रदेश की फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का एक बयान राजनीति के गरियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। अयोध्या में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा 50 से अधिक सीटें जीतती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उनके सांसद बनने से रिक्त हुई विधानसभा सीट मिल्कीपुर से उपचुनाव में उनके पुत्र अजीत प्रसाद को सपा के टिकट पर लड़ने की चर्चा है।

अवधेश प्रसाद।

मिल्कीपुर सीट पर सपा को पटखनी देकर पार्टी उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभालने से यह सीट प्रदेश के उपचुनाव वाली 10 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही वजह है कि 15 दिन में तीसरी बार मुख्यमंत्री 18 अगस्त को नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में हिस्सा लेने आ रहे हैं, लेकिन वह जीत को लेकर आशंकित नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी का बेजा दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिए सत्ता पक्ष करेगा, लेकिन सपा की ही जीत होगी।

राज्यसभा उपचुनाव

कांग्रेस ने सिंघवी को बनाया तेलंगाना से अपना उम्मीदवार

नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस ने तेलंगाना में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तेलंगाना से राज्यसभा के लिए आगामी उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। घोषणा के बाद सिंघवी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में वरिष् वकील और कांग्रेस के वरिष् नेता सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से पार्टी ने मैदान में उतारा था। हालांकि, कुछ असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रास-वोटिंग के कारण सिंघवी भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन से चुनाव हार गए थे। तेलंगाना समेत नौ राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए तीन सितंबर को चुनाव होंगे।

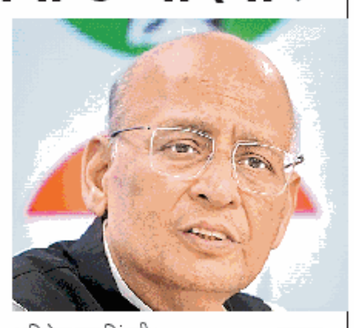
अभिषेक मनु सिंघवी। फाइल

हरियाणा में किसी राजनीतिक दल ने प्रत्याशी का नहीं किया फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

21 अगस्त तक नामांकन पत्र हो सकेंगे जमा लेकिन मतदान की गुंजाइश कम, भाजपा का वर्चस्व

हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। 21 अगस्त तक नामांकन-पत्र जमा हो सकेंगे। पहले दिन कोई आवेदन जमा नहीं हुआ। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशी का फैसला नहीं किया है। नामांकन-पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी और 27 अगस्त को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। अगर जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान होगा।

हरियाणा में उपचुनाव के लिए मतदान की नौबत आने की कम ही गुंजाइश है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले प्रमुख विपक्षी दल-कांग्रेस अपना उम्मीदवार देने की हिम्मत नहीं जुटाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास उपचुनाव के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है। नब्बे सदस्यों वाली विधानसभा में वर्तमान में 87 विधायक हैं। रानियां से निर्दलीय विधायक रहे रणजीत सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। मुलाना से कांग्रेस विधायक रहे वरुण चौधरी ने अंबाला पार्लियामेंट से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन के बाद से यह सीट भी रिक्त है। तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने अभी तक विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी हैं। तकनीकी रूप से और विधानसभा रिकार्ड के हिसाब से वे कांग्रेस की ही विधायक हैं। भाजपा के पास खुद के 41 विधायक हैं। जजपा के दो विधायकों – रामनिवास सुरजाखेड़ा व जोगीराम सिहाग का सरकार को खुला समर्थन है। सिरसा से हलोपा विधायक गोपाल कांडा व पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा के पास 45 विधायकों का आंकड़ा है। भाजपा में शामिल हो चुकी तोशाम से कांग्रेस विधायक को मतदान करना ही पड़ा तो, वह भाजपा को देंगी। कांग्रेस के पास 28 विधायक हैं। संख्याबल नहीं होने से कांग्रेस खुद को चुनाव से दूर कर चुकी है।

एससी-एसटी आरक्षण में होनी ही चाहिए क्रीमी लेयर : संजय निषाद

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

बोले, वोट बैंक घटने की आशंका में फैसले का विरोध कर रहे हैं कई दल

संजय निषाद। फाइल

विस उपचुनाव में मझवां और कटेहरी सीट पर खुद प्रत्याशी उतारेगी निषाद पार्टी

एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मत्स्य विकास मंत्री डा. संजय निषाद एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने साफ कहा है कि एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर होनी ही चाहिए। वोट कम होने के डर से कई बड़े दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। संजय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गरीबों को आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में है तो इसमें गलत क्या है? ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

मीडिया से बातचीत में संजय ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से निर्बल के साथ रही है, पार्टी का तो नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 'निषाद पार्टी' है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी उन्होंने अपना रुख साफ किया। संजय ने कहा, मझवां और कटेहरी सीट पर निषाद पार्टी अपने चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेगी। बोले कि एनडीए के सहयोगी होने के नाते हम भाजपा के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। मझवा और कटेहरी में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। इन सीटों को लेकर भाजपा के साथ बातचीत चल रही है।

संजय निषाद ने 16 अगस्त को आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर भी मीडिया से चर्चा की। कहा, स्थापना दिवस पर आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। बीते कुछ वर्षों में पार्टी ने क्या हासिल किया और कहां कमियां रह गईं, उसे कैसे दूर किया जाए। इन मुद्दों पर पदाधिकारियों से बातचीत होगी। सक्रिय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।

त्रिपुरा पंचायत चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी, 97 प्रतिशत सीटें जीतीं

अगरतला, प्रेट्र : त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 97 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 71 प्रतिशत सीटें निर्विरोध जीतीं। अन्य 29 प्रतिशत सीटों के लिए मतदान आठ अगस्त को हुआ था और मतगणना मंगलवार को हुई।

एक अधिकारी के अनुसार, पार्टी ने 606 में से 584 ग्राम पंचायतें, 35 पंचायत समितियों में से 34 और आठ जिला परिषदों में से आठ में जीत हासिल की। भाजपा ने जून में पूर्वोत्तर राज्य की दोनों लोकसभा सीटें जीती थीं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त आसित कुमार दास ने बताया कि आठ जिला परिषदों की 96 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 93 सीट जीतीं, जबकि कांग्रेस और माकपा क्रमशः दो और एक सीट पर विजयी रहीं।

पंचायत समितियों के संदर्भ में भाजपा ने कुल 188 सीट में से 173 जीतीं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस ने क्रमशः छह और आठ सीट जीतीं।

भाजपा ने पंचायत चुनाव में उस पर फिर भरोसा जताने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया

विपक्षी दलों ने कहा, भय फैलाने की रणनीति के चलते 71 प्रतिशत सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद देने के लिए त्रिपुरा की जनता का हार्दिक आभार। यह जीत उनकी है।
-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री।

« उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में भाजपा समर्थकों ने पंचायती राज चुनावों में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। प्रेट्र

दास के अनुसार, 1,819 ग्राम पंचायत सीटों के चुनाव में भाजपा ने 1,476 सीट जीतीं। माकपा, कांग्रेस और टिपरा मोथा को क्रमशः 148, 151 और 24 सीट मिलीं। भाजपा ने इस पंचायत चुनाव में उस पर फिर भरोसा जताने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। विपक्षी दलों ने कहा कि वे सत्तारूढ़ दल की भय फैलाने की रणनीति के चलते 71 प्रतिशत सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि इस जनादेश से पता चलता है कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके विकास कार्यक्रमों में विश्वास बना हुआ है।

सनातन धर्म विवाद में उदयनिधि को अदालतों में पेशी से छूट

नई दिल्ली, आइएएनएस : सनातन धर्म को मच्छरों, डेंगू, मलेरिया या कोरोना की तरह खत्म करने का बयान देने वाले द्रमुक नेता एवं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में देशभर की विभिन्न अदालतों में दायर विभिन्न मामलों में पेश होने से छूट प्रदान कर दी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ उदयनिधि की ओर से दाखिल उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विभिन्न मामलों को एक स्थान पर क्लब करने की मांग की गई है। पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया और इस बीच उदयनिधि को अदालतों में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट प्रदान कर दी। याचिका में उदयनिधि ने इस बात को रेखांकित किया है कि एक मामला बेंगलुरु के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष है, जबकि बाकी मामले या शिकायतें महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में लंबित हैं जो वर्तमान में भाजपा द्वारा शासित हैं।

'एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं मिला'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

राजद प्रमुख लालू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला

लालू प्रसाद यादव। फाइल

राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने सारण के रेल व्हील प्लांट का हवाला देकर एनडीए सरकार और नीतीश कुमार को घेरा है। प्रसाद ने कहा कि एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला, नीतीश कुमार इस बारे में बताएं।

बुधवार को लालू प्रसाद ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। जिसमें उन्होंने अपने रेल मंत्रित्व काल में स्थापित किए गए सारण स्थित रेल व्हील प्लांट का हवाला दिया और कहा कि बिहार में रेल के पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ। इस प्लांट से अब तक दो लाख से अधिक पहियों का उत्पादन हो चुका है। अब मेड इन बिहार रेल पहिये भारतीय रेलवे की रफ्तार भरने में रिकार्ड बना रहे हैं। यूपीए का हवाला देकर लालू प्रसाद ने कहा कि मनमोहन सरकार के सहयोग के कारण बिहार में ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया, बिजली, रेलवे लाइन, मनरेगा के तहत रोजगार, रेलवे स्टेशन तथा सारण और मधेपुरा में रेल कारखानों का जाल बिछा दिया गया था। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा यूपीए काल में दिए गए सहयोग राशि से नीतीश कुमार ने अपना चेहरा खूब चमकाया। नीतीश बताएं कि एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला? हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 2009 के बीच पांच वर्ष में ही बिहार को 1.44 लाख हजार करोड़ की सहायता राशि दिलाई, लेकिन ये तो 2014 में 31, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ा कर झोली फैलाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता।

मेनका की चुनाव याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं

विधि संवाददाता, लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भाजपा की महिला नेता व पूर्व सांसद मेनका गांधी द्वारा सुल्तानपुर से निर्वाचित सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। चुनाव याचिका परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर ही दाखिल की जा सकती है, लेकिन यह समयाविधि पूरी होने के बाद दाखिल हुई।

यह आदेश जस्टिस राजन राय की एकल पीठ ने पारित किया। कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) के बिंदु पर अपनी सुनवाई पूरी कर गत पांच अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। मेनका की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा था। उनकी दलील थी कि भले ही याचिका समय सीमा निकल जाने के बाद दाखिल की गई है, किंतु सुनवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अपना पूरा आपराधिक इतिहास सार्वजनिक नहीं किया। याचिका में कहा गया था कि राम भुआल निषाद पर 12 मुकदमे हैं, जबकि उन्होंने आठ की ही जानकारी दी है।

महिलाओं को लुभा रही मंईयां सम्मान योजना, 30 लाख से अधिक आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

30 लाख से अधिक महिलाएं करा चुकी हैं पंजीयन, 50 लाख से अधिक को जोड़ने का है लक्ष्य

राजनीतिक विरोध से इतर विपक्षी विधायक भी जुटे हैं अपने क्षेत्र में योजनाओं का लाभ दिलाने में

हेमंत सोरेन। फाइल

राज्य में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की घर-घर में चर्चा हो रही है। विपक्षी दल भले ही इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को लुभाने की कोशिश बता रहे हैं, लेकिन हर महीने खाते में एक हजार रुपये भेजे जाने वाली इस योजना ने आधी आबादी को पूरा आकर्षित किया है। योजना की लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक 30 लाख से ज्यादा महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। इस योजना में 50 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आला अधिकारी स्वयं पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि योजना के तहत अधिकाधिक महिलाओं को लाभ दिलाएं। उन्होंने बिचौलियों को दूर रखने का आदेश देते हुए कहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को कुछ महिलाओं के खाते में राशि भेजे जाने का प्रमाणपत्र देकर राज्यपाल ने इस योजना को दुमका में लांच भी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक विरोधियों ने भी इस योजना को हाथों-हाथ लिया है। वे खुलकर इसका प्रचार या प्रशंसा करने से भले ही परहेज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को इस अभियान में लगाया है, ताकि क्षेत्र की महिलाओं को योजना का लाभ मिलने में परेशानी नहीं हो। महिलाओं को लाभ दिलाने पर आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

आचार संहिता लागू होने तक चालू रखें योजना : राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि योजना का लाभ लेने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई जाए या इसे चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि तक जारी रखा जाए। राय ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का आवेदन फार्म अपने स्तर पर भी प्रकाशित करवाया है।

विपक्ष की भी नजर : भाजपा व अन्य विपक्षी दल की भी इसपर नजर है। भाजपा के नेताओं ने इसे केवल वोट पाने के लिए चुनाव के ठीक पहले दिया जा रहा प्रलोभन बताया है। उन्होंने सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि हेमंत सरकार को अगर वास्तव में महिलाओं की चिंता होती तो वह चुनाव के समय में ऐसी योजना लाने के बजाय पहले लागू करते। भाजपा काट ढूंढ रही है।

पंजाब में शिअद को झटका, बंगा विधायक आप में शामिल

कैलाश नाथ ● जागरण

- मुख्यमंत्री ने शिअद विधायक अयाली को भी दिया 'आ जाओ प्रस्ताव', बोले-सभी नेता सुखबीर जैसे नहीं
- विधानसभा में शिअद विधायकों की संख्या मात्र 2 रह गई, आप के हुए 93
- दाखा से मनप्रीत अयाली व मजीठा से गनीव कौर ही बनीं शिअद विधायक

मुख्यमंत्री भगवंत मान शिअद के विधायक डा. सुखविंदर सिंह सुक्खी को आप में शामिल करवाते हुए। सौ. इंटरनेट मीडिया

चंडीगढ़ : पंजाब में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में, शिरोमणि अकाली दल के बंगा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक डा. सुखविंदर सिंह सुक्खी आप में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को अपने आवास पर डा सुक्खी को सैकड़ों समर्थक सहित पार्टी में शामिल कराया।

मुख्यमंत्री मान ने डा. सुक्खी को ज्वाइनिंग कराने के बाद कहा कि अकाली दल की अब कोई विचारधारा नहीं रह गई है। दाखा विधानसभा क्षेत्र से अकाली विधायक मनप्रीत अयाली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी में सभी नेता सुखबीर बादल जैसे नहीं हैं, कई अच्छे नेता हैं और यदि वे भी आप में आते हैं तो वह उनका भी स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही संकेत देते हुए एक सरकारी समारोह में कहा था कि पंजाब में 25 वर्ष तक राज करने का दावा करने वाले सुखबीर बादल के पास अब 25 नेता भी नहीं रह गए हैं।

डा सुक्खी बंगा विधानसभा क्षेत्र से 2017 व 2022 में लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। डा. सुक्खी के आप में जाने के साथ ही पंजाब विधानसभा में शिअद के विधायकों की संख्या मात्र 2 रह गई है जबकि आप के 93 विधायक हो गए हैं। डा. सुक्खी 16वीं विधानसभा के तीसरे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी बदली है। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के डा. राजकुमार चब्बेवाल ने आप व आप के शीतल अंगुराल ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी।

राजनीतिक हाशिये पर चल रही शिअद के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि डा. सुक्खी एकमात्र ऐसे विधायक थे जो विधानसभा में पार्टी का सक्रिय प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पार्टी विधायक दल के नेता मनप्रीत अयाली का पहले से ही शिअद प्रधान सुखबीर बादल से मनमुटाव चल रहा है जबकि मजीठा से अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की पत्नी गनीव कौर विधायक तो हैं परंतु राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नहीं हैं। शिरोमणि अकाली दल के आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने प्रधान सुखबीर बादल के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा है।

विस में अकाली दल की संख्या 3 से घटकर अब 2 रह गई है। ऐसे में यदि कोई और विधायक टूटता है तो डा. सुखविंदर कुमार सुक्खी को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना होगा क्योंकि दलबदल कानून में यदि दो-तिहाई सदस्य टूटते हैं तो दलबदल कानून नहीं लगेगा, अन्यथा डा. सुक्खी को इस्तीफा देना होगा।

****

पंजाब के नए राज्यपाल कटारिया के 'सक्रिय' होते ही पक्ष-विपक्ष का एक सुर में 'विरोध' शुरू

कैलाश नाथ ● जागरण

- मुख्यमंत्री मान बोले-नए राज्यपाल कर रहे अधिकारियों से जान-पहचान
- शिअद ने कहा-समानांतर बैठकें करना संघवाद की भावना के खिलाफ

गुलाब चंद कटारिया।

भगवंत मान। फाइल

चंडीगढ़ : पंजाब के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सक्रिय हो गए हैं। राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उन्होंने अधिकारियों से बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। कटारिया ने सोमवार को बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके एक दिन बाद ही राज्यपाल ने राज्य में विश्वविद्यालयों के वीसी (वाइस चांसलर) के रिक्त पदों की जानकारी उच्च शिक्षा सचिव कमल किशोर से मांगी है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि लंबे समय से वीसी की नियुक्तियां क्यों नहीं हुई हैं।

पंजाब की राजनीति में राज्यपाल की सक्रियता इसलिए भी ध्यानाकर्षक है क्योंकि पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित व मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच खासा घमासान चला था जिसकी शुरूआत भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लगाने को लेकर हुई थी। पुरोहित व मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि विधानसभा का सत्र बुलाने में राज्यपाल की भूमिका की बाधा दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटियों का चांसलर मुख्यमंत्री को बनाने के लिए विधानसभा में बिल पारित किया था। राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दिए बिना पंजाब सरकार को वापस भेज दिया था। राज्यपाल की सक्रियता पर मुख्यमंत्री भी सजग नजर आ रहे हैं। उन्होंने फिलहाल इन बैठकों को अधिकारियों से 'जान-पहचान' वाली मीटिंग बताया है जबकि विपक्ष ने इन बैठकों को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। शिरोमणि अकाली दल के नेता डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि राज्यपाल की प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग संविधान में निहित संघवाद की भावना के विरुद्ध है तथा यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है।

पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू

अत्मनिर्भर भारत

- पैनेसिया बायोटेक ने विकसित की है डेंगीआल वैक्सीन, 18 राज्यों में होगा क्लीनिकल ट्रायल
- पीजीआइएमएस रोहतक में परीक्षण के तहत पहले प्रतिभागी को लगाया गया टीका

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और पैनेसिया बायोटेक ने भारत में डेंगू की वैक्सीन विकसित करने के लिए पहली बार तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया है। पैनेसिया बायोटेक ने भारत की स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन 'डेंगीआल' को बनाया है। इस परीक्षण में पहले प्रतिभागी को आज पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआइएमएस) रोहतक में टीका लगाया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि आइसीएमआर के सहयोग से पैनेसिया बायोटेक भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर चरण-3 का क्लीनिकल परीक्षण करेगा जिसमें 10,335 से अधिक स्वस्थ वयस्क प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा-'भारत के पहले स्वदेशी डेंगू टीके के लिए चरण-तीन के नैदानिक परीक्षण

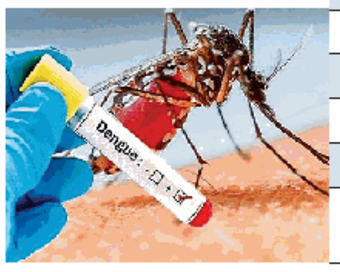

डेंगू के मामले और इससे हुई मौतें

वर्ष	कुल मरीज	मौतें
2018	10148	26
2019	157315	166
2020	44845	56
2021	193245	346
2022	233251	303
2023	289235	485
2024	320901	32

आंकड़े नेशनल सेंटर फार वेक्टर बार्न डिसीज (एनसीवीबीडी) के अनुसार

की शुरुआत डेंगू के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। यह नागरिकों को इस बीमारी से बचाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और टीका अनुसंधान और विकास में भारत की क्षमताओं को रेखांकित करता है।' उन्होंने कहा कि आइसीएमआर और पैनेसिया बायोटेक के बीच इस सहयोग के माध्यम से हम न केवल अपने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठा रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अपने दृष्टिकोण को भी सुदृढ कर रहे हैं।

वर्तमान में, भारत में डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है। सभी चार सीरोटाइप के लिए एक प्रभावी वैक्सीन का विकास जरूरी है। भारत में डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप कई क्षेत्रों में संक्रमण फैला सकते हैं। टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन (टीवी003/टीवी005) को मूल रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ (एनआइएच), अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। इसने विश् में प्रीक्लीनिकल और क्लीनिकल परीक्षणों में आशाजनक परिणाम हासिल किए हैं। पैनेसिया बायोटेक स्ट्रेन प्राप्त करने वाली तीन भारतीय कंपनियों में से एक है, जो विकास के सबसे उन्नत चरण में है। कंपनी ने पूर्ण विकसित टीका फार्मूलेशन विकसित करने के लिए इन स्ट्रेन पर बड़े पैमाने पर काम किया है और इस काम के लिए एक पेटेंट प्रक्रिया भी रखी है। भारतीय टीका फार्मूलेशन के चरण-1 और 2 के क्लीनिकल परीक्षण 2018-19 में पूरे हुए थे और इसके आशाजनक परिणाम मिले। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, पिछले दो दशकों में डेंगू के वैश्विक मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। 2023 के अंत तक 129 से अधिक देशों में डेंगू अपने पैर पसार चुका है। इस स्वदेशी वैक्सीन के बनने से जहां एक ओर देशभर में लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा वहीं अन्य देशों को भी इसका लाभ मिलेगा।

30 पूर्व सैनिकों ने तैयार किए 400 जवान

स्वतंत्रता दिवस विशेष

- अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की पहल, प्रदेश में 10 जगहों पर प्रशिक्षण केंद्र

राकेश साहू ● नईदुनिया

रायपुर : प्रदेश में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद युवाओं को सेना में भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संगठन से जुड़े 30 पूर्व सैनिकों से प्रशिक्षण लेकर चार वर्ष में लगभग 400 जवानों को सीआरपीएफ, बस्तरिया बटालियन, डीआरजी, अग्निवीर, वन रक्षक, पुलिस सहित एयर फोर्स में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसमें मैदानी क्षेत्रों के साथ बस्तर संभाग के युवा भी शामिल हैं।

संगठन द्वारा रायपुर जिले के बोरियाखुर्द, तिल्दा, अभनपुर में युवाओं को निश्शुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी में भी ट्रेनिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है। यहां पूर्व सैनिकों के द्वारा रोजाना सुबह पांच से नौ बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जाता है कि जिस शहर या गांव के मैदान में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। वहां शहर के साथ ग्रामीण युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।

हर केंद्रों में 100-150 तक युवा : संगठन के जुड़े पूर्व सैनिकों ने बताया कि प्रदेश में 10 सैन्य प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रों में 100 से 150 युवा शामिल हो रहे हैं। इनमें लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। इसके अलावा दूरस्थ अंचल के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास की सुविधा भी दी है। हालांकि रुकने और भोजन के लिए पैसा लिया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण निश्शुल्क है।

अभनपुर प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को ट्रेनिंग देते हुए पूर्व सैनिक। सौ. संगठन >>

संगठन द्वारा युवाओं को सैन्य बलों में भर्ती के लिए निश्शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए हर केंद्र में दो से चार पूर्व सैनिक सेवा देते हैं। आने वाले दिनों में अन्य जिलों में विस्तार किया जाएगा।

- योगेश साहू, पूर्व सैनिक, सचिव, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

चयनित युवा

सीआरपीएफ	20
बीएसएफ	30
बस्तरिया बटालियन	85
अग्निवीर	140
एयरफोर्स	60
वनरक्षक	20
पुलिस	25
अन्य	20

तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे डाक्टर, मरीज होते रहे परेशान

जूनियर डाक्टर की दुष्कर्म-हत्या : स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने वाले फोर्डा अध्यक्ष माथुर को आरडीए के अध्यक्ष पद से देना पड़ा इस्तीफा

बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बाधित, बिहार व झारखंड समेत कई राज्यों में हड़लात का व्यापक असर

जागरण टीम, नई दिल्ली

कोलकाता में जूनियर डाक्टर की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या को लेकर डाक्टरों में आक्रोश चरम पर है। राजधानी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार तीसरे दिन जूनियर डाक्टरों की हड़ताल से लोग परेशान रहे। अस्पतालों में मरीजों की लंबी-लंबी कतारें दिखीं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की फैकल्टी एसोसिएशन ने जूनियर डाक्टरों की हड़ताल को समर्थन दिया है। एम्स में बुधवार शाम को फैकल्टी के सदस्यों ने जूनियर डाक्टरों के साथ मार्च निकाला। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फैकल्टी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया है। बंगाल में डाक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। सभी सरकारी अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) के पर्ची काउंटरों पर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। चंडीगढ़ पीजीआइ व अन्य सरकारी

कोलकाता की एक युवा चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में विजयवाड़ा के सरकारी जनरल अस्पताल में डाक्टरों ने एक लैब कोट और एक स्टेथोस्कोप पर खून के निशानों को लाल स्याही से इस तरह ढककर विरोध प्रदर्शन किया। एएफपी

अस्पतालों में तीसरे दिन भी डाक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी बंद रही। इलाज नहीं मिलने पर कुछ मरीज लौट गए। बिहार में डाक्टरों का कार्य बहिष्कार कुछ जगहों पर जारी रहा। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की ओपीडी व पूर्व निर्धारित सर्जरी स्थगित रही। झारखंड में जूनियर डाक्टरों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। एमजीएम जमशेदपुर, रिम्स रांची और पीएमसीएच धनबाद में सुबह नौ बजे से ही डाक्टर ड्यूटी छोड़ धरने पर बैठे रहे, जबकि मरीजों को अपने इलाज के लिए दिनभर भटकते रहना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी हड़ताल का प्रभाव दिखा। लखनऊ में रेजिडेंट डाक्टरों ने एसजीपीजीआइ, केजीएमयू और लोहिया संस्थान में विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने मंगलवार को हड़ताल खत्म करने की घोषणा की थी। इसके बाद डाक्टर दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में हड़ताल खत्म कर दी गई है, लेकिन अधिकतर अस्पतालों में जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले फोर्डा के अध्यक्ष डा. अविरल माथुर को मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के रेजिडेंट डाक्टर एसोसिएशन (आरडीए) के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा है। फोर्डा के अध्यक्ष के तौर पर भी उनका विरोध हो रहा है। उनके स्थान पर डा. अपर्णा सेतिया मौलाना आजाद मेडिकल कालेज आरडीए की अध्यक्ष बनाई गई हैं। डा. अर्पणा सेतिया ने कहा कि शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी।

बंगाल में आधी रात को सड़कों पर उतरीं महिलाएं

- चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना के खिलाफ लड़कियों में रोष
- नारा था स्वंतत्रता दिवस की आधी रात महिलाओं की आजादी के लिए

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या की घटना के खिलाफ कोलकाता व राज्य के जिलों में बुधवार आधी रात को महिलाएं-लड़कियां सड़कों पर उतरीं और उन्होंने न्याय की मांग की। जिस अकेली युवती के आह्वान पर आधी रात को सड़कों पर महिलाएं उतरीं उनका नाम रिमझिम सिन्हा है। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा व वर्तमान शोधार्थी महिला चिकित्सक से साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना का इंसाफ चाहती हैं।

दरअसल 10 अगस्त की रात को उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके लड़कियों से आधी रात को सड़क पर उतरने का आह्वान किया था। इसका उन्हें लड़कियों की ओर से जबरदस्त समर्थन मिला। इस कार्यक्रम का नाम लड़कियां रात पर कब्जा करें दिया गया था। कार्यक्रम का नारा था स्वंतत्रता दिवस की आधी रात महिलाओं की आजादी के लिए। लड़कियों ने इस कार्यक्रम के लिए अनेक वाट्सएप ग्रुप बनाया था। रिमझिम के आह्वान पर रात 11.55 बजे कोलकाता के जादवपुर 8 बी बस स्टैंड, एकैडमी आफ फाइन आर्ट्स, कालेज स्ट्रीट समेत अनेक जगहों पर लड़कियां व महिलाएं इकट्ठा हुईं। रिमझिम के आह्वान पर सिर्फ बंगाल ही नहीं दिल्ली के बंगालीटोला चित्तरंजन पार्क में भी लड़कियां सड़क पर उतरीं। बेंगलुरु के टाउन हाल के सामने भी लड़कियां इकट्ठा हुईं। इस कार्यक्रम के लिए शहर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। मेट्रो रेलवे ने भी अपनी ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया था। रिमझिम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों उनके पास इतने काल आ रहे हैं कि फोन हैंग हो जा रहा है। रिमझिम ने बताया कि विभिन्न जिलों के 60-70 स्थानों के स्थानीय लोगों ने उनसे संपर्क किया था और अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए।

मी-टू में शिकायत करने वाली अपनी सहेलियों के लिए भी लड़ी थीं रिमझिम : रिमझिम की दो सहेलियों ने मी-टू में शिकायत दर्ज कराई थी। रिमझिम ने उनके लिए भी लड़ाई लड़ी थी। 2018 में सायबराबाद में एक डाक्टर की हत्या और जलाए जाने की घटना के खिलाफ भी रिमझिम ने रात में जादवपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। यह बिल्कुल प्रतीकात्मक था। ज्यादा लोग नहीं आए थे। रिमझिम को संसदीय लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल पर कोई भरोसा नहीं है।

समर्थन में टीएमसी नेता ने भी दिया धरना

टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने भी घटना के विरोध में महिलाओं की ओर से मध्य रात्रि को किए जाने वाले प्रदर्शन से एकजुटता दिखाने के लिए रात को धरना दिया। उन्होंने कहा कि उनकी खुद की भी एक बेटी और एक पोती है। हमें इस घटना के खिलाफ साथ खड़े होना चाहिए।

कन्नौज : दुष्कर्म आरोपित पूर्व ब्लाक प्रमुख की डीएनए जांच कराएगी पुलिस

जागरण संवाददाता, कन्नौज : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव की पुलिस डीएनए जांच कराएगी। पाक्सो एक्ट कोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस के आवेदन और आरोपित की जमानत अर्जी पर कोर्ट 16 अगस्त को सुनवाई करेगी। वहीं, मामले में समझौता कराने के लिए पूर्व ब्लाक प्रमुख के करीबियों ने पीड़िता की बुआ के बैंक खातों में बड़ी रकम जमा कराई है। आरोपित बुआ का आधार कार्ड मिलने पर पुलिस अब 16 अगस्त को उसके बैंक खाते खंगालेगी। रुपये जमा कराने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।

पूर्व ब्लाक प्रमुख पर उनके ही चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में 11 अगस्त की रात किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता अपनी बुआ संग वहां पहुंची थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके से नवाब को गिरफ्तार किया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। 13 अगस्त को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान में पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया तो पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपित का डीएनए जांच कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट 16 अगस्त को सुनवाई होगी।

'सीबीआइ को जांच सौंपने में देरी कर किसे बचाना चाह रही थीं ममता'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीएम ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा, घटना के बाद सुबूत नष्ट कराने का लगाया आरोप

बंगाल में डाक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में ममता बनर्जी सरकार के रुख पर भाजपा ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। राज्य पुलिस द्वारा एफआइआर दर्ज करने में देरी, शुरुआत में घटना की सत्यता छिपाने का प्रयास सहित सीबीआइ को जांच सौंपने में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ऐसे मामलों में सुबूत एकत्र के करने के लिहाज से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सीबीआइ को जांच सौंपने में देरी कर सुबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया। भाजपा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोलकाता में डाक्टर के साथ दुष्कर्म की बात प्रथम दृष्टया सामने आई। संभवतः सामूहिक दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या कर दी गई। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर जो टिप्पणियां की हैं, वे चिंताजनक हैं। वे बताती हैं कि किस तरह बंगाल में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ममता को निर्ममता बनर्जी नाम देते हुए भाटिया ने कहा कि जब उन्हें पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तब वह किसको बचाने की साजिश रच रही थीं? कलकत्ता हाई कोर्ट को जांच सीबीआइ को क्यों ट्रांसफर करनी पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पहले 48 घंटे सुबूत जुटाने व फोरेंसिक जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ममता बनर्जी ने अपराध के एक दिन बाद बयान दिया कि कुछ दिन बाद सीबीआइ को जांच ट्रांसफर कर देंगी। सवाल है कि कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? पीड़िता के माता-पिता वहां पहुंच गए तो क्या कारण था कि पार्थिव शरीर दिखाने में उन्हें तीन घंटे तक इंतजार कराया गया। मेडिकल कालेज के जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सुरक्षा देने की थी, वह सुबूत नष्ट करने में लगा था।

ममता ने की सीबीआइ से 18 तक जांच पूरी करने की मांग

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की जांच हाई कोर्ट द्वारा सीबीआइ को सौंपे जाने के बाद बुधवार को केंद्रीय एजेंसी से 18 अगस्त तक इसकी जांच पूरी करने और दोषियों की फांसी सुनिश्चित कराने की मांग की है। ममता ने कहा कि पीड़िता के न्याय के लिए 17 अगस्त को वह खुद कोलकाता में मौलाली से धर्मतल्ला तक रैली का नेतृत्व करेंगी और दोषियों की रविवार तक फांसी की मांग करेंगी। 90 प्रतिशत जांच तो पुलिस ने कर ली थी, इसलिए अब सीबीआइ दोषियों की फांसी सुनिश्चित करे। राज्यपाल डा.सीवी आनंद बोस ने कहा कि घटना पूरी मानवता के लिए शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको के पास एकत्रित होकर धरना देते हुए नारेबाजी की। कहा कि राज्य सरकार घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी के दो सांसद और तीन विधायक इसी मेडिकल कालेज से पढ़े हुए हैं मगर फिर भी उन्होंने अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है।

उत्तराखंड : नर्स के साथ दरिंदगी... दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूच दिया चेहरा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर

- आठ अगस्त को उप्र के रामपुर में खाली प्लाट से बरामद हुआ था तस्लीम जहां का शव

कोलकाता में जूनियर डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद उपजे आक्रोश के बीच उत्तराखंड में एक नर्स के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। ऊधम सिंह नगर जिले से सटी उप्र की सीमा में झाड़ियों में नर्स का शव मिला है। बरेली निवासी वहशी ने पहले उसकी रेकी की। फिर सुनसान स्थान पर अकेला पाकर मुंह दबाकर अचेत कर दिया। दुष्कर्म करने के बाद स्कार्फ से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पहचान न हो सके इसके लिए पत्थर से चेहरा कूचकर शव झाड़ियों के पीछे छिपा दिया और रुपये व मोबाइल लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित को राजस्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बुधवार को मामले का पर्दाफाश करते हुए एसएसपी डा. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि उप्र के बिलासपुर अंतर्गत डिबडिबा स्थित वसुंधरा इनक्लेव निवासी 33 वर्षीय नर्स तस्लीम 30 जुलाई की रात से गायब थी। वह रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल नर्स थी और ड्यूटी कर लौट रही थी। अगले दिन तस्लीम की बहन की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर

रुद्रपुर कोतवाली में तस्लीम जहां हत्याकांड का पर्दाफाश करते एसएसपी मंजूनाथ टीसी, एसपी सिटी मनोज कत्याल व पीछे पुलिस टीम के साथ पकड़ा गया हत्यारोपित। जागरण

तलाश शुरू कर दी थी। आठ अगस्त को डिबडिबा क्षेत्र में ही वसुंधरा इनक्लेव से कुछ आगे एक खाली प्लाट में तस्लीम जहां की क्षत-विक्षत लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई थी। इधर, पुलिस जांच में जुटी रही। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 30 जुलाई को तस्लीम इंदिरा चौक रुद्रपुर से आटो में बैठकर गई। इसी बीच मृतका से लूटे हुए मोबाइल की लोकेशन बरेली में मिली। पता चला कि मोबाइल तुरसापट्टी थाना शाही जिला बरेली निवासी धर्मेंद्र पुत्र पूरन लाल इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस बरेली पहुंची तो वह फरार हो चुका था। पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया।

अभियुक्त ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम : लूट के इरादे से 30 जुलाई को तस्लीम का पीछा किया और निर्जन स्थान पर पकड़कर उसे झाड़ियों में ले गया। बचाव में शोर मचाने पर उसने उसी के स्कार्फ से गला घोंट दिया। अचेत अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पत्थर से वार कर चेहरे को कूच दिया।

बिहार : सामूहिक दुष्कर्म के बाद खुरपी से काटकर हत्या

जासं, मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में माता-पिता के सामने घर से अगवा कर अनुसूचित जाति की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वह आठवीं की छात्रा थी। उसका शव सोमवार को गांव के समीप स्थित एक तालाब के पास मिला। मंगलवार को उसकी मां ने संजय राय समेत पांच अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बुधवार को एसएसपी राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने बताया कि हत्या में खुरपी का उपयोग किया गया है। मृत किशोरी के गर्दन के पिछले हिस्से, सिर एवं हथेली पर धारदार हथियार से जख्म के निशान मिले हैं। पुलिस तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्राथमिकी में किशोरी की मां ने पुलिस को बताया है कि रविवार की रात संजय राय अपने पांच साथियों के साथ दो-तीन बाइक से घर आया उसके पति तथा पुत्र को जातिसूचक गालियां देते हुए मारने-पीटने लगा। कहा कि तुम्हारी बेटी कहां है, उसका बलात्कार करेंगे। फिर दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया। मारपीट कर चाकू व हथियार दिखा पति व बेटे की हत्या की धमकी देते हुए पुत्री का मुंह दबाकर बाइक से लेकर चला गया। अगले दिन कुछ लोग तालाब के पास गए थे, वहीं शव अर्द्धनिर्वस्त्र अवस्था में मिला।

विकास गाथा

कटड़ा-रियासी के बीच त्रिकुटा पर्वत में बन रही 3209 मीटर लंबी सुरंग तैयार होने भर का है इंतजार, इस टनल के पूरा होने के साथ ही कश्मीर पूरे देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा

मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के नीचे से गुजर कश्मीर पहुंचेगी ट्रेन

अमित माही ● जागरण

ऊधमपुर : अब बस दो माह का इंतजार और...। उसके बाद मां वैष्णो देवी के चरणों (त्रिकुटा पर्वत के नीचे से) से होते हुए कश्मीर घाटी तक का रोमांचक सफर ट्रेन से कर सकेंगे। रियासी तक रेल लाइन तैयार होने के बाद रेलवे का सारा ध्यान कटड़ा से रियासी के बीच 19 किलोमीटर के रेलखंड को पूरा करने पर है। सबकुछ ठीक रहा तो दिवाली तक रेलवे कश्मीर घाटी को रेल नेटवर्क से देश से जोड़ देगा। इस खंड पर केवल एक टनल का काम पूरा करना बाकी है। इसके पूरा होते ही देश के किसी भी हिस्से से चलने वाली ट्रेन ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर तक पहुंच सकेगी।

कटड़ा-रियासी रेल खंड पर मां वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत की तलहटी में मां वैष्णो देवी के चरणों से नीचे से गुजरने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को छोड़कर बाकी काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 में इस टनल का ब्रेकथ्रू (सुरंग आरपार) हुआ था। इसके बाद से टनल को अंदर से पक्का करने का काम शुरू किया गया। टनल में जल निकास प्रणाली, प्लास्टर, बिजली, वेंटिलेशन के साथ सिगनल, निगरानी व सुरक्षा प्रणाली के साथ ट्रैक बिछाने का काम शेष है। अगर कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो इन सभी कामों के दो माह के भीतर पूरा होने की संभावना है। 272 किलोमीटर लंबे ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के अंतर्गत 77 प्रतिशत हिस्से में रेल परिचालन पहले ही शुरू हो चुका है। शेष 23 प्रतिशत काम 111 किलोमीटर लंबे बनिहाल-कटड़ा रेलखंड में बचा है। इस खंड पर बनिहाल से 48 किलोमीटर दूर संगलदान तक इसी वर्ष फरवरी में रेल परिचालन शुरू किया गया था। इसके बाद संगलदान से रियासी तक 44 किलोमीटर का रेलखंड भी ट्रेन परिचालन के लिए तैयार है। इसके बाद रेलवे का सारा ध्यान रियासी से कटड़ा तक के 19 कलोमीटर रेल खंड को शुरू करने पर होगा। इस खंड केवल 3209 मीटर लंबी टनल टी-33 का काम ही शेष है। लगभग 60 फीसद काम हो चुका है और बाकी का पूरा होते ही रेल से कश्मीर तक का सफर करने वाले रेल यात्री त्रिकुट पर्वत पर आसीन मां वैष्णो देवी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेते हुए गुजरेंगे। यह अनुभव मां के भक्तों के लिए बेहद सुखद और अद्भुत होगा। साथ ही पर्यटकों को भी लुभाएगा।

समूची घाटी से देश को जोड़ने वाले यूएसबी आरएल प्रोजेक्ट में कटड़ा- रियासी खंड के बीच त्रिकुटा पर्वत में बन रही 3209 मीटर लंबी टी-33 सुरंग। जागरण

रियासी-संगलदान रेलखंड पर इसी माह चल सकती है ट्रेन

सीआरएस दिनेश चंद देशवाल ने बीते शुक्रवार को रियासी-संगलदान रेलखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे पुल नंबर 43 सहित विभिन्न स्थानों पर उतर कर रेलवे ट्रैक और ट्रेन परिचालन से संबंधित विभिन्न चीजों का जायजा लिया था। सीआरएस संतुष्ट रहे। उम्मीद है कि इसी माह के अंत तक इस रेलखंड पर भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। ऐसा होने से रियासी से घाटी तक रेल यात्रा शुरू हो जाएगी। इसी ट्रैक पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल के पास कौड़ी साइट में तीन हेलीपैड का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसे अगस्त अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। तीन हेलीपैड के निर्माण इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रेलखंड का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आ सकते हैं।

'डेरा प्रमुख की तरह 89 कैदियों को दी गई थी फरलो-पैरोल'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत सिंह अकेले ऐसे कैदी नहीं हैं, जिन्हें 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा प्रमुख के अलावा 89 कैदी और ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार ने जेल में उनके अच्छे आचरण और व्यवहार को देखते हुए पैरोल अथवा फरलो प्रदान की है। दो कैदियों के पैरोल अथवा फरलो के आवेदनों को प्रदेश सरकार ने अलग-अलग कारणों से रद कर दिया था। एक केस में कैदी का पता गलत था, जबकि दूसरे केस मे पूर्व में मिली पैरोल के बाद कैदी ने सही समय पर सरेंडर नहीं किया था।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की फरलो के आवेदन पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने यह जानकारी मुहैया कराई थी। हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख के फरलो के आवेदन पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से पूछा था कि राज्य में ऐसे कितने एकसमान केस हैं, जिनमें फरलो अथवा पैरोल दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सभी पैरोल व फरलो की पूरी डिटेल उपलब्ध कराई गई है। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र खुराना बुधवार को मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि डेरा प्रमुख की फरलो का हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से किसी तरह का संबंध है। डेरा प्रवक्ता ने कहा कि डेरा प्रमुख को कानून के दायरे में फरलो मिली है।

गुरमीत सिंह। फाइल

- हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा-डेरा प्रमुख अकेले नहीं हैं

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 अगस्त, 2024

1975 में हुई थी ग्रामीण बैंकों की शुरुआत। वर्तमान में देश में 43 ग्रामीण बैंक हैं। अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंक इनके प्रायोजक हैं।

...ऐसे उभरती वैश्विक ताकत बना भारत

आज हम 78 वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त, 1947 को आजादी हासिल करने के बाद देश ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आइने एक नजर डालते हैं भारत की उपलब्धियों पर।

20 वर्ष में 10 गुना से अधिक बढ़ी जीडीपी

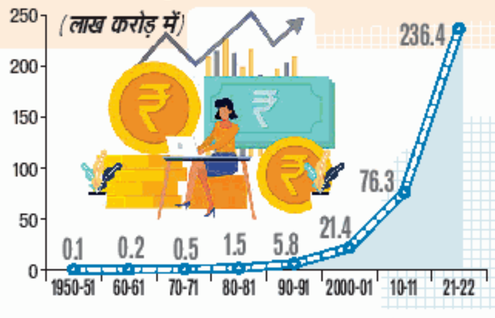

600 गुना बढ़ा भारत का निर्यात

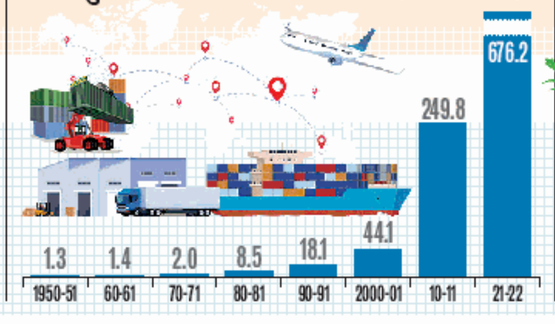

छह गुना बढ़ा अनाज उत्पादन

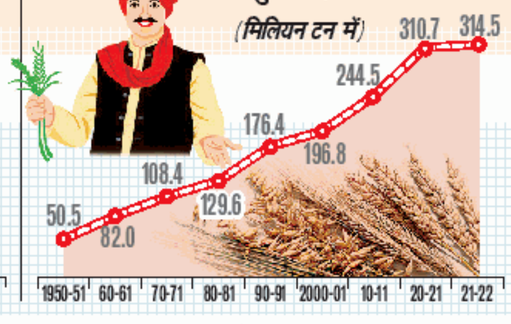

335 गुना बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

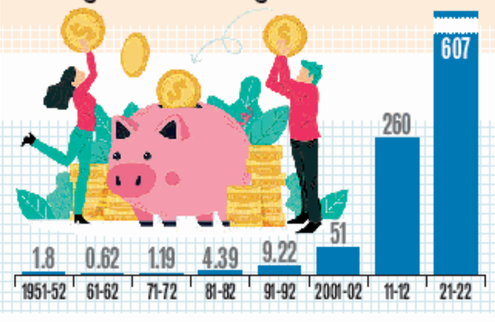

सात गुना बढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई

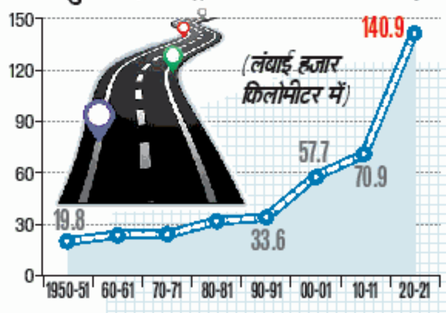

बिजली की कमी से सरप्लस बिजली

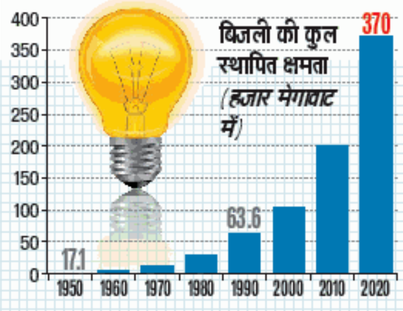

दूध उत्पादन में नंबर 1 बना भारत

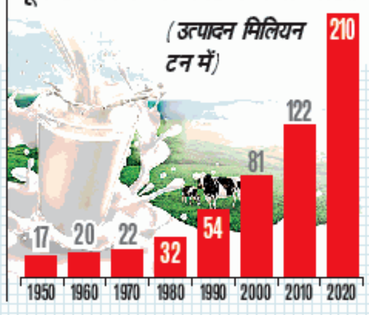

₹2.7 लाख करोड़ था भारत की जीडीपी का आकार 15 अगस्त, 1947 को

₹173.82 लाख करोड़ हो गया है जीडीपी का आकार वित्त वर्ष 2023-24 तक

जागरण इन्फो

1,000 से अधिक यूनिवर्सिटी

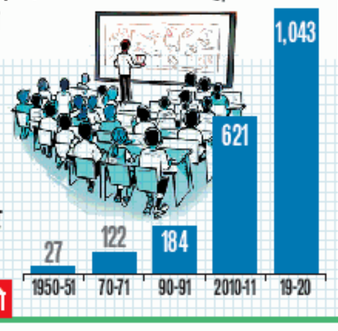

21 गुना बढ़े मेडिकल कालेज

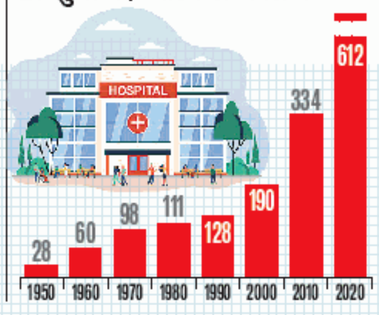

13 लाख हो गई डाक्टरों की संख्या

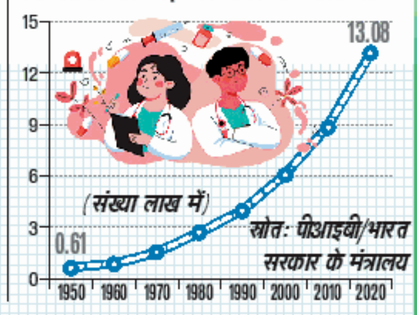

स्रोत: पीआइबी/भारत सरकार के मंत्रालय

एकता व भाईचारे की रक्षा के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध : मोदी

पीएम ने विभाजन की त्रासदी का शिकार हुए लोगों को किया नमन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

1947 में देश के विभाजन के दौरान कभी न भूली जा सकने वाली त्रासदी झेलने वाले लोगों के कष्टों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एकता और भाईचारे की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई है। पीएम ने विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर एक्स पर पोस्ट किया-हम विभाजन का दर्द झेलने वाले अनगिनत लोगों को याद करते हैं, जिन पर इस त्रासदी का अकल्पनीय प्रभाव पड़ा। पीएम ने इसके शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उन सभी के साहस को नमन। उनका साहस हमें मानव की संघर्ष शक्ति से परिचित कराता है। उनमें से तमाम लोग टूटे नहीं। उन्होंने जीवन फिर से खड़ा किया और अनंत सफलताएं पाईं।

इतिहास को याद रखने वाला देश ही शक्तिशाली बनता है : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गृह मंत्री ने विभाजन विभीषिका दिवस पर याद की बंटवारे की त्रासदी
- कहा-इस दौरान लोगों को हुए कष्टों को कभी भूला नहीं जा सकता

देश विभाजन के दौरान त्रासदी झेलने वालों को याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो देश अपने इतिहास को याद रखता है, वही भविष्य बना सकता है और शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकता है। शाह ने कहा, अंग्रेजी राज से मुक्ति के साथ ही देश को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाया गया था। इस संकट में न सिर्फ करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, बल्कि 20 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी।

गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया-विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अमानवीय दर्द सहने वालों, जीवन गंवाने वालों व अपनी जड़ों से उखड़ जाने वालों को श्रद्धांजलि। यह हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसके कष्टों को कभी भूला नहीं जा सकता। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इतिहास को याद रखना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का मूलभूत कार्य है।

'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया तिरंगा

गृह मंत्री अमित शाह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत बुधवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पूरा देश तिरंगामय हो रहा है। आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा लहरा कर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले नायकों को याद किया। तिरंगा करोड़ों देशवासियों की एकता, निष्ठा व गौरव का प्रतीक बनकर अनंत काल तक लहराता रहेगा।

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एएनआइ

उल्लेखनीय है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया था। तब से प्रति वर्ष इस दिन विभाजन की त्रासदी का स्मरण किया जाता है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि यह दिन उन लोगों को याद करने के लिए है, जिनका संघर्ष व बलिदान भूला नहीं जा सकता। घृणा व हिंसा की हद के कारण करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। विभाजन से किसी का घर छूटा। किसी की जान गई।

जो 1947 में पाकिस्तान में हुआ, वही अब बांग्लादेश में हो रहा : योगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ

- उप्र के सीएम ने कहा-बांग्लादेश में चिल्ला रहे डेढ़ करोड़ हिंदू पर कथित सेक्युलरिस्ट के मुंह सिले
- बोले- महर्षि अरविंद ने कहा था कि पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या उसका इतिहास मिटेगा

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो 1947 में पाकिस्तान में हुआ था, वही अब बांग्लादेश में हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदुओं को मार दिया गया था, आज फिर वही आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट व बहन-बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज जब डेढ़ करोड़ हिंदू बांग्लादेश में अस्मिता बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, तब दुनिया व भारत के कथित सेक्युलरिस्ट के मुंह सिले हैं, क्योंकि इन्हें वोटबैंक की चिंता है।

योगी ने कहा, जो किसी युग में नहीं हुआ, वह सत्ता के प्रति कांग्रेस के लालच ने विभाजन की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया। उसने स्वतंत्र भारत को ऐसा नासूर दिया, जिसका दंश देश आज भी आतंकवाद, उग्रवाद व अलगाववाद के रूप में झेल रहा है, पर हमारा संकल्प वही है, जो महर्षि अरबिंद ने 1947 में विभाजन से पूर्व उद्घोषणा की थी। महर्षि ने कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या हमेशा के लिए उसका इतिहास मिट जाएगा। योगी ने कहा, यदि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने दृढ़ता दिखाई होती तो कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्तरूप नहीं दे पाती। कांग्रेस को जब भी अवसर मिला, उसने लोकतंत्र का गला घोंटा। नागरिकों ने जब भी अधिकारों की बात की तो कांग्रेस ने देश में भाषाई, क्षेत्रीय विवाद, हिंदुओं-सिखों को लड़ाने का पाप किया। जो गलतियां पहले हुई थीं, वही चुनाव के समय आज भी राजनीतिक दल करते हैं। वे जातीयता का नग्न तांडव कर उसी विभाजन की ओर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा-इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि गलतियों के परिमार्जन व गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेने का संकल्प भी होता है। जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विभाजन करने वाली ताकतों से सतर्क रहकर हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा। उधर, योगी के नेतृत्व में लखनऊ में 'विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा' निकाली गई।

पटना के होटल से सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड संग तीन हिरासत में

जागरण संवाददाता, पटना: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व बुधवार को पटना के होटलों की जांच कर रही कोतवाली थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। फ्रेजर रोड स्थित मगध होटल के कमरे से तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से सिपाही भर्ती परीक्षा के आठ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, दो ब्लैंक चेक, कुछ नकद, चेकबुक, मोबाइल, स्टांप पेपर आदि बरामद हुए। तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि वन विभाग के दारोगा विजय रजक ने एडमिट कार्ड और नकद के साथ बुलाया था। दारोगा के ठिकानों पर दबिश देने के लिए टीम रवाना हो चुकी है।

अररिया निवासी रामाशीष कुमार, प्रेम प्रकाश और नालंदा निवासी चंदन कुमार ने मगध होटल में कमरा बुक किया था। कोतवाली पुलिस वहां सुरक्षा जांच के लिए पहुंची। जांच के दौरान रामाशीष के बैग से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अलग-अलग अभ्यर्थियों के आठ एडमिट कार्ड मिले। एक कापी मिली, जिसमें अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ उनका पूरा विवरण था। रामाशीष ने बताया कि वन दारोगा विजय रजक ने सिपाही बनाने के लिए प्रति अभ्यर्थी सात लाख रुपयों की मांग की थी। उसी ने यहां बुलाया था। एडमिट कार्ड पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत अन्य शहरों के अभ्यर्थियों के हैं। दारोगा ने कहा था कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वह पूरी राशि लेगा।

जेल में बंद बिहार में पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने दो केस में किया बरी

विधि संवाददाता, जागरण ● पटना : पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की दो अपील याचिकाओं को स्वीकृति देते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। पहला मामला 24 जून, 2015 को पटना में उनके आवास से अत्याधुनिक इंसास रायफल, उसकी मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी से संबंधित है। उस प्रकरण में उन पर सचिवालय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

- आवास से इंसास रायफल की मैगजीन व एके-47 की गोलियां मिलने का मामला

न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने अनंत सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश जारी किया। दूसरा मामला उनके पैतृक घर से एके-47 रायफल, गोलियां और दो ग्रेनेड की बरामदगी से संबंधित है। दोनों अपील याचिकाओं पर अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने बहस की। राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) अजय मिश्रा ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि अनंत सिंह का अपने इलाके में काफी रसूख रहा है।

ग्रामीण बैंक कर्मी 1993 से पाएंगे पेंशन, एक लाख से ज्यादा को लाभ

जागरण संवाददाता, कानपुर

मिला हक

- 31 वर्ष की बकाया रकम के बड़े हिस्से का दीपावली से पूर्व करना होगा भुगतान
- सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को वित्त मंत्रालय के शपथ-पत्र के अनुरूप निर्देश दिए

ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को जल्द ही 1993 से पेंशन और कंप्यूटर वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान होगा। सुप्रीम कोर्ट में वित्त मंत्रालय द्वारा शपथ-पत्र दिए जाने के बाद कोर्ट ने 12 अगस्त को निर्देश जारी कर बकाये का बड़ा हिस्सा दीपावली से पहले देने को कहा है। शेष राशि का भुगतान मार्च 2025 तक करना होगा। याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर न्यायालय ने अवमानना वाद की सुनवाई बंद नहीं की है और अगली तारीख 21 अक्टूबर, 2024 तय की है। आदेश का लाभ 60 हजार लोगों को पेंशन के रूप में और 12 हजार को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। करीब 30 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।

ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 1975 में हुई थी। वर्तमान में देश में 43 ग्रामीण बैंक हैं। अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंक इनके प्रायोजक हैं। इन बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट 1993 से देने के लिए ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी न्यायालय में लगातार पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन देने का आदेश दिया था। आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरके मिश्रा और यूनाइटेड फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी के मुताबिक 1993 से पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट का बकाया देने के लिए कहा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2018 से इनके भुगतान का आदेश कर दिया।

ग्रामीण बैंक पेंशनर्स समितियों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में वित्त मंत्रालय में तत्कालीन सचिव राजीव कुमार के विरुद्ध अवमानना वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान नौ अगस्त, 2024 को वित्त मंत्रालय ने शपथ-पत्र दिया कि केंद्र सरकार ग्रामीण बैंक कर्मियों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन और कंप्यूटर इंक्रीमेंट नवंबर 1993 से देने को तैयार है। मंत्रालय के शपथ-पत्र के आधार पर न्यायालय ने 12 अगस्त 2024 को आदेश दिया कि बकाया के बड़े हिस्से का भुगतान दीपावली से पहले करें और बाकी भुगतान मार्च 2025 तक करें।

श्री राम लला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज को अमेरिकी वीजा देने से इन्कार

मैसुरु, आइएएनएस : अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्रतिष्ठित श्री राम लला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार मैसुरु निवासी अरुण योगीराज को चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने वीजा देने से मना कर दिया है। यही नहीं, योगीराज के परिवार के सदस्यों को भी वीजा देने से मना कर दिया गया है।

योगीराज ने अक्का फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने व विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अमेरिकी यात्रा के लिए वीजा आवेदन किया था। उन्होंने 20 दिनी यात्रा की योजना बनाई थी। हालांकि, अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने वीजा देने से इन्कार करने का कोई खास कारण भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि योगीराज ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। उधर, योगीराज ने कहा कि उन्हें अमेरिका में अक्का फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। इसी वजह से सपरिवार अमेरिका के लिए वीजा लगाया था। उन्होंने कहा कि मैंने निमंत्रण कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा करा दिए थे। हमारा परिवार तय अप्वाइंटमेंट के अनुसार वीजा लेने के लिए चेन्नई गया था। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने कुछ सवाल पूछे और बाद में हमें पता चला कि हमें वीजा देने से मना कर दिया गया है।

अयोध्या में लाइटें चोरी होने की दर्ज कराई झूठी एफआइआर, संस्था पर होगा केस

जागरण संवाददाता, अयोध्या

- कार्यदायी संस्था ने दर्ज कराई थी फैंसी लाइटें चोरी होने की रिपोर्ट
- प्रशासन ने कहा-ज्यादा भुगतान लेने के लिए कराई थी प्राथमिकी

रामपथ के किनारे स्थित पेड़ पर लगायी गयी बैंबू लाइट। जागरण आर्काइव

श्रीराम जन्मभूमि जाने वाले रामपथ एवं हनुमानगढ़ी जाने वाले भक्तिपथ पर लगवाई गई फैंसी लाइटों के चोरी होने के प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। जांच में पता चला है कि कार्यदायी संस्था ने ज्यादा भुगतान लेने के लिए एफआइआर में लाइटों की संख्या 3800 लिखाई, जबकि सरकारी रिकार्ड के मुताबिक 2600 लाइटें ही लगवाई गई थीं। इस रहस्योद्घाटन के बाद प्रशासन कार्यदायी संस्था मेसर्स यश इंटरप्राइजेज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाएगा।

अयोध्या के मंडलायुक्त और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गौरव दयाल ने बताया कि लाइट लगाने वाली संस्था ने फर्जी भुगतान प्राप्त करने के लिए गलत एफआइआर कराई है। विकास प्राधिकरण की ओर से संबंधित संस्था के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। अयोध्या में पेड़ों पर केवल 2600 बैंबू लाइट ही लगाई गई हैं। जिन 3800 लाइट चोरी होना बताया जा रहा है, वो लगाई ही नहीं गईं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के कराए गए सत्यापन में यह बात सामने आई है कि संस्था ने अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बचाव व पेशबंदी में झूठी रिपोर्ट लिखाई है।

गौरतलब है कि कार्यदायी संस्था मेसर्स यश इंटरप्राइजेज और कृष्णा आटो मोबाइल के प्रतिनिधि शेखर शर्मा ने नौ अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि फर्म ने रामपथ पर 6400 बैंबू लाइट (पेड़ों पर लटकाने वाली) और भक्तिपथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें (खंभों पर लगने वाली) लगाई गई हैं। इनमें से 3800 बैंबू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी होने का उल्लेख है।

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दावा : अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी पांडेय ने कहा कि संबंधित फर्म के माध्यम से कुल 2600 बैंबू लाइटें लगवाई गई हैं, जिसका 23 लाख, 35 हजार रुपये भुगतान किया जा चुका है। इसी क्रम में स्थापित की जा चुकी कुल 96 गोबो प्रोजेक्ट लाइटों का 38 लाख, 74 हजार रुपये भुगतान हुआ है। संस्था ने झूठी एफआइआर करवाई है।

अखिलेश बोले, अयोध्या में चोरों ने की कानून-व्यवस्था की बत्ती गुल : लाइटें चोरी होने की घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अयोध्या में चोरों ने की कानून-व्यवस्था की बत्ती गुल। इसीलिए जनता तो पहले ही कह रही थी, बिन बिजली के खड़ा है खंभा। उन्होंने यह भी लिखा कि भाजपा सरकार मतलब अंधेर नगरी, सब तरफ अंधकार।'

सार्थक कदम

मध्य प्रदेश में है 25 चीते, 785 बाघ, गांधी सागर अभयारण्य के लिए अलग से लाए जाएंगे चीतें

मप्र-राजस्थान मिलकर करेंगे चीतों व बाघों का संरक्षण

सौरभ सोनी, नईदुनिया.

भोपाल: मध्य प्रदेश में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया से लाए गए चीतों ने राज्य की जलवायु को अपना लिया है और अब वे राजस्थान में नया आशियाना तलाश रहे हैं। इसके साथ ही चीतों की सुरक्षा की चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए मप्र सरकार को पत्र लिखकर संयुक्त प्रयास से चीतों व बाघों की सुरक्षा की बात कही है। सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को चीतों के प्रति जागरूक किया जाएगा। चीतों के मूवमेंट पर नजर रखकर उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे।

पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर 2022 को मप्र के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए थे। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से आठ चीते और दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को 12 चीते लाए गए थे। इनमें से कुछ चीतों की मौत हो गई। विशेषज्ञों के तमाम दावों के बीच चीतों ने यहां सर्वाइव किया और शावकों को भी जन्म दिया। वर्तमान में कूनो में 13 वयस्क चीता व 12 शावक हैं। अब चीतों को जल्द ही खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी है। इससे पहले खुले जंगल में छोड़ा गया चीता पवन कूनो की सरहद लांघ कर राजस्थान चला गया था। इसी के दृष्टिगत अब दोनों राज्यों की सरकारें संरक्षण की साझा पहल करने जा रही हैं। ज्ञात हो, मप्र में गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के नए आशियाने के रूप में तैयार कर लिया गया है। यहां भी जल्द ही चीतों को बसाया जाएगा। इसी तरह मप्र में बाघों की संख्या 785 हो गई है, जो देश में सर्वाधिक है।

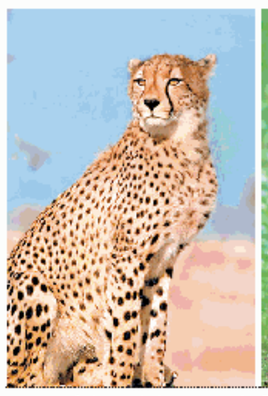

ऐसे बढ़ी प्रदेश में बाघों की संख्या	
वर्ष	बाघों की संख्या
2006	300
2010	257
2014	308
2018	526
2022	785
मप्र में चीते	
वयस्क	13
शावक	12

चीतों-बाघों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए राजस्थान सरकार ने मप्र सरकार को पत्र लिखा है। जल्द ही राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। -शुभरंजन सेन, वन्य प्राणी अभिरक्षक, मप्र वन

कूनो में चीता सफारी शुरू करने की तैयारी में सरकार

कूनो नेशनल पार्क के बाड़े से चीतों को खुले जंगल में छोड़ने के साथ ही सरकार चीता सफारी शुरू करने पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया है। इसके पीछे मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की मुख्य वजह बताई गई है। चीता स्टीयरिंग कमेटी भी चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने को जरूरी बता रही है। अन्यथा बाड़ों में रहकर वह अपना प्राकृतिक व्यवहार और शिकार के लिए मेहनत करना भूल सकते हैं या आलसी हो सकते हैं।

पाक महिला से निकाह करने वाला राजस्थान का आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर

- पहली पत्नी को दिया तीन तलाक, पत्नी ने थाने में दर्ज कराया था मामला, कुवैत से लौटते ही गिरफ्तार

पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले राजस्थान के चूरू जिले के निवासी रहमान खान को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुवैत से लौटते ही रहमान को जयपुर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। रहमान के खिलाफ उसकी पहली पत्नी फरीदा बानो ने मोबाइल पर तीन तलाक देने और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने रहमान के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था।

पुलिस उप अधीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि फरीदा ने थाने में पति रहमान पर मोबाइल पर तीन तलाक देने देवर, ननद, सास और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया था। तीन तलाक व दहेज प्रताड़ना मामले में रहमान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फरीदा बानो की 17 मार्च, 2011 को चूरू निवासी रहमान के साथ निकाह हुआ था। इसके बाद उनके एक बेटा व एक बेटी हुई। फिर रहमान कुवैत जाकर रहने लगा। वह वहां व्यापार करता है। करीब एक साल पहले रहमान की पाकिस्तान की महिला मेहविश से इंटरनेट मीडिया पर बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने निकाह कर लिया। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद फरीदा ने रहमान के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। फरीदा ने रिपोर्ट में बताया कि मेहविश पिछले महीने पर्यटन वीजा पर चूरू भी आई थी।

आतंकी गतिविधियों से निपटने की व्यवस्था चाक चौबंद करें : राजनाथ

रक्षा मंत्री ने सेना, सुरक्षा-खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों संग की बैठक

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए जवाबी रणनीति पर की गहन मंत्रणा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। जम्मू क्षेत्र में हाल के महीनों में बढ़ी आतंकी घटनाओं ने खुफिया तंत्र की ही नहीं, केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। समझा जाता है कि इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री ने सेना और सुरक्षा बलों को आतंकी गतिविधियों की चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय पहल करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए।

जम्मू के डोडा इलाके में आतंकियों के खिलाफ जारी सैन्य आपरेशन के बीच रक्षा मंत्री ने सूबे के सुरक्षा हालात को देखते हुए जवाबी कारगर रणनीति पर गहन मंत्रणा की। इस बैठक में

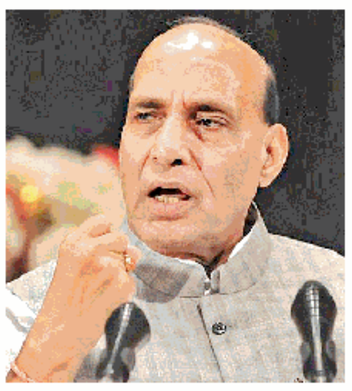

राजनाथ सिंह। फाइल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सैन्य अभियानों के महानिदेशक-लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, खुफिया एजेंसी आइबी के प्रमुख के साथ कुछ अन्य अति गोपनीय खुफिया तंत्र से जुड़े शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले डोडा जिले में आतंकी हमले में सेना के एक कैप्टन के बलिदान होने की घटना सुरक्षा बलों पर हमले में इजाफे की गंभीरता की ओर इशारा कर रही है।

समझा जाता है कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 10 अगस्त को अनंतनाग में दो सैनिकों और एक नागरिक के बलिदान होने से लेकर कठुआ में सेना के काफिले पर हमला, डोडा और उधमपुर की मुठभेड़ जैसी घटनाओं की समीक्षा भी हुई।

सुरक्षा बलों पर हमले के विशेष पैटर्न का भी आकलन

सीमा पार से जम्मू इलाके में सुरक्षा बलों पर हमले के विशेष पैटर्न का भी आकलन किया जा रहा है। बताया गया है कि रक्षा मंत्री ने बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से कहा कि वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के साथ ही प्रोएक्टिव पहल कर इनके इरादों को विफल करने की जरूरत है। इस दृष्टि से यह भी जरूरी है कि जम्मू ही नहीं श्रीनगर घाटी में भी सुरक्षा गैप की पहचान कर इसे चुस्त-दुरुस्त किया जाए। खुफिया एजेंसियों को लोकल इंटेलीजेंस के प्रवाह को मजबूत और अधिक गतिशील बनाने के निर्देश दिए गए।

लखनऊ पीजीआइ की डाक्टर को सात दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.81 करोड़ हड़पे

जागरण संवाददाता, लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) की डा. रुचिका टंडन को मनी लांड्रिंग और मानव तस्करी केस में फंसाने के नाम पर जालसाजों ने सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान उनके बैंक खातों से 2.81 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए। साइबर पुलिस ने मामले की प्रथमिकी दर्ज कर एक खाता ट्रेस करते हुए उसमें ट्रांसफर कराए गए 27.88 लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, डाक्टर के पास एक अगस्त को फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी आफ इंडिया का कर्मचारी बताया और कहा,आपके सिम पर कई शिकायतें हैं। अतः नंबर बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद कहा, अब आपसे सीबीआइ अधिकारी राहुल यादव बात करेंगे। अधिकारी बने ठग ने डाक्टर से कहा, जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मनी लांड्रिंग केस तथा महिलाओं और बच्चों की तस्करी के मामले में आपके खातों का इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया है, पर अभी आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आपको प्रापर्टी का पूरा विवरण देना है और पूरा पैसा सरकारी खातों में जमा कराना है ताकि जांच हो सके। इसके बाद ठग ने अलग-अलग बैंकों के सात खातों के नंबर डाक्टर को भेजे। डा.रुचिका इतना डर गई थीं कि जालसाजों के बताये खातों में रुपये ट्रांसफर कर दिए।

वायनाड में भूस्खलन के लिए जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई भारी बारिश जिम्मेदार

- भारत, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के 24 अनुसंधानकर्ताओं ने किया अध्ययन
- केरल में दो सप्ताह पहले हुए भूस्खलन में 231 लोगों की चली गई थी जान

नई दिल्ली, प्रेट्र : केरल के वायनाड में दो हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के लिए भारी बारिश जिम्मेदार थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण 10 प्रतिशत की तेजी आई है। भारत, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के 24 अनुसंधानकर्ताओं के हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई।

अध्ययन के मुताबिक, वायनाड में करीब दो माह की मानसूनी बारिश के चलते पहले से ही अत्यधिक नम मिट्टी पर एक ही दिन में 140 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। इससे क्षेत्र विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गया और 231 लोगों को जान गंवानी पड़ी। रेड क्रास रेड क्रिसेंट क्लाइमेट सेंटर में जलवायु जोखिम सलाहकार माजा वाहलबर्ग ने कहा- 'भूस्खलन का कारण बनी बारिश वायनाड के उस क्षेत्र में हुई, जो भूस्खलन के लिहाज से सबसे संवेदनशील माना जाता है। जैसे-जैसे जलवायु गर्म हो रही है और भी अधिक भारी बारिश की आशंका बढ़ रही है।'

मानव जनित कारणों से होने वाले जलवायु परिवर्तन का असर आंकने के लिए वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (डब्ल्यूडब्ल्यूए) के अनुसंधानकर्ताओं ने बेहद उच्च रेजोल्यूशन वाले जलवायु माडल का विश्लेषण किया ताकि अपेक्षाकृत छोटे अध्ययन क्षेत्र में बारिश के स्तर का अंदाजा लगाया जा सके। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि

वायनाड में प्राकृतिक आपदा के बाद वहां पहुंचे अभिनेता मोहनलाल। फाइल

जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अध्ययन में शामिल माडल यह अनुमान भी लगाते हैं कि अगर वैश्विक तापमान वृद्धि 1850 से 1900 तक के औसत तापमान से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है तो बारिश की तीव्रता में चार प्रतिशत और वृद्धि हो सकती है। गर्म वातावरण में आर्द्रता का स्तर अधिक होता है, जो भारी बारिश का कारण बनता है। वैश्विक तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से वातावरण में नमी को कैद करने की क्षमता सात प्रतिशत बढ़ जाती है। कार्बन डाइआक्साइड,मीथेन जैसी गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से पृथ्वी की सतह का औसत तापमान पहले ही लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। विज्ञानियों का कहना है कि दुनियाभर में बाढ़, सूखा और लू जैसी मौसमी घटनाओं में वृद्धि के पीछे यही कारण है। वायनाड में बढ़ते खनन और जंगलों के दायरे में 62 प्रतिशत की कमी जैसे कारकों ने भारी बारिश के दौरान पहाड़ों को भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है।

अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी जंगलों की कटाई, संवेदनशील पहाड़ियों में खनन व आर्द्रता का स्तर अधिक होने के कारण लंबे समय तक बारिश जैसे कारकों को वायनाड में भूस्खलन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उन्नत वायुमंडलीय रडार अनुसंधान केंद्र के निदेशक एस अभिलाष ने बताया कि अरब सागर के गर्म होने से घने बादलों का निर्माण हो रहा है, जिससे केरल में कम अवधि में अत्यधिक भारी बारिश हो रही है और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ज्ञात हो, भारत में भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील 30 जिलों में से 10 केरल में हैं। वायनाड 13वें स्थान पर है।

आइएमडी का वायनाड के लिए आरेंज अलर्ट : आइएमडी ने वायनाड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें गुरुवार को वायनाड व कोझीकोड में 24 घंटे में सात से 20 सेमी की भविष्यवाणी की है। इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पी.विजयन ने भारी भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को छह-छह लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की।

न्यूज गैलरी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात की

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर तस्वीर साझा कर इस भेंट की जानकारी दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पदभार संभालने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार राष्ट्रपति से मुलाकात की। इससे पहले, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। (प्रेट्र)

इंडिगो ने 77 महिला पायलट को कंपनी में शामिल किया

नई दिल्ली : एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने एयरबस और एटीआर विमानों के लिए बुधवार को 77 महिला पायलटों को शामिल किया है। साथ ही एयरलाइन कंपनी में 800 से ज्यादा महिला पायलट हो गई हैं। एयरलाइन ने कहा,देश की स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एयरबस बेड़े में 72 महिला पायलटों और एटीआर बेड़े में पांच महिला पायलटों को शामिल किया जाना एक मील का पत्थर है। (प्रेट्र)

त्रिपुरा में फर्जी आधार कार्ड के साथ 10 बांग्लादेशी पकड़े गए

अगरतला : सीमा सुरक्षा बल, मानव तस्करी विरोधी टीम व खुफिया इकाई ने मंगलवार को फर्जी आधार कार्ड से अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। यह तलाशी अभियान बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए विशेष रूप से चलाया गया था। इनपुट के आधार पर पश्चिम त्रिपुरा के अमताली और डुकली के सामान्य क्षेत्र में टीमों द्वारा संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। (एएनआइ)

17 भारतीय मछुआरे भारत वापस आये

कोलंबो : श्रीलंका नौसेना द्वारा अपने जलक्षेत्र में अवैध शिकार करने के आरोप में पकड़े गए 17 भारतीय मछुआरों को बुधवार को भारत वापस भेज दिया गया। बुधवार को श्रीलंका में भारतीय मिशन ने सभी मछुआरों की तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया कि अपने घर जा रहे हैं! 17 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से सफलतापूर्वक वापस लाया गया है। (प्रेट्र)

लाल चौक पर जगमगाती तिरंगी रोशनी

पूरा देश 78वें स्वतंत्रता दिवस के स्वागत को तैयार है। ऐसे में जम्मू- कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर महत्वपूर्ण इमारत को तिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है। इस कड़ी में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को श्रीनगर के लाल चौक को भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगा किया गया। प्रेट्र

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चिंता का विषय : विश्वप्रसन्न तीर्थ

उडुपी, प्रेट्र : कर्नाटक के उडुपी पेजावर मठ के वरिष्ठ संत विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामीजी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे रोकने के लिए सामूहिक जागरूकता तथा धार्मिक जगत के हस्तक्षेप का आह्वान किया।

स्वामीजी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें न केवल बांग्लादेश में बल्कि भारत में भी हिंदुओं की खराब होती स्थिति की निंदा की गई। उन्होंने हिंदू समुदाय को इन चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस प्रकार की स्थितियों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के बढ़ते चलन को रेखांकित किया। इसके साथ ही समाज को सतर्क रहने और अन्याय का मुकाबला करने के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि पड़ोसी देश में सरकार के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन हिंदुओं पर हमले का जरिया बन गए हैं।

तकनीकी समस्या के कारण बीच रास्ते से लौटा लंदन जा रहा विमान

- 354 यात्री थे सवार, विमान को मुंबई में सुरक्षित उतारा गया
- गोवा से मुंबई जा रहा एक अन्य विमान पक्षी से टकराया

मुंबई, प्रेट्र : एअर इंडिया का लंदन जा रहा विमान केबिन में दबाव की समस्या के कारण बीच रास्ते से वापस मुंबई लौट आया। उस पर 354 लोग सवार थे। एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ-129 बुधवार सुबह रवाना हुई थी। फ्लाइट सुबह 8.36 बजे मुंबई से रवाना हुई और 11.30 बजे लौट आई। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई। टिकट रद्द किए जाने पर पूर्ण रिफंड और किसी अन्य तिथि के लिए पुनर्निर्धारण की भी पेशकश की गई।

वहीं, दूसरी ओर बुधवार सुबह गोवा से मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ684 के टेक आफ के दौरान पक्षी के टकरा जाने के बाद उड़ान रोकना पड़ा। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार उड़ान रोकी थी। सभी यात्री सुरक्षित रूप से उतर गए। विमान को आवश्यक निरीक्षण के लिए भेज दिया गया। यात्रियों को

गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

हाइड्रोलिक समस्या के कारण विस्तारा के विमान की आपात लैंडिंग : दिल्ली से मुंबई जा रहे विस्तारा के विमान में हाइड्रोलिक संबंधी तकनीकी समस्या आने पर उसकी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इस पर 167 यात्री सवार थे। एयरलाइन ने कहा कि लैंडिंग से कुछ देर पहले विमान में तकनीकी समस्या का पता चला। एहतियाती कदम उठाते हुए इसकी लैंडिंग कराई गई।

हाथरस की तीन ग्राम पंचायतों में बने कई राज्यों के 2900 फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र

जागरण संवाददाता, हाथरस

- डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने गठित की जांच कमेटी

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में ग्राम पंचायतों में बनने वाले जन्म प्रमाण-पत्रों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जिले की तीन ग्राम पंचायतों से 2900 फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र बनाए गए हैं। उप्र के साथ ही हरियाणा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के लोगों ने भी यहां से प्रमाण-पत्र बनवाए हैं। एक जनवरी 2022 से अब तक प्रमाण-पत्र जारी किए गए। ग्राम पंचायत सचिव की यूजर आइडी हैक कर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। डीएम के निर्देश पर पांच सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। पंचायत सचिव ने पुलिस को तहरीर दी है। सभी ग्राम पंचायतों का डेटा जांचा जा रहा है। फर्जी प्रमाण-पत्रों की संख्या बढ़ सकती है।

जिले की 31 पंचायतों के नए आइडी और पासवर्ड बने हैं। इनमें ही सिचावली सानी, बीजलपुर और रहपुरा भी शामिल हैं। फर्जीवाड़े का राजफाश हसायन ब्लाक की ग्राम पंचायत सिचावली सानी से हुआ है। इस गांव की आबादी करीब 1100 है। यहां के सचिव ईश्वरचंद को सीआरएस (नागरिक पंजीकरण प्रणाली) आइडी तीन अगस्त को जारी हुई। उन्होंने इसे खोलकर देखा तो पता लगा कि इस आइडी से 2022 में 984 और एक जनवरी 2023 से अब तक 814 जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी सुबोध जोशी को सूचना दी। आइडी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग में भी शिकायत दी। डीएम के आदेश पर पंचायत राज विभाग ने जिले की सभी पंचायतों का डाटा खंगालना शुरू किया। इस पर सादाबाद के ग्राम पंचायत बीजलपुर में 700, रहपुरा में 400 फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी होना पाया गया। डीएम आशीष कुमार का कहना है कि ग्राम पंचायत से फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी होने की मामला सामने आया है। यह गड़बड़ी कैसे हुई, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई है।

ई-कामर्स कंपनियों के फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाले काल सेंटर का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, नोएडा

- तीन मास्टरमाइंड समेत गिरोह के 21 लोग किए गिरफ्तार
- एक हजार लोगों से कर चुके हैं एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी

कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आरोपित। जागरण

पुलिस ने नामी ई-कामर्स कंपनियों के माध्यम से सामान बेचने का झांसा देकर फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाले काल सेंटर का पर्दाफाश किया है। गिरोह के तीन मास्टरमाइंड समेत 21 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें 16 पुरुष एवं पांच महिलाएं हैं। आरोपितों के पास से 12 डेस्कटाप, 12 लैपटाप एवं 28 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपित ढाई वर्ष से किराये की एक बिल्डिंग ठकी की बारदात को कर रहे थे। आरोपित अब तक करीब एक हजार लोगों से एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुके हैं।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सेक्टर-63 स्थित इन्फोबीम साल्यूशंस कंपनी नामी ई-कामर्स कंपनियां नायका, ईबे, मिंत्रा, इंटसे आदि के नाम से जाली सर्टिफिकेट बनाकर विक्रेताओं के साथ धोखाधड़ी कर रही थी। ठगी का शिकार हुए श्रुति चौधरी, रश्मि गर्ग, अनुज तिवारी, यशा तैमूरी ने पुलिस को सूचना दी। सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता के संबंध में संबंधित ई-कामर्स कंपनियों को ईमेल भेजकर जानकारी मांगी गई तो नामी कंपनियों ने कोई भी सर्टिफिकेट जारी करने से इन्कार किया। इस कंपनी को अपना अधिकृत पार्टनर नहीं बताया।

पुलिस जब कंपनी में पहुंची तो वहां नामी ई-कामर्स कंपनियों के फर्जी सर्टिफिकेट फ्रेम दीवारों पर लगे मिले। आरोपित आने वाले व्यक्तियों को इन्हीं सर्टिफिकेट को दिखाकर झांसे में लेते थे। ई-कामर्स प्लेटफार्म पर सामान बेचने के नाम पर फीस के रूप में 15 से 20 हजार रुपये लेते थे। बाद में उन लोगों का सामान नामी ई-कामर्स साइट पर प्रसारित करते थे।

एनसीआर के बाहर रहने वाले लोगों को बनाते थे निशाना : डीसीपी का कहना है कोई अपना पैसा वापस मांगने के लिए इन पर दबाव न डाले, इसलिए आरोपित अधिकांश रूप से एनसीआर के बाहर के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। सभी फर्जी सर्टिफिकेट एवं अन्य डाटा ठग कंपनी के निदेशक जोगेन्द्र, गुंजन कात्याल व आकाश शर्मा द्वारा तैयार कर अपने कर्मचारियों को भेजा जाता था। फिर काल सेंटर के कर्मचारी विक्रेता को फोन करके फर्जी सर्टिफिकेट वाट्सएप पर भेजकर प्रलोभन देकर ठगी करते थे। ठगी का पैसा आपस में बांटते थे। बाकी कर्मचारियों को 10 से 15 हजार रुपये के प्रतिमाह के वेतन पर रखा गया था। इनका काम विक्रेता को फोन करके साथ इंटरनेट मीडिया फेसबुक, वाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम के माध्यम से झांसे में लेना था।

उप्र, दिल्ली, बिहार, राजस्थान व हिमाचल के रहने वाले हैं ठग : आरोपितों की पहचान मुजफ्फरनगर के जोगेंद्र कुमार, औरैया के गोपाल सक्सेना, मथुरा के रेयांश शर्मा, सहारनपुर के अखिल गर्ग, गाजियाबाद के आकाश शर्मा, निशांत, आकाश यादव, मुकुल त्यागी, पूर्ति, बुलंदशहर के रवि कुमार, लोकेश चौधरी, संभल के प्रदीप कुमार, अमरोहा की गुंजन चौहान, बिसरख के कार्तिक मिश्रा, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अनिल कुमार, कैमूर (बिहार) के पंकज उपाध्याय, झुंझुनू (राजस्थान) के हिमांशु शर्मा, दिल्ली के सरस भारद्वाज, गुंजन कात्याल, स्वीटी व लखनऊ की मोनिका वर्मा के रूप में हुई है।

स्वतंत्रता के सारथी

गंगा तट पर गुरुजन शिक्षा संग सहेज रहे संस्कारों की पाठशाला

कानपुर में शिक्षाविदों का समूह नई पीढ़ी में विकसित कर रहा सांस्कृतिक मूल्य व देशोत्थान का ज्ञान

विवेक मिश्र ● जागरण

कानपुर: शिक्षा के साथ यदि संस्कारों और देशोत्थान का ज्ञान भी मिल जाए तो नई पीढ़ी के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़ता है। इसी तरह का प्रयास कानपुर में शिक्षाविदों का समूह कर रहा है, जो गंगा के उस पार गांवों में बसे बच्चों के लिए 'घाट वाला स्कूल' संचालित कर शिक्षा संग संस्कारों की थाती भी सहेज रहा है। ये शिक्षक गंगा नदी के तट पर स्थित स्कूल में निषाद समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने और सांस्कृतिक मूल्य विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस पहल को एक नई राह फाउंडेशन पल्लिवत कर रहा है।

रचनात्मक गतिविधियों से संस्कृति से परिचय: डीसी ला कालेज की प्राचार्या व छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में फैकल्टी आफ ला की डीन रहीं डा. नंदिनी उपाध्याय, कान्यकुब्ज पब्लिक स्कूल, मालरोड की प्रिंसिपल पूजा सहगल व विधि छात्र नितिन व उनकी टीम परमट के समीप गंगा के तट पर प्रतिदिन शाम 224 बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल-खेल में नाटक मंचन, प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी, रंगोली, चित्रकला सहित अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से महापुरुषों की जीवनी, देश की संस्कृति व देश के उत्थान से संबंधित विषयों के बारे में अवगत कराते हैं।

नौ वर्ष पहले बनाई संस्था: घाट वाला स्कूल में शिक्षक की भूमिका निभा रहे नितिन बताते हैं कि जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही नई पीढ़ी सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित रहे, इसके लिए विशेष प्रयास होते हैं। इसी उद्देश्य से 2015 में 'एक नई राह फाउंडेशन' की शुरुआत हुई। यही संस्था स्कूल का खर्च व व्यवस्था संभालता है। सामाजिक सहयोग भी प्राप्त होता है।

बस नहीं, यह है नाव वाला स्कूल

घाट वाला स्कूल की प्रिंसिपल पूजा सहगल बताती हैं कि गंगा पार से आने वाले बच्चों को सड़क मार्ग से काफी दूर से घूमकर आना पड़ता था। बच्चों के पास किराया न होने से आवागमन में समस्या आ रही थी, इसलिए फाउंडेशन के सहयोग से बच्चों के लिए नाव खरीदी गई। प्रतिदिन शाम चार से छह बजे के बीच नाव के माध्यम से बच्चे घाट वाला स्कूल में पहुंचते हैं।

नाव के माध्यम से गंगा पार से पढ़ने के लिए आते बच्चे।

परमट के समीप घाट वाला स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे ● एक नई राह फाउंडेशन

कंप्यूटर की भी दे रहे शिक्षा, बना रहे जिम्मेदार नागरिक

डा. नंदिनी बताती हैं कि बच्चों को आनलाइन शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर भी खरीदे गए हैं। कभी नाम न लिख पाने वाली बेटियां अब स्नातक की पढ़ाई करने के साथ घाट वाला स्कूल में पढ़ाकर योगदान कर रही हैं। वह बताती हैं कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत जीवंत है। ये दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों को आश्चर्यचकित करती है। विरासत के संरक्षण में योगदान देना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस भाव से देश के भावी कर्णधारों को नई राह फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है।

घाट वाला स्कूल में कंप्यूटर पर आनलाइन प्रशिक्षण लेते बच्चे।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

इंजीनियरिंग के दो लाख छात्रों को इस साल मुहैया कराई जाएगी वर्चुअल इंटर्नशिप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एआइसीटीई और एडुस्किल्स फाउंडेशन ने एंसिस, मिडास जैसी कंपनियों के साथ किया करार
- इस पहल को सरकार द्वारा युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा

इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब नौकरी के लिए भटकना नहीं होगा। ऐसे छात्रों की मदद के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) और एडुस्किल्स फाउंडेशन ने आइटी सहित इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों संग मिलकर वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का एलान किया है। जिसमें दो लाख छात्रों को वर्चुअल इंटर्नशिप दी जाएगी। इस पहल को सरकार की ओर से बजट में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। एआइसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम ने बुधवार को इस प्रोग्राम का लांच किया। साथ ही कहा कि इस पहल से छात्रों को उद्योगों से जुड़े अनुभव और उनकी क्षमता के विकास में मदद मिलेगी। साथ ही पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके लिए नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस बीच छात्रों को वर्चुअल इंटर्नशिप मुहैया कराने के लिए आइटी सहित इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी एंसिस, मिडास व वाधवानी फाउंडेशन जैसी कंपनियों के साथ करार किया है। वर्चुअल इंटर्नशिप के यह अवसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ईई), इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (ईईई), मैकेनिकल, आटोमोबाइल, एयरोस्पेस और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी दी जाएगी।

****

दैनिक जागरण

आजादी से मिले अधिकारों में कर्तव्य भाव भी निहित होता है

और सुगम हो राष्ट्र निर्माण का पथ

गिरीश्वर मिश्र

भविष्य हमारा है, पर तभी जब हम अपने हिस्से के दायित्वों का निर्वाह करते हुए नए भारत के निर्माण में समुचित सहयोग करेंगे

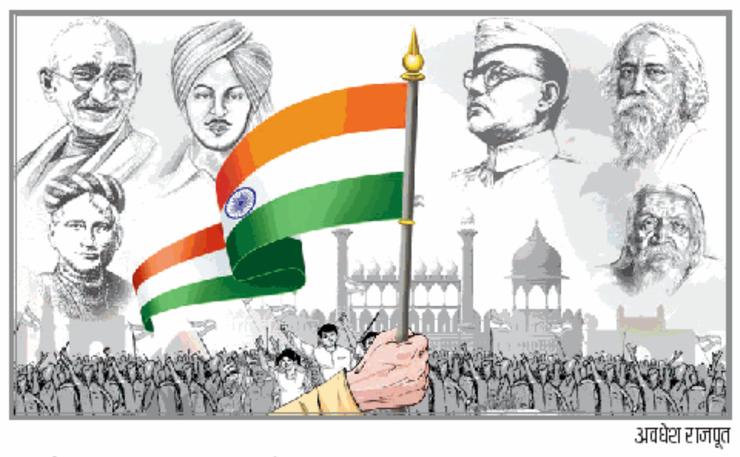

अवधेश राजपूत

देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम यह उत्सव बना रहे हैं तो इसके पीछे अनेक समर्पित नेताओं, किसानों और युवाओं की निष्ठा है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निःस्वार्थ रूप से लोकतंत्र की भावना को अपने खून-पसीने से सींचा था और अनेक युवा क्रांतिवीरों ने प्राणों की आहुति दी थी। वे भिन्न-भिन्न पंथों, जातियों, क्षेत्रों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, किंतु सब एक देश की भावना के प्रति समर्पित थे। स्वाधीनता दिवस उन सभी का स्मरण करते हुए नमन करने का भी अवसर है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने एक सशक्त लोकतंत्र की नींव रखी। ऐसे में यह संयोग मात्र नहीं है कि भारत में लोकतंत्र न केवल सुरक्षित एवं समृद्ध हुआ है, बल्कि वह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह तथ्य आज की तारीख में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि पड़ोसी देश एक-एक कर लोकतंत्र से विमुख हो रहे हैं। वहां अराजकता के चलते घोर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पनप रहा है। बांग्लादेश की घटनाएं बता रही हैं कि वहां किस तरह चुनी हुई सरकार और प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया।

आज अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर चहुंओर उथल-पुथल है। इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में भी असंतोष की भावनाएं उबल रही हैं। इस दृष्टि से यह बड़ी बात है कि भारी विविधताओं और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत न केवल लोकतंत्र को संभालने में सफल रहा, बल्कि यहां यह और सुदृढ़ हुआ है। इसके दम पर भारत एक समर्थ अर्थव्यवस्था के साथ विकसित देश बनने की तैयारी कर रहा है। यदि आपातकाल के दुर्भाग्यपूर्ण दौर को छोड़ दें तो जनतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें ही भारत में सत्ता संभालती रहीं। फिर चाहे वह अकेली पार्टी की सरकार हो या मिली-जुली। जनता ने सबका स्वागत किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया। आपसी समझदारी और भरोसे के साथ देश की यात्रा चलती रही। यह आगे और सुगमता से और तीव्र गति से चले, इसकी चेष्टा सबको करनी चाहिए। आज देश अंतरिक्ष विज्ञान जैसे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है तो साथ ही स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर है। समाज के हाशिए पर स्थित लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस सबके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक है।

पंद्रह अगस्त, 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और यहां तक पहुंचने के पहले कई नेताओं को शासन चलाने का अभ्यास मिला। नौकरशाही, कानून-व्यवस्था, शिक्षा-व्यवस्था और लोकतांत्रिक रीति-नीति का अच्छा-बुरा जो ढांचा अंग्रेजों ने औपनिवेशिक भारत के लिए बनाया था, वह रेडीमेड तैयार था। उसे ही स्वतंत्र भारत के लिए आधार बनाया गया। अंग्रेजी चाल-ढाल वाला साहबी ठाट-बाट, शौक और रुतबे की छवि मन में बसी हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता और लोकतंत्र का विचार कम और राजसी प्रतीकों और ताम-झाम को बनाए रखने के उपाय अधिक किए जाते रहे। इनमें स्वराज और जनसेवा का विचार पृष्ठभूमि में खोता चला गया। यह कड़वी सच्चाई है कि जन-सेवा से जिन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया, वे शीघ्र ही उसे भूल गए और आंखें मूंद कर सिर्फ धन-संपदा कमाने में जुट गए। राजनीति एक व्यवसाय या धंधा बनता गया, जिससे बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता था। अनेक नेताओं की संपदा जिस तरह तीव्र गति से बढ़ी, वह अकल्पनीय है। उनमें आय से अधिक संपत्ति के मामले आम हैं। चाहे कुछ पकड़े गए हों या नहीं। राजनीति का व्यापारीकरण भी होता गया। वोट पाने, समर्थन जुटाने और अपनी बात चलाने के लिए सौदेबाजी सामान्य सी बात हो गई। अधिकांश दलों और नेताओं के लिए विचारधारा का कोई मूल्य-महत्व नहीं रह गया है। आम चुनावों में सैकड़ों करोड़ की जब्ती होती है और जो पकड़ में नहीं आता, उसकी तो बात ही नहीं। चूंकि अपराध सिद्ध करना लगभग असंभव सा कानूनी खेल है अतः तमाम नेता जमानत लेकर राजनीति में सक्रिय रहते हैं। एक किस्म के दायित्वहीन नेताओं की भीड़ जमा होती जा रही है, जिन्हें देश, समाज और संस्कृति किसी की भी चिंता नहीं है। वे सिर्फ अपने, अपने परिवार और अपनी पार्टी का ही भला देखते हैं।

बीते दिनों ऐसा बहुत कुछ हुआ, जो देश के लिए शर्मनाक है। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर कई छोटे-बड़े नवनिर्मित से लेकर निर्माणाधीन कई पुल ध्वस्त होकर जलमग्न हो गए। रेल की कई दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें जान-माल की बड़ी क्षति हुई। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जलभराव से विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। लाखों छात्र नीट और नेट की परीक्षा की गड़बड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर त्रस्त हुए। हाथरस में एक आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंची भीड़ कुछ इस तरह अनियंत्रित हुई कि सौ से अधिक लोगों को 'मुक्तिदायी गुरुचरणरज' लेने में अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। पहाड़ों पर पहले जंगल की आग ने बहुत बड़ा हरित क्षेत्र स्वाहा किया और अब तीव्र वर्षा सड़क और घर सबको तहस-नहस कर रही है। तिस पर सरकार जनता को यह 'ज्ञान' देती रहती है कि इन सब मामलों में उचित कार्रवाई हो रही है, रपट का इंतजार है, न्याय अवश्य होगा और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि जनता की स्मृति कमजोर होती है और नई-नई समस्याएं हाजिर होती रहती हैं, लिहाजा पुरानी घटनाओं का असर उत्तरोत्तर कम होता जाता है।

संसदीय कार्यवाही के सजीव प्रसारण से सभी को पता चलता है कि कौन क्या बोल रहा है? यह समझना अवश्य आसान हो जाता है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है? आम लोग भी समझदार हो रहे हैं और लोकतंत्र का आशय समझने लगे हैं। आज आवश्यकता है कि अपने छोटे-छोटे घरौंदों की सीमाओं को पहचानें। स्वाधीनता दिवस के अवसर को सुयोग बनाने की जरूरत है, ताकि देश आगे बढ़ सके। देश सुरक्षित और समृद्ध होगा तभी सभी का भविष्य सुधरेगा। भविष्य हमारा है, मगर तभी जब हम अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए नए भारत के निर्माण में समुचित सहयोग करेंगे। हमें स्वतंत्रता की महत्ता समझनी होगी और इस पर ध्यान देना होगा कि हमने बीते वर्षों में जो कुछ अर्जित किया है, उससे अधिक पाने के हकदार हैं।

(लेखक पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

सशक्त भारत का निर्माण

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सामाजिक स्तर पर कलह की प्रवृत्तियों को खारिज करने की आवश्यकता पर जो बल दिया, उस पर प्रत्येक नागरिक को ध्यान देना चाहिए। निःसंदेह सबसे अधिक ध्यान राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर लोगों का नेतृत्व करने वालों को देना चाहिए। स्पष्ट है कि नेताओं का दायित्व कहीं अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वे ही समाज को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू में समावेशी भावना तभी दिखाई देगी, जब राजनीतिक वर्ग इस भावना को बल देने के लिए तत्पर रहेगा। अभी ऐसा नहीं है। आज जब हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तब हर किसी को इसके प्रति सजग रहना होगा कि उसके कार्य-व्यवहार से सामाजिक एकता को कहीं कोई क्षति न पहुंचे। इसके प्रति सजग रहकर ही हम सभी को साथ लेकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकेंगे और वह सब कुछ अर्जित कर सकेंगे, जो संभव नजर आ रहा है, जो हमारे लिए अभीष्ट है और जिसके जरिये देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न देखा जा रहा है, उसमें सभी की हिस्सेदारी आवश्यक है, क्योंकि इससे ही भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सभी अपने मतभेदों के बीच सद्भाव बनाए रखने की महत्ता को समझें। यह सद्भाव ही सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने का कार्य करता है।

आज सामाजिक एकता पर बल देने की आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि देश को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियां आंतरिक मोर्चे पर भी हैं और बाहरी मोर्चे पर भी। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि आज विश्व में किस तरह उथल-पुथल हो रही है। चूंकि उथल-पुथल हमारे पड़ोस में भी हो रही है, इसलिए हमें कहीं अधिक सचेत रहना चाहिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उससे हमें केवल चिंतित ही नहीं, बल्कि सजग भी रहना चाहिए। संभवतः बांग्लादेश के अस्थिरता और अराजकता से घिरने के कारण ही राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन की विभीषिका की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित किया। हम सबको यह सदैव स्मरण रहे कि हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता हासिल की, उसकी देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। यह कीमत इसीलिए चुकानी पड़ी थी, क्योंकि तब हम सामाजिक रूप से एकजुट नहीं रह सके थे। अपनी तमाम विविधता और बहुलता के बाद भी हमारे समाज की एकजुटता देश की एक बड़ी शक्ति रही है। एकजुट समाज वह सब कुछ कहीं अधिक आसानी से हासिल कर सकता है, जो उसके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई मिलकर लड़ी थी, वैसे ही हमें सशक्त और समरस भारत के निर्माण का लक्ष्य भी मिलकर साधना चाहिए।

योजनाओं पर निगाह

उत्तराखंड में जिला स्तर पर योजनाओं की प्रगति पर निगाह रखने के लिए मुख्यमंत्री ने डीएम डैशबोर्ड को धरातल पर उतराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों के कल्याण और नारी सशक्तीकरण की दिशा में तेजी से कार्य किए जाने की उम्मीद जताई है, ताकि विभागों द्वारा इन क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे। केंद्र और राज्य की ध्वजवाहक योजनाओं को डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाने के साथ ही प्रधानमंत्री गतिशक्ति उत्तराखंड पोर्टल में पांच करोड़ से अधिक धनराशि की सभी परियोजनाओं को भी शामिल करने को कहा है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जाएं। उच्च शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के साथ जोड़ा जाए। सरकार की चिंता जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण की है। यह तभी संभव है, जबकि योजनाओं को समय से धरातल पर उतारा जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि नियमित तौर पर योजनाओं का अनुश्रवण हो। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की स्थिति क्या है। किस योजना पर कितना काम हुआ है। यदि किसी योजना की चाल मंद है तो इसके क्या कारण हैं। विभागीय सक्रियता एवं उदासीनता का योजनाओं के लागू होने पर क्या असर पड़ रहा है। यह जानकारी जिलाधिकारी को एक क्लिक में उपलब्ध होनी चाहिए। डीएम डैशबोर्ड बनने से जिले में संचालित योजनाओं को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस नहीं रहेगा। हर विभाग की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अधिकतर योजनाओं के सापेक्ष स्वीकृत बजट का उपयोग नहीं होने की बात सामने आती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि किन कारणों से बजट का उपयोग नहीं किया गया। पेयजल, सड़क, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में भी बजट खर्च में उदासीनता सामने आई है।

सदा स्मरण रहे स्वतंत्रता की महत्ता

आरके सिन्हा

हमें स्वाधीनता सेनानियों के साथ उनका भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने विभाजन की पीड़ा देखी-भोगी

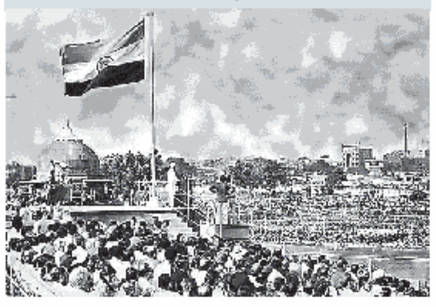

बहुत कठिनाई से मिली थी आजादी। फाइल

आज देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। स्वाधीनता दिवस भारत के लिए दो तरह की अनुभूतियां लेकर आता है। पहला, असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष के कारण 15 अगस्त, 1947 को देश को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्ति मिली। इसलिए उन तमाम स्वाधीनता सेनानियों के प्रति मन में अपार श्रद्धा का भाव पैदा होने लगता है, जिनके बलिदानों की वजह से अंग्रेज यहां से गए। दूसरा, देश को आजादी के साथ बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। भारत दो भागों में बंट गया। विभाजन की त्रासदी की मार पड़ने के बाद कुछ ही दिनों में नए देश बने पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी देश के अनेक हिस्सों के साथ दिल्ली आए। लाखों सौभाग्यशाली बचकर आ गए तो लाखों अभागे मारे भी गए। जब देश अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब लाखों लोग विभाजन की पीड़ा भोग रहे थे। विभाजन के दिनों में दिल्ली जंक्शन पर आने वालों में मिल्खा सिंह भी थे, जिसे आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। वह आगे चलकर महान धावक बने। देश के बंटवारे के समय इंसानियत एक तरह से मरी पड़ी थी। पाकिस्तान में सांप्रदायिक सोच वालों ने मिल्खा सिंह के माता-पिता का कत्ल कर दिया था, पर तब भी कुछ फरिश्ते तो मौजूद थे ही। वे उन्हें रेल के महिला डिब्बे में छिपाकर भारत ले आए थे। विभाजन की विभीषिका में वह अपनी बहन से बिछड़ गए। जरा सोचिए कि विभाजन के कारण अस्त-व्यस्त और अनजान शहर में मिल्खा सिंह दंगों के दौरान गुम हो गई अपनी बहन को कैसे खोज रहे होंगे, पर उन्होंने अंततः उनको तलाश लिया।

देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली विभाजन की घड़ी में उस समय आज के मुकाबले एक छोटा सा शहर था। तब यहां सेंट स्टीफंस अस्पताल की प्रमुख डा. रूथ रोसवियर के नेतृत्व में घायल और बीमार शरणार्थियों का इलाज हो रहा था। डा. रूथ रोसवियर ब्रिटिश नागरिक थीं। सेंट स्टीफंस अस्पताल को दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी ने 1885 में खोला था। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को सारा देश उनकी देशभक्ति से रची-बसी फिल्मों के चलते बखूबी जानता है। उनका परिवार जब देश के बंटवारे के बाद सरहद के उस पार से लुटा-पिटा 1947 में दिल्ली आया तो उनके परिवार के कई सदस्य दंगाइयों के हमलों के कारण चोटग्रस्त थे। उनका छोटा भाई बीमार था। तब उन सबका इलाज इसी सेंट स्टीफंस अस्पताल में हुआ था।

देश के बंटवारे के कारण पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली आए थे। ये ज्यादातर दिल्ली जंक्शन पर ही आते थे। तब इनके पास नए शहर में खुले आसमान के अलावा कुछ नहीं होता था। उस भीषण दौर में दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ सिख संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शरणार्थियों की बहुत मदद की। इनके अलावा संकट के उस दौर में दिल्ली के करोलबाग में रहने वाले डा. एनसी जोशी ने भी शरणार्थियों की खूब सेवा की। करोलबाग में 1947 के दौरान जब दंगे भड़के तो डा. एनसी जोशी भी उसके शिकार हो गए थे। लेडी इरविन अस्पताल (अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल) के तत्कालीन मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डा. बनवारी लाल और कबूलचंद वाल्मीकि जैसे उनके साथियों ने भी रोगियों का दर्द दूर किया। दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी के कार्यकर्ता बहुत से रोगियों को लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल भी इलाज के लिए लेकर जाते। उस दौर में इसकी प्रिंसिपल-डायरेक्टर डा. केजे मैक्डरमाट और डा. ओपी बाली की देखरेख में रोगियों का अच्छी तरह इलाज हुआ था। शरणार्थियों की सेवा के लिए मशहूर हुए विशंभर दास ने 1922 में नई दिल्ली क्षेत्र में विशंभर फ्री होम्योपैथिक डिस्पेंसरी की स्थापना की और जीवनपर्यंत दीनहीनों का इलाज करते रहे।

आज भी बहुत से ऐसे परिवार मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि अगर दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी से जुड़े फादर इयान बेदरबेल और उनके साथियों का साथ न मिलता तो वे भारत विभाजन की भेंट चढ़ गए होते। आज उनका कोई नामलेवा नहीं रहता। वे विभाजन के कारण सड़क पर आ गए थे। फादर इयान बेदरबेल शरणार्थियों के पुनर्वास में लगे रहे। फादर इयान बेदरबेल का भारत से सबसे पहले रिश्ता तब स्थापित हुआ था, जब दूसरा विश्व महायुद्ध चल रहा था। वह ब्रिटेन की फौज में पंजाब रेजीमेंट में थे। विश्व महायुद्ध की समाप्ति के बाद उनका जीवन बदला। वह युद्ध के विरुद्ध बोलने-लिखने लगे। उन्होंने जंग के कारण होने वाली तबाही अपनी आंखों से देखी थी। उन्हें युद्ध की निरर्थकता समझ आ गई थी। वह जीवन में शांति चाहते थे। फादर इयान बेदरबेल पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना शेष जीवन गरीबों और हाशिए पर धकेल दिए लोगों के हक में काम करने में लगा दिया। फादर इयान बेदरबेल की जान भारत में बसती थी।

भारत आज जब अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है, तब हमें स्वाधीनता सेनानियों के साथ-साथ उन तमाम लोगों का भी स्मरण कर लेना चाहिए, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका झेली और जिन्होंने पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को सहारा दिया। ध्यान रहे कि तब देश में सरकार नाम की कोई चीज मुश्किल से ही थी। सब तरफ अराजकता और अव्यवस्था का आलम था। उस दौर में निःस्वार्थ भाव से शरणार्थियों का साथ देने वाले किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। न तो विभाजन को भूला जाना चाहिए और न ही लाखों-लाख शरणार्थियों को। देश को विभाजन की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसीलिए हर किसी को यह समझना चाहिए कि हमें जो स्वतंत्रता मिली, वह बहुत अनमोल है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पारिवारिक जीवन की सार्थकता

वर्तमान में कुसंग और भौतिकता की अंधी दौड़ में पारिवारिक जीवन की प्रसन्नता और समृद्धि तार-तार होकर रुदन कर रही है। परिवार की एकता में बिखंडता जीवन की गति-मति को प्रदूषित कर रही है। संसार में वही परिवार सुख-समृद्धि से परिपूर्ण है, जहां परस्पर प्रेम और अपनत्व का वातावरण है। स्मरण रहे, सभी परिजन एक-दूसरे के अनुकूल व्यवहार करें, यह संभव हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि यह हमारे अधिकार में नहीं है, किंतु हम यह विचार करें कि हम सबके अनुकूल हो जाएं, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र में हो सकता है।

पलायनवाद किसी भी परिस्थिति या समस्या का निदान नहीं है। परिवार के लोग बाधक नहीं हैं, अपितु हमारा कृपण व्यवहार ही हमारा बाधक है। परिवार का भावार्थ है-परस्पर आवेष्टित अर्थात घिरा हुआ एक समूह। हमारे चारों ओर जो परिजन हैं वे सब हमारे शरीर के अंग और संरक्षक हैं। इस प्रकार का सद्भाव ही परिवार की एकता को मुखरित करता है। हमारे ऋषि-महर्षियों ने 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना की, जिसका अनुपालन सर्वत्र सदा 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की सत्कामना को अलंकृत करता है। श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, 'सबहि मानप्रद आपु अमानी।' यानी सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मानरहित होते हैं। इस सूत्र के अनुपालन से देश-विदेश, नगर-ग्राम और घर-परिवार में सर्वत्र अनेकता में एकता का संयोजन हो जाएगा।

जब तक परिवार में परस्पर विश्वास और प्रेम नहीं होगा, तब तक सदस्यों के मानस पटल पर संशय एवं अविश्वास छाया रहेगा। घर-परिवार में पारदर्शी आचार-विचार ही सबको अपनत्व के कवच से सुरक्षित रखते हैं। परिजनों का सुविचार ही उनके संबंधों के प्रेम को सदा आलोकित करता है। वे परिवार धन्य हैं जहां सभी एक-दूसरे के कल्याण का चिंतन करते हैं।

आचार्य नारायण दास

मिलावटी दूध का दंश

डा. शशांक द्विवेदी

मिलावटी दूध की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कोई ठोस नीति बनानी होगी

पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार देश में मिलावटी दूध के मामले बढ़ रहे हैं। दूध में मिलावट के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इसके बाद केरल एवं तमिलनाडु का स्थान है। पंजाब में भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट की मात्रा काफी पाई गई है। इसके लिए खुले दूध, दूध के पैकेटों, पनीर, दही, मिठाई, बिस्कुट आदि के सैंपलों की जांच की गई। दूध में मिलावट ने दूध की गुणवत्ता खत्म कर दी है। सिंथेटिक और मिलावटी दूध तथा दूध के उत्पाद यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड आयल, कास्टिक सोडा और सफेद पेंट आदि से तैयार हो रहे हैं। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लीवर एवं किडनी फेल होने एवं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां केमिकल मिले दूध के कारण बढ़ रही हैं।

कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध के मामले में कहा था कि कि क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए, जिसे पीकर लोग तुरंत मरने लगें, तब सरकारें कोई कानून बनाएंगी? शायद अब देश में लोगों की नियति ही बन गई है मिलावटी दूध पीने की। व्यावसायिक रूप में गाय, भैंस पालने वालों से लेकर दूधिया और ठेकेदार सभी दूध की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकारों ने इसे रोकने को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। लगता है लोगों की सेहत से जुड़ा यह संवेदनशील मुद्दा सरकारों की प्राथमिकता सूची में ही नहीं है। दूध में मिलावट पर संसद में स्वीकारोक्ति के बाद तो यह मामला और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि जब केंद्र सरकार इसे मान रही है तो प्रश्न उठता है की इसे रोकने को लेकर तत्काल कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

अधिकांश प्रदेशों में अभी फूड सेफ्टी से जुड़े कानूनों के तहत मिलावट के दोषियों को अधिकतम छह माह कैद की व्यवस्था है। लचीले कानून का लाभ मिलने से मिलावटखोरों की मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है। कोर्ट ने सरकारों को मौजूदा कानून में बदलाव करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस निर्देश पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मिलावटी दूध के मामले को लेकर अभी तक अधिकांश छोटे शहरों, जिलों में कोई जांच लैब नहीं हैं। इतने बड़े पैमाने पर हो रही दूध की बिक्री के एवज में कस्बों और जिले के स्तर पर जांच संबंधी लैब न होने से लोग दूध में मिलावट की शिकायत नहीं कर पाते हैं। साफ है देश भर में मिलावटी दूध की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस नीति बनानी होगी। गांवों, कस्बों और शहरों में प्रशासन को स्पष्ट दिशानिर्देश देने होंगे। मिलावटी दूध के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रविधान भी करने होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सम्यक दृष्टि जरूरी

'फिर दिखा सेक्युलरिज्म का विकृत चेहरा' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने विपक्षी दलों के नेताओं के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वाधीनता के सात दशक बाद भी हमारे देश के राजनीतिक दलों को यह क्यों लगता है कि हिंदुओं की आलोचना या उनके ऊपर विश्व के किसी हिस्से में हो रही ज्यादती से मुंह फेर लेना ही पंथनिरपेक्षता है? पंथनिरपेक्षता के प्रति यह गलत समझ विकसित करने में ऐसे ही नेताओं का योगदान है, जिसका दर्द एक बार देश भुगत चुका है। पंथनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मावलंबियों के प्रति समादर का भाव है, ताकि किसी पंथ विशेष के लोगों में विशिष्ट होने का भाव उत्पन्न न हो और किसी में कमतर होने के भाव विकसित न हों, लेकिन हमारे नेता वोट बैंक के फेर में अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी विशेष धर्म के प्रति उपेक्षा और अनुराग का भाव सांप्रदायिक राजनीति है। लिहाजा बांग्लादेश सहित विश्व के किसी हिस्से में किसी भी धर्मावलंबी पर अत्याचार हो रहा है तो उसके प्रति हमें सम्यक दृष्टि रखने की जरूरत है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

एक दिन की देशभक्ति

भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 78 साल हो गए। देखा जाए तो लोगों के लिए रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाषचंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों का मोल बस एक दिन की देशभक्ति तक ही सीमित रह गया है। लोगों को बस एक सरकारी नौकरी, एक घर और दो वक्त का खाना चाहिए। आज लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने स्वार्थपूर्ति और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार न होने के कारण देश का कितना नुकसान होता है। इंटरनेट मीडिया पर सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाले पोस्ट शेयर करके लोग देशभक्ति के समंदर में ऐसे डूब जाते हैं मानो उनके ऐसा करने से ही देश की उन्नति हो रही हो। लोगों को संविधान में लिखे मौलिक अधिकार तो याद हैं, लेकिन उसी संविधान के अनुच्छेद 51(ए) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों को लोग क्यों भूल जाते हैं, जिसमें संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें आदि महत्वपूर्ण कर्तव्य शामिल हैं? हमें साफ सुथरी गड्ढे रहित सड़कें चाहिए फिर चाहे हम उसे पान की पीक से सजाएं या घर से निकले कचरे से और यातायात नियमों का पालन करने को तो मत कहना। वह हमसे होता नहीं है। जब तक देशवासी ऐसे छोटे-छोटे कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और नेता अपनी गद्दी बचाने के लिए घटिया राजनीति का सहारा लेते रहेंगे तब तक देश की उन्नति संभव नहीं है। जनता हो या नेता हर किसी को अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करना होगा।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

कमजोर लोकतंत्र के दुष्परिणाम

वस्तुतः जहां लोकतंत्र कमजोर होता है, वहां निरंकुशता जन्म लेती है। विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों के दमन की नीति से प्रधानमंत्री शेख हसीना की लोकतांत्रिक छवि को बट्टा लगा। यह ठीक है कि उनके 15 वर्ष से अधिक के शासनकाल में भारत के सहयोग से बांग्लादेश ने पर्याप्त आर्थिक उन्नति की थी, लेकिन अपने चौथे कार्यकाल में वह विपक्षी आक्रोश को हवा देने वाली विदेशी शक्तियों के षड्यंत्र को भांप नहीं पाईं। जिसके दुष्परिणाम स्वरूप उन्हे अपदस्थ हो कर देश से निष्कासित होना पड़ा। बांग्लादेश की सेना चाहती तो वह विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आए बिना प्रधानमंत्री शेख हसीना का साथ दे सकती थी, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों के आगे झुकते हुए बांग्लादेशी सेना ने देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा देने से मना कर दिया। बांग्लादेश के इन बदतर हालातों के लिए लोकतंत्र में विश्वास न रखने वाला कट्टरपंथ ही जिम्मेदार है।

pandeyvp1960@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

राजकुमार जैन
वरिष्ठ स्तंभकार

आजकल

विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर देश

लगभग दो सदी तक अंग्रेजों के अधीन रहने के पश्चात हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1947 में आज के दिन ही हम भारतीयों ने ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही अपनी नियति का निर्माण स्वयं करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की थी। आज जब हम अपने देश की साढ़े सात दशक की यात्रा को देखते हैं तो पाते हैं कि इस दौरान देश ने तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां कायम हैं, फिर भी ऐसी अनगिनत उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हमें जानना-समझना चाहिए

देश के लगभग प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति की गति भी तेज हो रही है। फाइल

वर्ष 1947 में आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता मिलने और अपने स्वतंत्र संविधान को अपनाने के बाद हमारे देश ने अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लिए एवं देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम 'विकसित भारत' है, जो देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। आज 77 वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर अपनी प्रगति देखकर हम गर्व के साथ रोमांचित भी हो जाते हैं। आज हमारा देश विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल, आर्थिक-सामाजिक, कला व वास्तुकला के क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। देश निरंतर प्रगति कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी, नवाचार और संस्कृति का केंद्र बनने तक हमने अविश्वसनीय प्रगति की है।

शिक्षा और स्वास्थ्य : किसी भी देश के विकास में शिक्षित नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। इस क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। साक्षरता दर 12 प्रतिशत से बढ़कर 77 प्रतिशत हो गई हैं। देश में स्कूलों की संख्या एक लाख 40 हजार से बढ़कर 15 लाख हो गई है, शिक्षा और ज्ञान के केंद्र विश्वविद्यालयों की संख्या 1265 हो गई हैं। कालेजों की संख्या 50 हजार से अधिक हो चुकी है। वहीं स्वस्थ जनसंख्या किसी भी विकसित राष्ट्र की आधारशिला होती है और स्वस्थ नागरिक एक मजबूत देश का निर्माण करते हैं। महज नौ मेडिकल कालेज से शुरू हुआ सफर 731 तक पहुंच चुका है, जहां हर साल एक लाख से भी अधिक छात्र डाक्टर बनने के लिए प्रवेश लेते हैं। देश भर में लगभग 70 हजार अस्पताल और 13 लाख डाक्टर्स की मौजूदगी के चलते मातृत्व मृत्यु दर दो हजार से घटकर 103 रह गई है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार में 150 से घटकर 27.6 हो गई है।

यातायात : आज देश में लगभग 600 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 67 लाख किलोमीटर तक फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल मौजूद है, जो आर्थिक विकास में महती योगदान देता है। आजादी के बाद भारतीय रेल देश के विकास के लिए आधुनिक तकनीक से साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही है। आज हमारे रेल नेटवर्क की लंबाई 1.26 लाख किलोमीटर से अधिक है। इसी तरह हवाई उड़ान सेवा किसी भी विकासशील देश की परिवहन सेवा का एक अहम हिस्सा होता है और देश की तरक्की का अभिन्न अंग भी। आजादी के समय यह सेवा महज नौ कंपनियों द्वारा देश के चुनिंदा लोगों को ही उपलब्ध करवाई जाती थी और आज देश में 39 एयर ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जो 148 हवाई अड्डों से संचालित 700 से ज्यादा विमानों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। इस साल की पहली छमाही में 7.93 करोड़ यात्रियों ने घरेलू विमानों से यात्रा की है, जिसमें निरंतर वृद्धि जारी है। हालांकि सभी देशवासियों को सुगम और सस्ती यात्रा प्रदान करने के बारे में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

बिजली का दर्जा जीवन रेखा की तरह समझा जाता है, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में तीव्रता से काम करते हुए हमारी क्षमता 1,362 मेगावाट से बढ़कर चार लाख मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसके चलते आज छह लाख से अधिक गांव बिजली से रौशन हैं। अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने का पहला प्रयास 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुअनंतपुरम के पास थुंबा में हुआ था। तब राकेट को प्रक्षेपण स्टेशन तक साइकिल से ले जाया गया था। उस समय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े विज्ञानियों के पास अपना कोई कार्यालय तक नहीं था और आज हमने चंद्रयान-3 लांच करके चांद पर पहुंचने वाले चौथे देश की उपाधि हासिल कर ली है।

विदेश व्यापार : किसी भी देश के द्वारा किया जाने वाले निर्यात, देश की वित्तीय और आर्थिक साख को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत के निर्यात दर की बात करें तो साल 1950-51 की 1.27 अरब डालर से बढ़कर 2023-24 में यह 776.68 अरब डालर तक पहुंच चुकी है। तकनीक के मामले में भी देश ने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। वर्ष 1986 में भारत में इंटरनेट आया, उस दौर में यह केवल शिक्षा और अनुसंधान के लिए ही उपलब्ध था। लेकिन आज देश में 95.44 करोड़ लोग इंटरनेट के ग्राहक हैं, जिनमें से लगभग 40 करोड़ तो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। विश्व आर्थिक मंच का मानना है कि अगले एक दशक में भारत की आर्थिकी 10 लाख करोड़ डालर तक पहुंच जाएगी। विकसित भारत का संकल्प चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह असंभव नहीं है तो आसान भी नहीं है।

चुनौतियां : विकसित देश बनने की राह में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सतत प्रगति के लिए कुशल शासन महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना बड़ी चुनौतियां हैं। विशाल जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती है जो संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। विभिन्न वर्गों के मध्य आय असमानताएं बनी हुई हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर अलग-थलग पड़े समुदायों के उत्थान के लिए समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच और स्वास्थ्य सेवा असमानताओं से जूझ रहे हैं। कुपोषण से लेकर गैर-संचारी रोगों तक की स्वास्थ्य चुनौतियां सामने हैं। स्नातकों और कामगारों द्वारा अर्जित कौशल और उद्योगों की मांग के बीच अंतर है, जो आर्थिक उत्पादकता और नवाचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हालांकि भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत को कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।

देश को विकसित बनाने के लिए कई और महत्वपूर्ण सेवाओं एवं सुविधाओं की जरूरत होगी। देश में प्रत्येक नागरिक के पास गुणवत्तापूर्ण आवास, 24 घंटे शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा और गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति, हाई-स्पीड ब्राडबैंड और बैंकिंग सुविधाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच जरूरी होगी। देश में एआइ सक्षम चिकित्सा, शिक्षा और कृषि जैसी उन्नत तकनीकों सहित सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना आवश्यक है।

स्वतंत्र भारत में नाम, जाति, धर्म, स्थान से परे हम सबकी एक ही पहचान है- भारत का नागरिक होना। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं और अपने मूल्यों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना भी याद रखना चाहिए। विविधता में हमारी एकता ही हमें अद्वितीय बनाती है और यही एकता हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। इस 15 अगस्त को जरूरत है उसी सकारात्मक बदलाव का जश्न मनाने की। हमें यह याद रखना है कि स्वतंत्रता दिवस इतिहास में दर्ज केवल एक तारीख भर नहीं है, बल्कि एक बार स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद, उसे पोषित, संरक्षित और संजोकर रखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. आइए आज हम इस महान राष्ट्र के पथप्रदर्शक बनने, इसके मूल्यों को बनाए रखने और इसकी प्रगति के लिए एक देशभक्त नागरिक के रूप में अथक और ईमानदार प्रयास करने का संकल्प लें।

पड़ोस से पैदा चुनौतियों से निपटने की क्षमता

विकसित देश बनने की राह में हमारे समक्ष अनेक प्रकार की आंतरिक चुनौतियां तो हैं ही, साथ में अस्थिर पड़ोसियों के चलते सुरक्षा चुनौतियां चौतरफा बढ़ रही हैं। नेपाल में चीन समर्थक सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होने दिया है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत के लिए असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न कर सके। इससे बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं। पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमजोर करने में सफल हो गए हैं। दबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक घटनाक्रम के चलते वहां अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला कायम है। यदि बांग्लादेश और म्यांमार की तानाशाही ताकतें चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में आकर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती हैं। उधर म्यांमार में भी आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। हमारे एक और पड़ोसी श्रीलंका में अभी भी भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। हद तो यह है कि मालदीव जैसे देश ने भी बीते दिनों ऐसी हरकतें की हैं, जो भारत को असहज करने वाली रही हैं। हालांकि वहां के राष्ट्रपति को अब इसका अहसास हुआ है जो पिछले दिनों लगातार भारत विरोध में लगे हुए थे, परंतु अब उनका रुख कुछ बदला है।

पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पहले से ही मुसीबत बने हुए हैं। भारत इन सभी देशों की सीमाओं से जुड़े होने के कारण एक प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। दक्षिण एशिया में जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए हमें अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है और विश्व के लोकतांत्रिक देशों एवं क्षेत्र में मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे जापान व आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पाकिस्तान-चीन पर दबाव बनाना होगा, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का लाभ उठाकर भारत को कमजोर करने के मंसूबों से बाज आएं। **(राजकुमार जैन)**

खरी-खरी

आज के फ्रीडम फाइटर

अलंकार रस्तोगी

लोग आज की इस आधुनिक पीढ़ी को यह कहकर नकारा घोषित करते हैं कि इनको आजादी का महत्त्व नहीं मालूम है। लेकिन मामला उल्टा है भाई। इस पीढ़ी में भी एक अलग ही टशन चल रहा है। यहां भी 'स्वतंत्रता संग्राम' का घनघोर आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे पड़ोसी का इकलौता लड़का तो पूरा क्रांतिकारी हुआ जा रहा है। सुबह उठते ही उसका 'गदर' शुरू हो जाता है। कालेज नियमित रूप से जाने को कहने पर वे 'असहयोग आंदोलन' की तर्ज पर नई वाली धूम स्टाइल की बाइक मिलने पर ही अपने कालेज की ओर कूच करने की बात कहते हैं। 'करो या मरो' की तर्ज पर अपने परम लोफर दोस्तों की सलाह पर अब वह एक अदद 'गर्ल फ्रेंड' की जी जान लगाकर तलाश कर रहे हैं। मजनूगिरी जैसे साहसिक कार्य करने के कारण उनका 'जेल भरो आंदोलन' अब पूरे इलाके में अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुका है।

दोस्तों के साथ बाइक पर ट्रिपलिंग करने के समाजोपयोगी कार्य के लिए उन्होंने अत्याचारी पुलिस के 'लाठी चार्ज' का कई बार दिलेरी से सामना किया है। उनके क्रांतिकारी कृत्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। एक बार तो उन्होंने भरे क्लास में टीचर के ऊपर चाक फेंक कर सोते हुए सिस्टम को 'जगाने का प्रयास' भी किया था। उनके दाएं गाल में जो खरोंच का निशान है, वह उसी क्रिया की 'दमनीय प्रतिक्रिया' का परिणाम है।

अपने साथियों के अंदर अपने पुराने फोन से 'आजादी की ललक' को जगाने का सूत्रपात कर सके, इसलिए वह बाप की कमाई का एपल फोन ही चलाते। जब भी घर में किसी 'जुल्म' की तरह लौकी की सब्जी बनती है, तब वह 'आमरण अनशन' पर बैठ जाते हैं। उनका अनशन तब तक जारी रहता है, जब तक उनके घर वाले उनके लिए 'आनलाइन पिज्जा वाली मांग' पूरी नहीं कर देते हैं। उनकी एक आदत सबसे अच्छी है कि वह 'अहिंसा के रास्ते' पर चलते हैं। उन्हें जब भी समाज में कुछ गलत दिखाई देता है, तब जनाब उसका विरोध करने के बजाय अहिंसक तरीके से उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर देते हैं।

पोस्ट

भारत का जो हाल है, उसे देखते हुए विभाजन विभीषिका दिवस उचित लगने लगा है, लेकिन केवल सरकारी आयोजन से सामाजिक चेतना नहीं विकसित होती।
रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

पश्चिमी देश भारत को प्राकृतिक खेती करने को कह रहे हैं। हरित क्रांति से पहले हम कैसी खेती करते थे? बिना उर्वरक, कीटनाशक और रसायनों के खेती के सिवा और क्या है प्राकृतिक खेती? पश्चिम को नचाना पसंद है और हमें नाचना।
मंजीत ठाकुर@manjit2007

एक्स पर जिन लोगों ने भी कोलकाता दुष्कर्म मामले पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल पूछा, उन सभी को महुआ ने ब्लाक कर दिया है, क्योंकि सवाल से सब डरते हैं। जबकि कुछ लोग सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते!
प्रभाकर मिश्रा@PMishra_Journo

ट्रेनी डाक्टर रेप-मर्डर केस में कलकत्ता हाई कोर्ट की दो बातें अहम हैं। एक, पीड़िता की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। दूसरी, राज्य सरकार पीड़िता या उसके माता-पिता के साथ नहीं है। इसके चलते ही जांच सीबीआइ को सौंपी गई। ये दोनों कारण किसी भी राज्य सरकार के लिए भारी शर्मिंदगी की वजह होने चाहिए।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या कोलकाता ट्रेनी डाक्टर दुष्कर्म-हत्या मामले की सीबीआइ जांच जरूरी है?

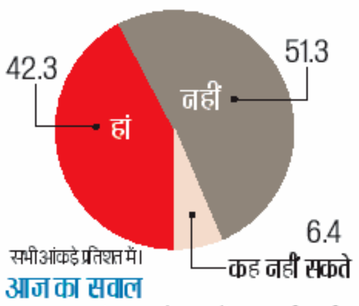

समीआंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की अभी तक की यात्रा संतोषजनक रही?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आज तिरंगे की बढ़ी 'लालचौक' पर शान,
'डल' के तीरे गूँजता जय भारत का गान।
जय भारत का गान हुआ है यह परिवर्तन,
जहां रोज आतंक किया करता था नर्तन।
धरती होती लाल हुआ करते थे दंगे,
वहीं शान के साथ फहरते आज तिरंगे।
- ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

संकट में प्रदेश के बाघ, साजिश की आशंका

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के बाघ इन दिनों संकट में हैं। दरअसल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पिछले तीन वर्षों के दौरान 34 बाघों की मौत हुई। इसकी जांच में पाया गया कि कई बाघों का शिकार किया गया था और इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय फंडिंग की बात भी सामने आई है। स्वाभाविक है कि इस साजिश में कुछ स्थानीय, तो कुछ विदेशी लोगों का हाथ हो सकता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में कई अंतरराष्ट्रीय एनजीओ बाघ संरक्षण का काम कर रहे हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो रही है। इन एनजीओ के माध्यम से कई विदेशी लोग भी वन्यजीव विशेषज्ञ के नाम पर इन उद्यानों में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो इन विदेशी एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग की जांच के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस से भी आग्रह किया है कि बाघों के शिकार के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश की जांच करे। पर क्या बाघों को बचाने के लिए ये कदम पर्याप्त हैं? यह बड़ा सवाल है।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की ही बात की जाए तो तीन वर्ष में 34 बाघों की संदिग्ध मौत और उद्यान प्रबंधन द्वारा उस पर पर्दा डालने का प्रयास सामान्य बात मानी जाएगी। जब सरकार के स्तर पर एक-एक मामले की जांच कराई गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पार्क प्रबंधन ने अधिकतर बाघों की मौत को आपसी संघर्ष का परिणाम बता दिया और फाइल बंद कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 मामलों में, विस्तृत जांच के बिना बाघों की मौत को आपसी लड़ाई का परिणाम बताना एक बड़ी भूल है। जिस बाघ की मौत बिजली के करंट से हुई, यह देखना तक उचित नहीं समझा गया कि उसे करंट लगा या किसी शिकारी ने करंट देकर मारा। बिजली का करंट देकर शिकारियों ने बाघ को मारा और नाले में रेत के नीचे दबा दिया। ऐसी मौत को भी बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन ने प्राकृतिक मौत बताने का प्रयास किया।

एक अन्य मामले में पता चला कि 17 मई 2023 को नौ साल का एक बाघ मृत पाया गया। उसके नाखून गायब थे। पहले इस बाघ की मौत का कारण अवैध शिकार माना गया और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बाद में इसे भी बाघों का आपसी संघर्ष बताया गया। पांच सितंबर 2023 को एक वयस्क बाघ का शव रेत में दबा हुआ पाया गया, जिसके नौ नाखून, सिर, खोपड़ी, त्वचा और सिर के कुछ अंग गायब थे। रिपोर्ट के अनुसार, मामले की ठीक से जांच नहीं की गई, पोस्टमार्टम और प्रयोगशाला के निष्कर्षों से अवैध शिकार का पता चला है। इस बाघ की मौत के मामले में उद्यान प्रबंधन द्वारा कहा गया था कि बाघ की मौत नाले के नीचे हुई है। संभवतः वर्षा के दौरान पानी के बहाव के साथ रेत बहने के कारण शव उसके नीचे दब गया होगा। बांधवगढ़ में वर्ष 2021 में 12 बाघों की मौत हुई, तो वहीं 2022 में नौ और 2023 में 13 बाघों की मौत हुई। सबसे अधिक मौतें मनपुर बफर जोन में हुई। इनमें से दस बाघों की मौत के बाद उद्यान प्रबंधन ने पोस्टमार्टम करवाना भी उचित नहीं समझा और इसके लिए टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक को पोस्टमार्टम नहीं कराने का दोषी बता दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीन वर्षों में वहां अलग-अलग समय में पदस्थ रहे फील्ड डायरेक्टरों से लेकर वन विभाग और काम करने वाले एनजीओ की भूमिका की जांच तक नहीं की गई। बता दें कि यहां बांधवगढ़ सहित मध्य प्रदेश में लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशन, एसएलएमसी, विद पार्टनर विनरोक, वर्टिवर फाउंडेशन, डब्ल्यूआरसीएस पुणे, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूटीआइ, डब्ल्यूसीटी सहित अन्य गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं।

इस बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने कहा कि बांधवगढ़ में विदेशी फंडिग और ट्रांजेक्शन की बातें सामने आई हैं जिसका पता लगाया जा रहा है। प्रबंधन अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के अकाउंट को भी पुलिस जांच में लेने का आग्रह करेगा। जाहिर सी बात है कि एक राष्ट्रीय उद्यान का यह सच बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। सच तो यह भी है कि अवैध शिकार में अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और साजिश का यह खेल केवल बांधवगढ़ तक सिमटा नहीं है, बल्कि प्रदेश और देशभर में इनका जाल न फैला हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भी इस बात की चिंता करना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में इतने अधिक बाघों की मौत क्यों हो रही है। इसका समाधान भी बताना चाहिए। उन अधिकारियों की भी जांच करनी चाहिए, जिन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय साजिश में भूमिका निभाई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 34 बाघों की हुई है संदिग्ध मौत। फाइल

एमएसएमई क्षेत्र

राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका

मनोहर मनोज
वरिष्ठ पत्रकार

हमारी आर्थिकी में एमएसएमई क्षेत्र का व्यापक योगदान है। फिर भी इनमें से अनेक उद्यम कई कारणों से कुछ वर्षों के उपरांत ठप हो जाते हैं, लिहाजा इनके लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं

केंद्र सरकार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की बात कर रही है, इसीलिए इस बार के बजट में सरकार ने एमएसएमई के लिए कई प्रोत्साहनों और स्कीमों घोषणा की है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो एमएसएमई की राहें अभी भी आसान नहीं हैं। औद्योगिक प्लाट, पूंजी, तकनीक, मशीनरी, प्रशिक्षण, कच्चे माल की आपूर्ति, बिजली, परिवहन, मार्केट आर्डर तथा सबसे ऊपर बड़े देशी-विदेशी उद्योग से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा, ये तमाम बाधाएं किसी भी छोटे कारोबारी के लिए बड़े कारोबारी से ज्यादा कठिन होती हैं। देखने में आता है कि देश के अनेक छोटे उद्यमी कुछ वर्षों तक व्यवसाय करने के बाद उपरोक्त बाधाओं के आगे घुटने टेक देते हैं। इस बार के बजट में एमएसएमई यानी छोटे, लघु व मध्यम उद्योग को आगामी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का आधार मानकर उसे प्रोत्साहन देने के हर संभव उपाय घोषित किए गए हैं।

सरकार के वर्तमान प्रोत्साहनों के पीछे कई कारक हैं। देश की आबादी में युवाओं की करीब दो तिहाई हिस्सेदारी है, लिहाजा बेरोजगारी को लेकर स्वरोजगार पर अधिकाधिक संबल देने की सरकार की नई नीति, बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को कौशल विकास व इंटर्नशिप प्रदान कर निजी क्षेत्र को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने आदि में इनकी भूमिका बड़ी मानी जा रही है। दूसरा देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आमदनी, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा विकास के विकेंद्रीकरण इन सभी को ध्यान में रखकर एमएसएमई अब सरकार द्वारा विकास की आगामी व्यूह रचना का एक बेहद महत्वपूर्ण अवयव माने जा रहे हैं। यही कारण है कि अभी लघु मध्यम उद्योग को लेकर हो रहे विमर्श में अब कई नए पहलू जुड़ गए हैं। मसलन स्वरोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, सहकारी क्षेत्र उद्यमी, खाद्य प्रसंस्करण, रुफ टाप सोलर पैनल, हथकरघा, स्व-सहायता समूह व लखपति दीदी, आदिवासी ग्राम विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा, आवास विकास योजना, कई अन्य स्कीमें व वित्तीय योजना एमएसएमई के विराट इकोसिस्टम में समाहित कर दी गई हैं। इस बार के बजट में यह बात भलीभांति देखने में आई है कि सरकार लघु मध्यम उद्योगों के लिए कच्चे माल, मशीनरी, फाइनेंस, मार्केट, प्रशिक्षण और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसी सुविधाओं का एक बहुस्तरीय प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने को लेकर काफी गंभीर है। इसके तहत सरकार द्वारा एमएसएमई का दायरा काफी विस्तृत कर दिया गया है। जैसे छोटे उद्योग के तहत निवेश सीमा मौजूदा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़, लघु उद्योग की निवेश सीमा मौजूदा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ तथा मध्यम उद्योग की निवेश सीमा मौजूदा 50 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दी गई है।

इस क्रम में नई घोषणा यह है कि सेवा और विनिर्माण उद्योग को उनकी निवेश सीमा के मुताबिक एमएसएमई के मातहत रख दिया गया है जिसकी सारी सुविधाएं और प्रोत्साहन इन्हें प्रदान की जाएंगी। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए सभी सप्लाई आर्डर का भुगतान अधिकतम 45 दिनों के भीतर करना होगा, अन्यथा आर्डर देने वाले फर्म की टीडीएस कर देनदारी जब्त कर ली जाएगी। एमएसएमई को लेकर इन सारे उपायों पर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो इसमें दिक्कत बस यह दिखती है कि इस क्षेत्र को लेकर इस समय सरकार के पास एक से अधिक चैनल व एजेंसियां हैं, परंतु इनके बीच आपसी समन्वय सही से नहीं हो पा रहा है।

यदि हम देश में छोटे, लघु व मध्यम उद्योग की एक पूरी तस्वीर का अवलोकन करें तो देश में पंजीकृत एमएसएमई उद्योगों की कुल संख्या 3.64 करोड़ है जिनसे करीब 16 करोड़ लोगों की आजीविका चल रही है और यह हमारी कुल श्रमशक्ति का लगभग 40 प्रतिशत है। इनमें देश के विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन का 38 प्रतिशत तथा निर्यात क्षेत्र का 45 प्रतिशत योगदान है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में इसका कुल योगदान 30 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि पिछली सदी के अंतिम दशक में नई आर्थिक नीति के बाद यह बहस तेजी से छिड़ी कि उदारीकरण व भूमंडलीकरण से देश के बचे छोटे मध्यम उद्योग बड़े उद्योग के साये तले मिट जाएंगे या प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इस श्रेणी के उद्योगों ने देश की अर्थव्यवस्था में न केवल अपनी पहचान बनाए रखी, बल्कि उत्पादन, रोजगार और निर्यात में भी अपनी अहम हिस्सेदारी बनाए रखी।

नई आर्थिक नीति के उपरांत उद्योगों में जिस इंस्पेक्टर राज का उल्लेख किया जाता था, कहीं न कहीं देश के लघु, मध्यम उद्योग ही उसके ज्यादा भुक्तभोगी बनते थे। यह स्थिति अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाई है। हालांकि पिछले तीन दशक में लघु मध्यम उद्योग पहली बार सरकार की प्राथमिकता में अपनी महत्ता हासिल कर रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार की बजट घोषणा में एमएसएमई सेक्टर को लेकर की गई नई कानूनी व नीतिगत पहल भारत की अर्थव्यवस्था में इसे एक नया स्वरूप प्रदान करने में मददगार साबित होगी।

प्रतीकात्मक

(ईआरसी)

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
www.jagran.com
गुरुवार 15 अगस्त, 2024
10
बिजनेस

मारुति को मिला सीमा शुल्क से 3.8 करोड़ रुपये का नोटिस

नई दिल्ली : मारुति सुजुकी इंडिया को सीमा शुल्क प्राधिकरण से 3.8 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया, 'नोटिस में प्राधिकरण ने कंपनी से कुछ श्रेणी के सामान के आयात पर सीमा शुल्क छूट का दावा करने का कारण बताने और लागू ब्याज तथा जुर्माने के साथ 3,81,37,748 रुपये के शुल्क में अंतर का भुगतान करने को कहा है।' कंपनी ने कहा कि इस नोटिस के कारण वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। (प्रेट्र)

अधिग्रहण और विस्तार परियोजनाओं की मदद से हमें वित्त वर्ष 2027 तक अपनी सीमेंट निर्माण क्षमता के 20 करोड़ टन प्रति वर्ष पार कर जाने की उम्मीद है।

— कुमार मंगलम बिड़ला, चेयरमैन, अल्ट्राटेक सीमेंट

सेंसेक्स	79,105.88 ▲ 149.85	निफ्टी	24,143.75 ▲ 4.75	सोना प्रति दस ग्राम	₹73,150 ▲ ₹300	चांदी प्रति किलोग्राम	₹83,200 ▼ ₹300
डालर	₹83.94 ▼ ₹0.03	क्रूड (बैंट) प्रति बैरल	$ 81.17				

एक नजर में

जुलाई में 10.81 लाख टन पाम आयल का आयात

नई दिल्ली : जुलाई में भारत का पाम तेल आयात 10.81 लाख टन के उच्चस्तर पर पहुंच गया। हालांकि पिछले साल की समान अवधि में आयात किए 10.86 लाख टन पाम तेल के आयात से कुछ कम रहा। कुल वनस्पति तेल आयात में पाम तेल का हिस्सा 57 प्रतिशत था। जुलाई में वनस्पति तेल आयात 18.95 लाख टन रहा, जो एक साल पहले 17.71 लाख टन था। (प्रेट्र)

यूआइडीएआइ को पांच साल के लिए आयकर से छूट

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) की आय को 2027-28 तक पांच साल के लिए आयकर भुगतान से छूट दे दी है। प्राधिकरण को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान/ सब्सिडी, आरटीआइ शुल्क, निविदा शुल्क और सूचनाओं को अपडेट करने की एवज में मिलने वाला सेवा शुल्क पांच साल तक आयकर से मुक्त होगा। (प्रेट्र)

ओयो का 2023-24 में शुद्ध लाभ 229 करोड़ रुपये

नई दिल्ली : होटल कारोबार से जुड़े प्लेटफार्म ओयो का वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध लाभ 229 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने 'एक्स' पर बताया कि यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनके अनुमान 100 करोड़ रुपये से अधिक है। ओयो की समायोजित कर पूर्व आय 2023-24 में 215 प्रतिशत बढ़कर करीब 877 करोड़ रुपये तक पहुंच गई जो वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 277 करोड़ रुपये थी।' (प्रेट्र)

जुलाई में पीई और वीसी निवेश 2.7 अरब डालर पर

मुंबई : उद्यम पूंजी (वीसी) और निजी इक्विटी (पीई) कोषों का भारतीय इकाइयों में निवेश इस वर्ष जुलाई में घटकर 2.7 अरब डालर रह गया है। उद्योग लाबी समूह आइवीसीए और परामर्श कंपनी ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार, यह निवेश पिछले महीने जून के 4.6 अरब डालर से 42 प्रतिशत तथा पिछले साल जुलाई के 4.1 अरब डालर आंकड़े से 35 प्रतिशत कम है। (प्रेट्र)

थोक महंगाई से मिली राहत, लेकिन निर्यात की स्थिति बिगड़ी

बुधवार को देश की इकोनमी से जुड़े तीन आंकड़ें जारी हुए हैं। एक आंकड़ा थोक महंगाई को लेकर है जबकि दूसरा जुलाई महीने में देश के आयात-निर्यात का है। तीसरा आंकड़ा घरेलू बाजार में कारों की बिक्री को लेकर है। थोक महंगाई की दर जुलाई माह में घटकर 2.04 प्रतिशत पर आ गई है जो आरबीआइ व वित्त मंत्रालय दोनों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि इसी महीने निर्यात 1.2 प्रतिशत घटकर 33.98 अरब डालर पर आ गया है जबकि आयात में 7.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की नब्ज बताने वाले आटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री इसी महीने 2.5 प्रतिशत घट गई है। आटोमोबाइल सेक्टर देश के कुल मैन्यूफैक्चरिंग में 20 फीसद योगदान देता है।

सब्जियों की कीमतों में नरमी से घटी थोक मुद्रास्फीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: थोक मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर तीन महीने के निचले स्तर 2.04 प्रतिशत आ गई। खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों की कीमतों में नरमी इसकी प्रमुख वजह रही। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) आधारित मुद्रास्फीति में जुलाई में गिरावट आई है, जबकि जून तक लगातार चार महीने इसमें वृद्धि हुई थी। जून में 3.36 प्रतिशत थी। पिछले साल जुलाई में इसमें 1.23 प्रतिशत की गिरावट रही थी।

जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति 3.45 प्रतिशत रही, जो जून में 10.87 प्रतिशत थी। इसकी मुख्य वजह सब्जियों, अनाज, दालों और प्याज की कीमतों में मासिक आधार पर गिरावट रही। सब्जियों की कीमतों में जुलाई में 8.93 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि जून में इनमें 38.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। निर्मित उत्पाद समूह की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून 2024 में 1.43 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2024 में 1.58 प्रतिशत हो गई। ईंधन तथा बिजली की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर बढ़कर 1.72 प्रतिशत हो गई, जो जून 2024 में 1.03 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट इस महीने के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अनुरूप रही।

भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में निरंतर नरमी से उत्पादन स्तर की लागत कम होगी और देश में उपभोग मांग बढ़ेगी। -**संजीव अग्रवाल,** पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री

मुख्य (गैर-खाद्य विनिर्माण) डब्ल्यूपीआइ लगातार पांचवें महीने बढ़ता रहा, जो जुलाई 2024 में 1.2 प्रतिशत के साथ 17 महीने के उच्च स्तर को छू गया, हालांकि सूचकांक लगातार दूसरे महीने क्रमिक आधार पर संकुचित हुआ।

-**राहुल अग्रवाल,** वरिष्ठ अर्थशास्त्री, इक्रा

कच्चे तेल, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के आयात से बढ़ा व्यापार घाटा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत का वस्तुओं का निर्यात तीन महीने सकारात्मक दायरे में रहने के बाद जुलाई में सालाना आधार पर 1.2 प्रतिशत घटकर 33.98 अरब डालर रहा है। एक साल पहले इसी महीने में यह आंकड़ा 34.39 अरब डालर था। आयात जुलाई में लगभग 7.45 प्रतिशत बढ़कर 57.48 अरब डालर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 53.49 अरब डालर था। इस दौरान कच्चे तेल, चांदी और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात प्रमुख रूप से बढ़ा है।

कच्चे तेल का आयात 17.44 प्रतिशत बढ़कर जुलाई में 13.87 अरब डालर हो गया, वहीं चांदी का आयात 439 प्रतिशत उछाल के साथ 16.57 करोड़ डालर हो गया। आंकड़ों के अनुसार, व्यापार घाटा जुलाई में 23.5 अरब डालर रहा है। इसी साल जून में यह 21 अरब डालर और पिछले साल जुलाई में 19.3 अरब डालर था। इस दौरान चीन को निर्यात में 9.44 फीसद की गिरावट आई है जबकि वहां से होने वाले आयात में 13 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मा और इंजीनियरिंग निर्यात में क्रमशः 37.31 प्रतिशत, 8.36 प्रतिशत और 3.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष (2024-25) के पहले चार माह (अप्रैल-जुलाई) में निर्यात 4.15 प्रतिशत बढ़कर 144.12 अरब डालर पर पहुंच गया है, जबकि आयात 7.57 प्रतिशत बढ़कर 229.7 अरब डालर रहा है। पहले चार महीनों में व्यापार घाटा बढ़कर 85.58 अरब डालर हो गया है, जो पिछले साल समान अवधि में 75.15 अरब डालर था। अप्रैल-जुलाई में सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 117.35 अरब डालर रहा।

मौजूदा रुझानों को देखने से पता चलता है कि देश का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात पिछले साल के 778 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। वस्तु निर्यात में गिरावट का एक कारण पेट्रोलियम उत्पादों की मांग घटना है। पेट्रोलियम निर्यात 22.15 प्रतिशत घटकर 5.22 अरब डालर रह गया है।

-**सुनील बर्थवाल,** वाणिज्य सचिव

घरेलू बाजार में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में गिरावट

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री जुलाई, 2024 में 2.3 फीसद घट कर 3,41,510 रही है। वाहनों की बिक्री में इस कमी के लिए ग्राहकों की मांग के साथ ही कंपनियों की तरफ से कम आपूर्ति को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल, पिछले कुछ महीनों से बाजार की मांग से ज्यादा आपूर्ति कर रही थी और अब उन्होंने आपूर्ति कम दी है। भारतीय आटोमोबाइल सेक्टर के लिए पिछले दो साल काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन अब संकेत है कि मांग संकुचित हो रहा है। ऐसा हर दो वर्षों बाद होता है। सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि कार कंपनियों ने जुलाई, 2023 में अपने डीलरों को कुल 3,50,355 वाहनों की आपूर्ति की थी। इस महीने मोटरसाइकिलों की थोक बिक्री 12.5 फीसद (14,41,694) और स्कूटरों की बिक्री 29.2 फीसद (5,53,642) बढ़ी है।

मोदी से मिले फाक्सकान के चेयरमैन लियू

नई दिल्ली, प्रेट्र: अनुबंध पर आइफोन बनाने कंपनी फाक्सकान के चेयरमैन यंग लियू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और भारत में कंपनी की निवेश योजना पर चर्चा की।

मोदी ने इंटरनेट मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'होन हाई टेक्नोलाजी ग्रुप (फाक्सकान) के चेयरमैन यंग लियू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने भविष्य के क्षेत्रों में भारत द्वारा पेश किए जाने वाले शानदार अवसरों पर प्रकाश डाला। हमने कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भारत में उनकी निवेश योजनाओं पर भी बेहतरीन चर्चा की।' लियू को इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अनुमान है कि फाक्सकान भारत में 40,000 लोगों को रोजगार देगी।

फाक्सकान चेयरमैन यंग लियू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की● एएनआइ

बांग्लादेश के साथ व्यापार पर सरकार की नजर : वाणिज्य सचिव

नई दिल्ली, प्रेट्र: वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बुधवार को कहा कि भारत बांग्लादेश में स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों देशों के बीच सीमापार कारोबार को बेहतर करने के लिए कदम उठा रहा है। घरेलू निर्यातक बांग्लादेश के सियासी हालात को लेकर चिंतित हैं।

निर्यातक ऐसी आशंका जता चुके हैं कि बांग्लादेश के राजनीतिक संकट का द्विपक्षीय व्यापार पर असर देखने को मिलेगा। बर्थवाल ने संवाददाताओं से कहा, 'बांग्लादेश में स्थिति तेजी से सुधर रही है और हम सीमापार होने वाले व्यापार पर नजर रख रहे हैं। हमें लगता है कि जो भी व्यवधान थे, उन्हें काफी हद तक दूर कर लिया गया है। हम यह भी मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में सुधार होना चाहिए।

आइटी शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स में 150 अंक की तेजी

मुंबई, प्रेट्र: स्थानीय शेयर बाजारों में दो दिन से जारी गिरावट पर बुधवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 150 अंक चढ़ गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से वहां के बाजारों में तेजी के बीच सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में मजबूती रही। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 149.85 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79,105.88 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 272.91 अंक तक चढ़ गया था।

निफ्टी भी मामूली 4.75 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,143.75 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खनन शेयरों में गिरावट रही। शीर्ष अदालत ने खनिज संपन्न राज्यों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 वर्ष में चरणबद्धत तरीके से रायल्टी तथा कर पर एक अप्रैल, 2005 से बकाया लेने की बुधवार को अनुमति दे दी। इस फैसले से एनएमडीसी जहां छह प्रतिशत नीचे आया वहीं हिंद कापर चार प्रतिशत तथा नाल्को 2.7 प्रतिशत टूटा।

वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच घरेलू बाजार एक सीमित दायरे में रहा। आइटी सूचकांक बढ़त में रहा। यह अमेरिका में आज जारी होने वाले खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े के बेहतर रहने की उम्मीद को दर्शाता है। इससे फेडरल रिजर्व की नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश बढ़ सकती है। -**विनोद नायर,** रिसर्च हेड, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज

अमेरिका में तीन साल के निचले स्तर पर महंगाई

वाशिंगटन, एपी: अमेरिका में जुलाई में मुद्रास्फीति तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह इस बात का संकेत है कि पिछले चार दशकों में सबसे खराब महंगाई का दौर अब धीमा पड़ रहा है। मुद्रास्फीति के नीचे आने से सितंबर में होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दर में कटौती की संभावना है।

श्रम विभाग द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि जून से जुलाई के बीच उपभोक्ता कीमतों में सिर्फ 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इससे पहले जून में चार साल में पहली बार महंगाई में गिरावट दर्ज की गई थी। एक साल पहले से तुलना करें तो कीमतों में 2.9% की वृद्धि हुई जो जून के 3% से कम है। यह मार्च 2021 के बाद से साल-दर-साल मुद्रास्फीति का सबसे कम आंकड़ा है। अमेरिका में महंगाई राष्ट्रपति चुनाव का केंद्रीय मुद्दा है।

राष्ट्रीय फलक

दो चरणों में खुलेगा आइजीआइ टर्मिनल-1, स्पाइसजेट से शुरुआत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- बंद पड़े टर्मिनल 1 पर शुरू होगी वायुयानों व यात्रियों की हलचल
- 17 अगस्त से स्पाइसजेट व 2 सितंबर से शुरू होगी इंडिगो उड़ानों की आवाजाही

28 जून को फोरकोर्ट की छत टूटकर गिरने की घटना के बाद से बंद पड़े आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी एजेंसी डायल का कहना है कि यहां से पहले की तरह ही इंडिगो व स्पाइसजेट की उड़ानें संचालित होंगी। इनमें वे उड़ानें ही हैं, जो टर्मिनल 1 के बाद होने के बाद टर्मिनल-2 या 3 पर स्थानांतरित कर दी गई थीं। 17 अगस्त से टर्मिनल 1 से सबसे पहले स्पाइसजेट की उड़ानों का संचालन होगा। शुरुआत में यहां से स्पाइसजेट की 13 उड़ानें यहां से संचालित होंगी। इन उड़ानों को टर्मिनल 3 से यहां स्थानांतरित किया जा रहा है।

2 सितंबर से इंडिगो की उड़ानें होंगी शुरू

स्पाइसजेट के बाद जिस दूसरी एयरलाइंस की उड़ानों का यहां से संचालन होगा, वह इंडिगो है। टर्मिनल बंद होने से पहले भी यहां से इंडिगो व स्पाइसजेट की उड़ानें संचालित होती थीं। डायल के अनुसार 2 सितंबर से यहां इंडिगो की उड़ानों का संचालन शुरू होगा। शुरुआत में 34 उड़ानें यहां से संचालित होंगी। अभी इंडिगो की ऐसी उड़ानें जो टर्मिनल-1 से संचालित होती थीं, उन्हें स्थानांतरित कर टर्मिनल-2 पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब ये उड़ानें वापस टर्मिनल-1 से संचालित होंगी।

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले फारूक के खिलाफ ईडी का आरोपपत्र खारिज

राज्य ब्यूरो ● जागरण जम्मू

- याचिकाकर्ता का था तर्क, ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता मामला
- सीबीआइ भी इस मामले में वर्ष 2018 में दायर कर चुकी है आरोपपत्र

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में 43.69 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र को खारिज कर दिया है। इस मामले में सीबीआइ वर्ष 2018 में ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। सीबीआइ जांच के आधार पर ईडी ने मामले में जांच शुरू की थी।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव कुमार की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कोई आरोप नहीं बनता, इसलिए ईडी की ओर से दायर आरोपपत्र व पूरक आरोपपत्र को रद किया गया है। ईडी ने आरोपपत्र में नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा व मीर मंजूर गजंफ्फर समेत कुछ अन्य को आरोपित के रूप में नामित किया था। आरोप पत्र को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सात अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी का प्रतिनिधित्व वर्चुअल माध्यम से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया। अहसान अहमद मिर्जा व मीर मंजूर गजंफ्फर की ओर से शारिक जे रियाज अदालत में पेश हुए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इस मामले में कोई अपराध नहीं हुआ है। साथ ही, मामला ईडी के अधिकार क्षेत्र नहीं है।

फारूक अब्दुल्ला। फाइल

यह था मामला

फारूक अब्दुल्ला उस समय जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उनके अलावा पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा व मीर मंजूर गजंफ्फर व पूर्व अकाउंटेंट बशीर अहमद मिसगर, गुलजार अहमद बेग के खिलाफ सीबीआइ ने चार्जशीट दायर की थी। इसमें आरोप था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट के प्रसार के लिए 2002 से 2011 तक दिए गए फंड में से 43.69 करोड़ की हेराफेरी हुई है।

गुरुग्राम में युवती की हत्या, घामड़ोज टोल प्लाजा के पास मिला शव

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

- 12 अगस्त को पुलिस ने बरामद किया था शव, बुधवार को हुई पहचान
- यूपी के फिरोजाबाद की थी युवती, नौकरी की तलाश में आई थी गुरुग्राम

गुरुग्राम में नौकरी की तलाश में आई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली युवती की हत्या कर दी गई। उसका शव भोंडसी थाना क्षेत्र में घामड़ोज टोल प्लाजा के पास खाली जमीन पर पाया गया। बुधवार को स्वजन के आने के बाद शव की पहचान हो पाई। थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव डिकंपोज होने से यह पता नहीं चल सका कि युवती की हत्या कैसे की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो पाएगा।

भोंडसी थाना पुलिस ने बताया कि 12 अगस्त की शाम कंट्रोल रूम में एक शव बरामद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद एफएसएल और फारेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शव डिकंपोज होने की स्थिति में यह पता नहीं लग सका कि उसकी मौत कैसे हुई। शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सुदामानगर निवासी परिवार के लोग आए। उन्होंने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दी। थाना पुलिस ने फोटो और पूछताछ के आधार पर शव की पहचान मुस्कान के रूप में की। मां गीता देवी ने बताया कि मुस्कान कुछ दिन पहले नौकरी की तलाश में भोंडसी के गोवर्धन कुंज निवासी अपनी दोस्त के यहां आई थी। जब दोस्त से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मुस्कान 10 अगस्त की रात उसके वहां से निकली, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। थाना पुलिस ने परिवार की शिकायत पर केस दर्ज किया है।

निठारी कांड : कोली को बरी करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सीबीआइ की ओर से दाखिल उस नई याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया, जिसमें 2006 के नोएडा के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में आरोपित सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सीबीआइ की अर्जी को हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में विचाराधीन अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने 19 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर सीबीआइ और उप्र सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। उसने इन याचिकाओं पर कोली को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। मई में शीर्ष कोर्ट ने एक पीड़ित के पिता की उस याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई थी, जिसमें कोली को बरी करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती

- सीबीआइ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले साल दिए गए फैसले को शीर्ष कोर्ट में दी है चुनौती
- 2006 के नोएडा के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड में पंढेर व कोली पर दर्ज किए गए थे कुल 19 केस

दी गई थी। इस मामले में सत्र अदालत ने 28 सितंबर 2010 को सुनाए गए फैसले में मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया था जबकि उसके नौकर कोली को मौत की सजा दी थी। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में नाकाम रहा। जांच सही ढंग से नहीं हुई।

कोली को 12 मामलों और पंढेर को दो मामलों में सुनाई गई मौत की सजा को पलटते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के तय मानदंडों पर दोनों आरोपितों का अपराध साबित करने में नाकाम रहा और जांच जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात से कम नहीं थी। पंढेर और कोली को हत्या एवं बलात्कार का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने कोली व पंढेर की ओर से दायर याचिकाओं पर सहमति जताई थी, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद में सीबीआइ अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को चुनौती दी थी। बता दें कि पंढेर व कोली के खिलाफ 2007 में 19 मामले दर्ज किए गए थे। सुबूतों की कमी के कारण सीबीआइ ने तीन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। बाकी 16 मामलों में से कोली को तीन में बरी कर दिया गया था।

बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को रद के आदेश पर रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एड-टेक बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को रद कर दिया गया था और बीसीसीआइ के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाये के निपटान को मंजूरी दे दी गई थी।

चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एनसीएलटी के आदेश पर ये रोक लगाई। इससे पहले अमेरिका स्थित लेनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी ने न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किय। पीठ ने बीसीसीआइ को बायजू से प्राप्त 158.9 करोड़ को एस्क्रो खाते में रखने का निर्देश दिया। बीसीसीआइ का प्रतिनिधित्व कर रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया।

****

वित्तीय साधन बच्चे की कस्टडी देने का एकमात्र आधार नहीं : कोर्ट

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली

साकेत कोर्ट ने कहा कि वित्तीय साधन बच्चे की कस्टडी माता-पिता को देने का एकमात्र आधार नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने दो बच्चों की अंतरिम कस्टडी उनकी मां को देने आदेश दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सना खान घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण (पीडब्ल्यूडीवी) अधिनियम के प्रविधान के तहत एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। याचिका में महिला ने अपनी नाबालिग बेटी व बेटे की कस्टडी की मांग की थी। पति ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह एक प्यार करने वाला पिता है और बच्चों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है।

कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी के मुद्दों पर निर्णय लेते समय उनके सर्वोपरि कल्याण का आकलन, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह बच्चों का पिता एक साधनसंपन्न व्यक्ति है। वह अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवनशैली प्रदान करने में सक्षम है। यह भी निर्विवाद है कि किसी पक्ष की वित्तीय क्षमता एक अनिवार्य पहलू है। मगर दुख की बात है कि वित्तीय साधन बच्चों की कस्टडी का फैसला करने का एकमात्र आधार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों का बच्चों पर समान रूप से अच्छा दावा है, लेकिन बच्चों की कम उम्र को देखते हुए संभावना शिकायतकर्ता या मां के पक्ष में अधिक है। अगर बच्चों को उनके जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक वर्षों में उनकी मां की संगत से वंचित किया जाता है, तो यह उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए हानिकारक होगा। कोर्ट ने कहा कि मां बच्चों की देखभाल करने के लिए बिल्कुल सही है। अगर उसे अंतरिम कस्टडी दी जाती है तो बच्चों का कल्याण सुनिश्चित होगा।

बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन की होगी जांच

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन का सर्वे कराकर जांच कराई जाएगी। अगर किसी जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध तरीके से दलालों या माफिया द्वारा बेची गई है तो उसकी जांच कराकर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान से सूचना भवन में पत्रकारों के सवाल पर अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए लागू योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी दे रही है। शिक्षा व रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, उर्दू भाषा का विकास तथा उद्यमी योजनाओं का लाभ समेत अन्य योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

मंत्री मो. जमा खान ने बताया कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत 12 जिलों में भूमि चिन्हित की है] जहां आवासीय विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू होगा।

बांग्लादेश में आश्वासन के बाद भी हिंदू परिवार का घर जलाया

ठाकुरगांव जिले में भीड़ ने मंगलवार को घटना को दिया अंजाम

पूरे देश में 278 स्थानों पर हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। मंगलवार देर शाम ठाकुरगांव जिले के फाराबाड़ी मंदिरपाड़ा गांव में उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार का घर जला दिया। हमले के शिकार हुए परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है।

बांग्लादेश में कुछ हद तक स्थिति में सुधार के बाद दूरदराज के इलाकों में हुई घटनाओं की जानकारी अब सामने आ रही है। राष्ट्रीय हिंदू महागठजोड़ द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में हिंदुओं पर हमलों की 278 घटनाएं हुई हैं। मंगलवार को हुई घटना में कालेश्वर बर्मन का घर जलाया गया है। उपद्रवियों का हमला होते ही बर्मन के आसपास रहने वाले लोग हरकत में आ गए और उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षित घर से निकाल लिया। इसके बाद पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। ठाकुरगांव के थाना प्रभारी एबीएम फिरोज वहीद ने कहा है कि पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। अब हमले में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। इससे कुछ दिन पहले इसी इलाके के नीमबाड़ी कमरपाड़ा गांव में उपद्रवियों द्वारा अनंत बर्मन का घर जलाया दिया गया था।

हसीना के खिलाफ अब दर्ज हुआ अपहरण का मुकदमा

बांग्लादेश के पूर्व विधि मंत्री अनीसुल हक को गिरफ्तार कर बुधवार को ढाका में कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान लोगों ने उन पर अंडे फेंके। उन्हें बचाने के लिए हेलमेट पहनाया गया था। एपी

बांग्लादेश में अपदस्थ पीएम शेख हसीना और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बुधवार को एक और मामला दर्ज किया गया। यह मामला 2015 में एक अधिवक्ता के अपहरण का है। इस्तीफे के बाद हसीना के खिलाफ दर्ज किया गया यह दूसरा मामला है। नया मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सोहेल राणा ने दर्ज कराया है, इसमें उनके साथ हुई घटना का उल्लेख है। यह मामला ढाका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट फरजाना शकीला सुमू चौधरी के आदेश पर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। मामले में हसीना सरकार के कई पूर्व मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को आरोपित किया गया है। इससे पहले मंगलवार को हसीना और छह अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक सब्जी विक्रेता की हत्या का आरोप लगाया गया है। यह हत्या बीती जुलाई में हुई थी। पुलिस ने इन मामलों में हसीना सरकार में मंत्री रहे अनीसुल हक और पीएम के सलाहकार रहे सलमान एफ रहमान को गिरफ्तार किया है। इस बीच बांग्लादेश में आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए एक छात्र के पिता बुलबुल कबीर ने शेख हसीना व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें हसीना व अन्य पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया है। जुलाई व अगस्त में हुए आंदोलन के दौरान हुई मौतों और उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के विशेषज्ञों का दल जल्द ही बांग्लादेश आएगा। यह दल पीड़ितों से मुलाकात कर आरोपों की सत्यता की जांच करेगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने संबंधी आरोप को हास्यास्पद व झूठा करार दिया है।

भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है बांग्लादेश

- द्विपक्षीय संबंधों में विकास की इच्छुक है अंतरिम सरकार
- अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार
- भारतीय उच्चायुक्त वर्मा की प्रभारी विदेश मंत्री हुसैन से वार्ता

बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बुधवार को ढाका में अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रभारी मुहम्मद तौहीद हुसैन से भेंट की। एएनआइ

ढाका, प्रेट्र: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है और द्विपक्षीय सहयोग में विकास करना चाहती है पर हाल ही में दिया पूर्व पीएम शेख हसीना का बयान इस लिहाज से सकारात्मक नहीं है। यह बात अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रभारी मुहम्मद तौहीद हुसैन ने कही है।

हुसैन का यह बयान तब आया है जब ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने उनसे भेंट की और द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। इस बातचीत में बांग्लादेश के हाल के घटनाक्रम और हिंदुओं व मंदिरों पर हमलों की भी चर्चा हुई है। हुसैन ने कहा, बांग्लादेश भारत से घनिष्ठ संबंध रखते हुए कार्य करना चाहता है और द्विपक्षीय संबंधों में और विकास करने का इच्छुक है। संबंधों में यह विकास दोनों देशों के लोगों के मेलमिलाप और सुविधाओं में विकास पर आधारित होना चाहिए। प्रभारी विदेश मंत्री ने कहा,अंतरिम सरकार बांग्लादेश में सभी समुदायों के लोगों के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का वातावरण बनाने को संकल्पबद्ध है। अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सरकार सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों व मूलवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उनके खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तौहीद हुसैन ने कहा, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए संकल्पबद्ध है और जल्द ही स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए वातावरण बनाएगी। वार्ता में हुसैन ने आपसी सहयोग में मजबूती के लिए तीन बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता जताई। ये बिंदु हैं- सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों पर हमलों को रोका जाए, तीस्ता नदी जल बंटवारे का समझौता लागू किया जाए और बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु रखी जाए।

हसीना का बयान दोनों देशों के संबंधों के लिए ठीक नहीं

शेख हसीना द्वारा हाल ही दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए तौहीद हुसैन ने कहा कि भारत में प्रवास के दौरान हसीना का हाल का बयान दोनों देशों के संबंधों के लिए सकारात्मक नहीं है। हसीना ने मंगलवार को दिए बयान में बांग्लादेश की जनता से न्याय की मांग की थी। कहा था कि जो लोग हाल के दिनों में हत्या-तोड़फोड़ जैसी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं उनकी पहचान होनी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हसीना ने 15 अगस्त के दिन शांति रखने का आह्वान भी किया है। इसी दिन उनके पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की 1975 में ढाका में हत्या हुई थी। हसीना का यह बयान उनके बेटे सजीब ने अमेरिका से एक्स पर पोस्ट किया था।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारतीय उच्चायुक्त के जरिये दोनों देशों के बीच यह पहली औपचारिक वार्ता थी। इससे पहले उच्चायुक्त वर्मा ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था।

पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे किशिदा, जापान को नया पीएम मिलेगा

टोक्यो, एपी : जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि वह सितंबर में होने वाले पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे जापान को नए पीएम मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि बिना जनता के विश्वास के राजनीति नहीं चल सकती।

फुमियो किशिदा। एएफपी

उन्होंने बुधवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेता के रूप में दोबारा चुनाव न लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। किशिदा को 2021 में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और उनका तीन साल का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है।

किशिदा के दौड़ से बाहर होने का मतलब है कि पार्टी का वोट जीतने वाला नया नेता प्रधानमंत्री के रूप में उनका उत्तराधिकारी होगा, क्योंकिलिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का संसद के दोनों सदनों को नियंत्रण है। पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किशिदा के समर्थन में गिरावट आई है। सितंबर में होने वाले मतदान में भाग न लेना यह दिखाने का प्रयास होगा कि उनकी पार्टी बेहतरी के लिए अपने आपको बदल रही है और एक नए नेता को मौका दिया जा रहा है। किशिदा ने कहा कि वह नए नेता का समर्थन करेंगे।

ईमानदारी और अनुशासन के मामले में हैरिस को ट्रंप पर बढ़त

वाशिंगटन, एपी : द एसोसिएटेड प्रेस और एनओआरसी सेंटर फार पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के एक सर्वे में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त हासिल की है। सर्वे में शामिल अमेरिकियों ने ईमानदारी जैसे नेतृत्व गुणों के मामले में हैरिस को बढ़त दी है। हालांकि, अर्थव्यवस्था और अप्रवासन के मामले में ट्रंप पर अधिक भरोसा जताया है।

लगभग आधे अमेरिकियों का कहना है कि लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध और अनुशासित ऐसे गुण हैं, जो हैरिस को बढ़त दिलाती है। 10 में से चार लोगों का कहना है कि हैरिस आम लोगों की परवाह करती हैं, जबकि 10 में से तीन यह बात ट्रंप के संबंध में कही है। 10 में से चार ने हैरिस को ईमानदार बताया है।

ट्रंप अपने अभियान के दौरान खुद को मजबूत नेता के रूप में प्रचारित करते रहे हैं, जो देश के सामने आने वाले संकटों से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी नेता व्हाइट हाउस में हैरिस का सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन सर्वे के अनुसार, उस विशेषता के आधार पर उन्हें अमेरिकियों से कोई लाभ नहीं है। अमेरिका के 10 में से चार लोग ट्रंप को मजबूत नेता के रूप में देखते हैं। लगभग यही अनुपात हैरिस के बारे में भी यही मत रखता है। 10 में से चार का कहना है कि ट्रंप किसी संकट से निपटने में सक्षम हैं। वहीं लोगों का कहना है कि हैरिस ऐसा करने में बेहतर स्थिति में हैं। अमेरिकी इस बात को लेकर लगभग समान रूप से विभाजित हैं कि वे नवंबर में जीतने में किसे अधिक सक्षम मानते हैं।

- आधे लोगों ने हैरिस को लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध और अनुशासित बताया

- अर्थव्यवस्था और अप्रवासन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर अधिक भरोसा

गुप्त धन मामले में जज ने हटने से किया इन्कार : डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन मामले में झटका लगा है। न्यायाधीश जुआन एम मर्चन ने केस से हटने से इन्कार कर दिया और कहा कि ट्रंप की मांग अशुद्धियों और निराधार दावों से भरी थी। यह तीसरा मौका है जब न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान रिपब्लिकन उम्मीदवार के वकीलों के ऐसे अनुरोध को खारिज कर दिया है। तीनों बार, उन्होंने तर्क दिया कि मैनहट्टन में न्यायाधीश मर्चन के हितों का टकराव है, क्योंकि उनकी बेटी डेमोक्रेट के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करती है।

यूक्रेन ने ड्रोन से चार रूसी हवाई अड्डों पर बोला हमला

कीव, रायटर : यूक्रेन ने रात भर के दौरान चार रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर ड्रोन हमला बोला। रूस के बोरोनिश, कुर्स्क, सवासलेका और बोरिसोग्लबस्क हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। हमले का उद्देश्य यूक्रेन पर बम हमलों के लिए युद्धक विमानों का उपयोग करने की मास्को की क्षमता को कमजोर करना था। रायटर का कहना है कि दावे की तुरंत स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। खार्किव के स्थानीय गवर्नर ने कहा कि कुर्स्क में हमले के बाद से रूसी बलों ने यूक्रेन के उत्तरपूर्वी खार्किव में सीमावर्ती बस्तियों पर गाइडेड बम हमलों की संख्या कम कर दी है।

साथ ही, रूस के बेलगोरोद सीमा क्षेत्र में यूक्रेन की ओर से भारी गोलाबारी के कारण बुधवार को आपातकाल घोषित कर दिया गया। बेलगोरोद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने स्थिति को बेहद कठिन और तनावपूर्ण बताया। हमलों ने घरों को नष्ट कर दिया और नागरिक हताहत हुए। वहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई सुरक्षा प्रणाली ने 117 यूक्रेनी ड्रोन और चार मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। इस बीच, रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा सुविधाओं पर हमला बोला है।

- युद्धक विमानों के उपयोग की क्षमता को कमजोर करना यूक्रेन का लक्ष्य
- रूस के बेलगोरोद सीमा क्षेत्र में भी यूक्रेन की ओर से भारी गोलाबारी

रूस-यूक्रेन सीमा पर स्थित सुमी क्षेत्र में अपने बख्तरबंद वाहन के बाहर बैठे यूक्रेनी सैन्यकर्मी। एपी

जेलेंस्की ने कहा, रूस में तेजी से बढ़ रही सेना : यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि कीव की सेनाएं कुर्स्क में बढ़त हासिल कर रही हैं और बुधवार को एक से दो किलोमीटर और आगे बढ़ गई है। छह अगस्त को हजारों यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुस गई थी। इस अवधि में 100 से अधिक रूसी युद्ध बंदी बनाए गए हैं। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूसी शहर सुद्जा, जो यूक्रेन के माध्यम से यूरोप में रूसी प्राकृतिक गैस का ट्रांसशिपमेंट केंद्र है, पूरी तरह से यूक्रेन के नियंत्रण में है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 1,000 वर्ग किमी क्षेत्र उसके नियंत्रित में है।

जो बाइडन बोले, पुतिन के लिए वास्तविक दुविधा पैदा हो गई है

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि रूस में यूक्रेन की सैन्य घुसपैठ ने व्लादिमीर पुतिन के लिए वास्तविक दुविधा पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी इस कदम के बारे में यूक्रेनियन के साथ लगातार संपर्क में हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कुर्स्क पर हमले का मुख्य लक्ष्य रूसी सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुलाने के लिए मजबूर करना है।

भारत ने नागरिकों के लिए जारी की सलाह

मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को रूस के ब्रांस्क, बेलगोरोद और कुर्स्क क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों सहित भारतीय नागरिकों के लिए सलाह जारी की है। दूतावास ने कहा कि हाल की घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने और अस्थायी रूप से इन क्षेत्रों से दूसरे स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है।

न्यूयार्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी को शामिल करने का विरोध

न्यूयार्क, प्रेट्र : न्यूयार्क में 18 अगस्त को 42वीं वार्षिक इंडिया डे परेड का आयोजन होगा। इसमें राम मंदिर की झांकी भी शामिल की जाएगी। हालांकि, इस फैसले को लेकर विरोध किया जा रहा है। भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद (आइएएमसी) ने कहा है कि परेड के लिए प्रस्तावित झांकी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के महिमामंडन का प्रयास है और यह सांस्कृतिक या धार्मिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि मुस्लिम विरोधी नफरत और कट्टरता का उत्सव है। एक समूह की ओर से न्यूयार्क के गवर्नर कैथी होचुल और मेयर एरिक एडम्स को पत्र लिखकर इंडिया डे परेड में झांकी शामिल करने की निंदा करने और झांकी का विरोध करने का आग्रह किया गया है।

वहीं, फेडरेशन आफ इंडियन एसोसिएशन (एफआइए) के चेयरमैन अंकुर वैद्य ने कहा कि यह परेड पिछले चार दशकों से आयोजित की जा रही है। इसके आयोजन के लिए समर्थक कड़ी मेहनत करते हैं। इस बार शांतिपूर्ण

- न्यूयार्क में 18 अगस्त को 42वीं वार्षिक इंडिया डे परेड का आयोजन होगा
- झांकी को बाबरी मस्जिद विध्वंस के महिमामंडन का प्रयास बता रहे

सामुदायिक उत्सव के आयोजन के लिए खुद को भारी जांच के दायरे में पा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण और नफरत भरी सूचना फैलाई जा रही है। विविधता का जश्न मनाने की हमारी दीर्घकालिक परंपरा के बावजूद अब हम सांप्रदायिक नफरत और कट्टरता का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने, लोगों को गुमराह करने और घृणा फैलाने वाली बातों का हिंदू समुदाय से दृढ़ता से विरोध करने का आग्रह किया है।

थाइलैंड के पीएम श्रेथा थाविसिन को नैतिकता के उल्लंघन पर कोर्ट ने हटाया

बैंकाक, एपी : थाइलैंड की एक अदालत ने बुधवार को पीएम श्रेथा थाविसिन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया। कोर्ट ने श्रेथा को जिस मामले में दोषी ठहराया है उसमें एक कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति शामिल है, जिसे एक कोर्ट के अधिकारी को घूस देने के प्रयास में जेल में डाल दिया गया था। जब तक संसद नए पीएम को मंजूरी नहीं देती, तब तक कैबिनेट कार्यवाहक आधार पर बनी रहेगी। संसद के पास पद भरने की समय सीमा तय नहीं है। अप्रैल में कैबिनेट फेरबदल में श्रेथा ने पिचिट चुएनबान को पीएम कार्यालय का मंत्री नियुक्त किया था। पिचिट को 2008 में अदालत की अवमानना में छह माह की जेल हुई थी। उन्होंने पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा से जुड़े मामले में एक जज को रिश्वत देने की कोशिश की थी।

श्रेथा थाविसिन। एएफपी

अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे मलेशिया के पीएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटे भारत के दौरे पर अगले हफ्ते मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम आने वाले हैं। इब्राहिम की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व भारत के वांछित इस्लामिक धार्मिक प्रचारक जाकिर नाइक के मलेशिया में शरण लिए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। मलेशिया के पूर्व पीएम महाथिर मोहम्मद के कश्मीर और नागरिकता कानून पर गलत टिप्पणी करने की वजह से भी रिश्ते बिगड़ गए थे। हालांकि पीएम इब्राहिम ने भारत के साथ रिश्तों को सुधारने को लेकर कई प्रयास किए हैं। इस महीने की शुरुआत में विएतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन्ह नई दिल्ली आये थे और अब मलेशियाई पीएम का यहां आना बता रहा है कि इस क्षेत्र के देश भी भारत के साथ संबंधों को काफी तवज्जो दे रहे हैं।

कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 19 व 20 अगस्त को नई दिल्ली में होंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दो चरणों में शीर्षस्तरीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के समक्ष कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसमें एक समझौता भारतीय प्रशिक्षित कामगारों को मलेशिया में रोजगार के अवसर देने से संबंधित भी होगा। यह समझौता मलेशिया में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा करने में मदद करेगा। बताया जा रहा है कि हाल के वर्षों में कई मलेशियाई कंपनियां भारत से प्रशिक्षित व गैर-प्रशिक्षित कामगारों को ले जा रही हैं।

- भगोड़े जाकिर के मलेशिया के शरण लेने, कश्मीर पर पूर्व पीएम मोहम्मद के बयान से रिश्तों में आई थी तल्खी
- प्रधानमंत्री मोदी के साथ शीर्षस्तरीय वार्ता करेंगे, कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना

अनवर इब्राहिम। फाइल

खासतौर पर जब से वैश्विक स्तर पर 'चीन प्लस वन' नीति के तहत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मलेशिया में संयंत्र लगाने शुरू किए हैं तब से वहां भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। साइबर फ्राड को रोकने में एक दूसरे की मदद करने और स्थानीय मुद्रा में कारोबार के अवसरों को साथ मिलकर तलाशने संबंधी दो अन्य समझौते भी होंगे।

वर्ष 2018 के बाद यह किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में भगोड़े जाकिर नाइक का मामला भी उठने की संभावना है। नाइक के खिलाफ भारत में मनी लांड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे मामले दर्ज हैं। नाइक के अभी भी मलेशिया की सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लेने की सूचना आती रहती हैं।

फ्रांस में दो राफेल विमान हवा में टकराए

पेरिस, आइएएनएस : फ्रांस की सेना के दो राफेल लड़ाकू विमान बुधवार दोपहर हवा में टकरा गए। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी पुष्टि की। एक पायलट सुरक्षित है जबकि दूसरे पायलट की तलाश अभी जारी है। फ्रांसीसी समाचार चैनल बीएफएमटीवी के अनुसार, दो विमानों में से एक का पायलट टक्कर से पहले ही बाहर निकल गया, जबकि दूसरे विमान में मौजूद प्रशिक्षक और पायलट अभी भी लापता हैं। फ्रांसीसी सेना द्वारा खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सैन्य अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजना का विरोध

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बुधवार को चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन करते लोग। यह प्रदर्शन रेम्पांग द्वीप के निवासियों ने चीन द्वारा वित्तपोषित रेम्पांग इको-सिटी परियोजना के विरोध में किया। परियोजना के कारण द्वीप के लगभग 7500 निवासियों को बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। एएफपी

पाक में ईशनिंदा मामले में 25 वर्ष की सजा

करांची, प्रेट्र : पाकिस्तान की अदालत ने एक शख्स को ईशनिंदा मामले में 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि उसने खुद को पैगंबर घोषित किया था। सिंध प्रांत में उसके खिलाफ जेल में ट्रायल पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। शख्स के धर्म और नाम की जानकारी नहीं दी गई है। उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

न्यायाधीश ने कहा,सजा कम करने वाली परिस्थितियों के आधार पर दी गई है। उन्होंने कहा कि मौत की सजा देने का कोई ठोस सुबूत नहीं मिला। शख्स को ईशनिंदा कानून के तहत तब गिरफ्तार किया गया, जब महबूब अली नाम के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि एक अप्रैल 2018 को उसने उसके सामने खुद को पैगंबर घोषित किया था। गवाह के तौर पर उसने चार लोगों को पेश किया। पाकिस्तान में रहने वालों अल्पसंख्यकों के खिलाफ अक्सर ईशनिंदा कानून का गलत इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है।

****

आज होने वाली गाजा संघर्ष विराम वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा हमास

काहिरा, रायटर : हमास ने बुधवार को कहा कि वह कतर में गुरुवार को होने वाली गाजा युद्धविराम वार्ता के नए दौर में हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि, एक अधिकारी ने कहा, मध्यस्थों को बाद में फलस्तीनी समूह के साथ परामर्श की उम्मीद है। अमेरिका ने कहा, उसे उम्मीद है कि गुरुवार को दोहा में योजना के अनुसार वार्ता आगे बढ़ेगी और युद्धविराम समझौता अब भी संभव है। साथ ही चेतावनी दी कि व्यापक युद्ध को रोकने के लिए प्रगति की तत्काल आवश्यकता है।

इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पश्चिम एशिया की यात्रा स्थगित कर दी है। यात्रा मंगलवार से शुरू होने वाली थी। तीन वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने कहा, गाजा में केवल युद्धविराम समझौता ही ईरान को इजरायल के खिलाफ सीधी जवाबी कार्रवाई से रोकेगा। सरकार के प्रवक्ता डेविड मेन्सर ने कहा, 'फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए इजरायल 15 अगस्त को वार्ता दल भेजेगा।'' प्रतिनिधिमंडल में इजरायल के खुफिया प्रमुख डेविड बार्निया, घरेलू सुरक्षा सेवा के प्रमुख रोनेन बार आदि शामिल हैं।

- फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इजरायल वार्ता के लिए दल भेजेगा
- अमेरिका ने कहा, व्यापक युद्ध को रोकने के लिए वार्ता में प्रगति की आवश्यकता

हमास ने बातचीत के वास्तविक नतीजे आने की संभावना पर संदेह व्यक्त किया है और इसमें रुकावट डालने के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। वहीं, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास नेता याह्या सिनवार किसी समझौते पर मुहर लगाने में मुख्य बाधा रहे हैं। हालांकि, वार्ता से हमास की अनुपस्थिति प्रगति की संभावनाओं को खत्म नहीं करती है, क्योंकि इसके मुख्य वार्ताकार खलील अल-हया दोहा में हैं और समूह के पास मिस्र और कतर के साथ खुले चैनल हैं।

अमेरिका ने इजरायल को 20 अरब डालर के हथियार बेचने की मंजूरी दी : विदेश विभाग ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका ने इजरायल को 20 अरब डालर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है,जिसमें लड़ाकू विमान और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं।

गाजा में इजरायली हमलों में 17 लोग मारे गए : गाजा पर रात भर और बुधवार को इजरायली हमलों में पांच बच्चों सहित 17 लोग मारे गए। इन हमलों में नुसीरत शरणार्थी शिविर और पास के मघाजी शरणार्थी शिविर वाले क्षेत्र में घरों को निशाना बनाया गया। वहीं, उत्तरी वेस्ट बैंक के तुबास और तम्मुन में इजरायली सेना द्वारा पांच फलस्तीनियों को मार गिराया गया।

दैनिक जागरण
राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 15 अगस्त, 2024
स्पोर्ट्स
12
www.jagran.com

भारतीय टीम के पास मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी है जिससे भारत आस्ट्रेलिया की सरजमीं पर इस बार जीत की हैट्रिक लगा सकता है। टीम के पास बुमराह, शमी, सिराज, अश्विन, जडेजा जैसे खिलाड़ी हैं। — रवि शास्त्री, पूर्व भारतीय कोच

डेविस कप टीम के कोच जीशान अली ने पद छोड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्टाकहोम में स्वीडन के विरुद्ध मुकाबले से पहले भारतीय डेविस कप टीम के कोच जीशान अली ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जीशान ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वह 11 साल से इस टीम के कोच रहे हैं और पाकिस्तान के विरुद्ध ऐतिहासिक मुकाबले में कप्तान भी थे। जीशान पहली बार 2013 में नंदन बाल की जगह दक्षिण कोरिया के मुकाबले से पहले टीम के कोच बने थे।

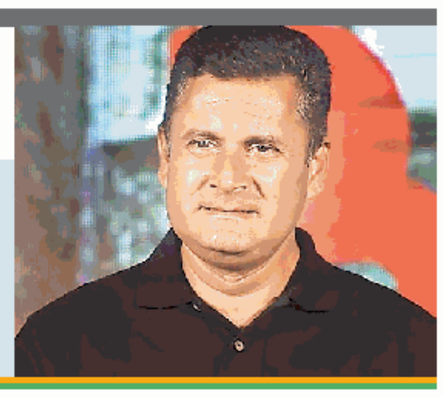

श्रीमद्भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करती हूं : मनु भाकर

स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी मनु भाकर का कहना है कि आप कोई भी सपना देखो तो उसे पूरा करने में दिलों जान से जुट जाना चाहिए। पेरिस में मिली सफलता का श्रेय मनु अपने माता-पिता और कोच को देतीं हैं। मनु ने कहा कि मुश्किल समय में उन्होंने श्रीमद्भगवत गीता का सहारा लिया और अब उसी को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करती हैं। **मनु भाकर** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने विशेष बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :-

साक्षात्कार

● आप आज देश की लाखों बेटियों की प्रेरणा हैं। क्या कोई विशेष संदेश आप देना चाहती हैं सभी के लिए जो जीवन में ऐसे ही किसी असफलता के कारण अंधकार में हैं?

-पहले तो सभी माता-पिता को कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को आजादी दो, उनका समर्थन करो। उनका करियर कैसा भी हो, हमेशा ही उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप ही उनकी ताकत हो और आपको ही उन्हें आगे बढ़ाना है। बाकी मैं लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि आपने जो सपने देखे हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। आपको ये देखना होगा कि क्या किया जाए जिससे आपका सपना पूरा हो और दिलों जान से उसमें जुट जाना चाहिए। मन लगाकर मेहनत करो और आगे बढ़ते जाओ। कभी भी हार मत मानो और आपका सपना जरूर पूरा होगा।

● टोक्यो में निराशा और अब पेरिस में दो ओलिंपिक पदक जीतना। इस उपलब्धि को आप कैसे देखती हैं। इन तीन वर्षों के दौरान नीचे से ऊपर उठाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा?

-मेरे लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, लेकिन मैंने हौसला रखा। मैं तो यही कहूंगी जो उस समय मुझे अपने परिवार का साथ मिला, उसकी बहुत अहम भूमिका रही। इस दौरान काफी उतार-चढ़ाव आए, कई प्रतियोगिताएं हारे और कई जीते, लेकिन अंदरूनी खुशी नहीं थी। यह 2023 से बदलना शुरू हुआ। मैंने फिर से जसपाल राणा सर के साथ वापस काम करना शुरू किया। उनसे मुझे काफी मदद मिली और हमारा तालमेल काफी अच्छा हो गया। तब लगा हां मैं काफी अच्छा कर रही हूं। हमेशा ही हर सफर इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको हौसला बनाए रखना चाहिए और बस मेहनत करते जाना चाहिए।

● आपने पहला पदक जीतने के बाद श्रीमद्भगवत गीता का उल्लेख किया था। गाय को चारा खिलाते आपके कई वीडियो हमने देखे। आपकी मां ने कहा कि जब मनु आएंगी तो उसे आलू का पराठा खिलाऊंगी। ये जीवन जीना कितना अच्छा लगता है?

-ये सब तो मुझे बचपन से मेरे माता-पिता ने सिखाया है। बड़ों के पैर छूना, गाय को चारा खिलाना। गांव में हमारे पास गाय और भैंस थीं। जब हम गांव से शिफ्ट हुए, उसके बाद भी मम्मी हमें इन चीजों में सक्रिय रखती थीं। इसमें मेरी मां की काफी अहम भूमिका रही है। जितना आत्मविश्वास मुझे मिला है और मैं यहां तक पहुंची हूं, इसका श्रेय मैं अपनी मां को दूंगी। उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है। श्रीमद्भगवत गीता तो बचपन से जानती थी, लेकिन पिछले दो तीन साल से ज्यादा जुड़ाव रहा। पढ़ना भी अभी शुरू किया। मेरे कोच, मम्मी और मेरे आध्यात्मिक गुरू मुझे रोजाना एक-दो श्लोक सिखाते हैं। मैं कोशिश करती हूं कि इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करूं। जितना हो सके उतना सीखूं। ये चीजें काफी मदद करती हैं साथ ही आपको जमीन से जोड़े रखती हैं। गांव की संस्कृति हमेशा से अच्छी रही है। गांव के बच्चों में काफी प्रतिभा होती है। वे काफी मेहनती होते हैं।

● 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 प्वाइंटर मारना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए ये इतना कठिन क्यों होता है?

-मुझे लगता है कि जिस चीज में आप मेहनत करते हो, उसका अभ्यास करते हो तो वो चीज आपको आसान लगने लगती है। मैं तो काफी लंबे समय से निशानेबाजी कर रही हूं। मेरा तो काम ही यही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करती जाऊं। जितना हो सके अपने आप को स्थिर रख सकूं। निशानेबाजी बेहतर करूं। अब बहुत सारे बच्चे निशानेबाजी को करियर के रूप में अपना रहे हैं। इसमें ध्यान की सबसे बड़ा रोल होता है। थोड़ी चुनौती आती है इसके लिए आप ध्यान लगाने में पारंगत होने चाहिए। फोकस अच्छा होना चाहिए। एक मैच करीब डेढ़ घंटे का होता है और उस पूरे समय आपको बिल्कुल फोकस रहना होता है। मानसिक रूप से मजबूत होने के साथ ही आपको शारीरिक रूप से भी फिट होना होता है। चोटमुक्त रहना होता है।

● इतनी कम उम्र में रोल माडल बनकर कैसा लग रहा है?

-मुझे बहुत खुशी है कि अगर मैं लोगों को थोड़ा बहुत भी प्रेरित कर पाई। अच्छा लगता है जब लोग आपकी सराहना करते हैं। इससे हमें भी आगे अच्छा करने, मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मैं तो यही कहूंगी कि अगर मुझे देखकर कोई एक व्यक्ति भी आने वाले समय में देश के लिए पदक जीतता है तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी।

● देखने में निशानेबाजी अन्य खेलों की तरह बहुत थकाने वाला खेल प्रतीत नहीं होता है। हालांकि, एक पिस्टल को लंबे समय तक एक हाथ में उठाए रखना और जैसा हमने देखा था 25 मीटर रैपिड स्पर्धा में लगातार आपने 40 शाट लगाए। ऐसे में एक निशानेबाज में फिटनेस कितनी महत्वपूर्ण है?

-जो भी लोग कहते हैं कि निशानेबाजी इतनी मुश्किल नहीं है, मैं तो उनको कहती हूं कि आप आइए और शुरू करिए। हर खेल की अपनी-अपनी चुनौतियां होती हैं। जैसे निशानेबाजी में सोल्डर इंजरी होने या पैर के निचले हिस्से में खून रुक जाने जैसी दिक्कतें होती हैं। कोहनी, कमर के निचले हिस्से में काफी समस्या होती है। ऐसे में खुद को फिट रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए हमारे पास पूरी टीम रहती है। हम कोशिश करते हैं कि खुद को चोट मुक्त रखें और फिट रखें।

● कई ऐसी चीजें भी होंगी, जो आपको पसंद होंगी और जिन्हें आपको त्यागना पड़ा होगा?

-अब तो आदत पड़ गई है। शुरुआत में लगता था कि स्कूल और कालेज लाइफ नहीं है। हम बाहर नहीं जा पाते थे। लोग एक दूसरे के घर में टीवी देखने जाते थे, लेकिन हमें उसकी भी इजाजत नहीं थी। मीठा और जंक फूड खाने से परहेज करना पड़ता था। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब तो आदत हो चुकी है। अब जो लाइफस्टाइल बन चुका है, उसे ही जीने में आनंद आता है।

● दूसरे बच्चों की तरह शादी में जाना, खेलना, फिल्में देखना, घूमने जाना, आप ये करती थीं या इसकी बिल्कुल मनाही थी?

-सच कहूं तो शादी ब्याह में जाना तो मुझे कभी भी पसंद नहीं था। हां, भाई के साथ मेले में कभी-कभी चले जाते थे। मेले में जाने में बहुत मजा आता था। कभी दोस्तों के साथ चले जाते थे, लेकिन ज्यादा इन चीजों का शौक नहीं रहा है कभी। एक एथलीट की जिंदगी आम बच्चे की तरह नहीं होती। काफी चीजें त्यागनी पड़ती हैं क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत समय लगता है।

● टोक्यो में खराब प्रदर्शन के बाद कोच जसपाल राणा और आपके संबंध में कुछ खटास आई थी लेकिन इस बार आप दोनों की ट्यूनिंग शानदार थी। मैंने सुना है कि प्रतियोगिता के दौरान जहां से आप शाट लेती थीं वह ऐसी जगह बैठते थे कि हर शाट के बाद आप दोनों आंखों में ही संवाद हो सके?

-टोक्यो के समय कुछ चीजों को लेकर गलतफहमी हो गई थी। उस समय किसी न किसी तरीके से चूक रही थीं, फिर हमने कोशिश की जो तब हुआ वो कभी न हो। दोनों की ओर से ही यह समझ थी कि वापसी से तालमेल बिठाएंगे और देश के लिए अच्छा करेंगे।

● आजकल के बच्चों को इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और आप खुद कैसे करते हो?

-प्रतियोगिता के दौरान मैं इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करती हूं। उस समय तो पूरा ध्यान प्रतियोगिता पर होता है, लेकिन कभी-कभी देख लेते हैं। ज्यादातर समय तो ट्रेनिंग में व्यस्त रहते हैं इसलिए समय ही नहीं मिल पाता है।

पेरिस ओलिंपिक में **अयोग्य** ठहराए जाने को दी थी चुनौती

विनेश फोगाट की अपील खेल पंचाट ने खारिज की

नई दिल्ली, जेएनएन: पेरिस ओलिंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय के विरुद्ध भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील को खेल पंचाट ने बुधवार को खारिज कर दिया। पिछले सप्ताह विनेश को ओलिंपिक में 50 किग्रा फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश ने इसके विरुद्ध अपील दायर कर उन्हें संयुक्त रूप से रजत पदक देने की मांग की थी। इस निर्णय के मायने हैं कि पेरिस ओलिंपिक में भारत के छह ही पदक होंगे जिसमें एक रजत और पांच कांस्य शामिल हैं।

भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा, पहलवान विनेश फोगाट की युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) और अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) के विरुद्ध दायर अपील पर खेल पंचाट के एकमात्र पंच के फैसले से स्तब्ध और निराश हूं। पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में साझा रजत पदक दिए जाने के विनेश के आवेदन को खारिज करने वाले 14 अगस्त के फैसले का प्रभावी हिस्सा विशेष रूप से उनके लिए, और बड़े पैमाने पर खेल समुदाय के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।

आइओए की ओर से कहा गया कि 100 ग्राम की मामूली विसंगति और उसके परिणाम का न केवल विनेश के करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा है, बल्कि ये अस्पष्ट नियमों और उनकी व्याख्या को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। दो दिन में से दूसरे दिन किसी खिलाड़ी को वजन में इतनी मामूली सी विसंगति के लिए पूरी तरह से अयोग्य करार देने के मामले में गहन समीक्षा की आवश्यकता है। विनेश का मामला बताता है कि कड़े और अमानवीय नियम खिलाड़ियों खासकर महिला खिलाड़ियों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनावों को समझने में विफल रहे हैं। यह निर्णय अधिक न्यायसंगत और उचित मानकों की आवश्यकता की सख्त याद दिलाता है, जो एथलीटों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं । आइओए विनेश के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है और आगे के कानूनी विकल्प तलाश रहा है।

वजन कम न होने से निराश विनेश फोगाट ● फाइल फोटो, आइएएनएस

वजन कम नहीं कर पाई थीं: पिछले मंगलवार को विनेश ने लगातार तीन बाउट जीतकर 50 किग्रा वर्ग के फाइनल में जगह बनाई थी। वह ओलिंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान थीं और अगले दिन बुधवार को उनकी फाइनल बाउट होनी थी, जिसमें उन्हें अमेरिका की सारा एन से भिड़ना था। बुधवार सुबह फाइनल बाउट से पहले जब विनेश का वजन किया गया तो उनका वजन 50.1 किग्रा निकला। छह अगस्त को पहली बाउट से पहले विनेश का वजन 49.9 किलोग्राम था। सेमीफाइनल के बाद विनेश ने एनर्जी ड्रिंक ली और भोजन किया तो उनका वजन 52.7 किलोग्राम हो गया। उन्होंने मंगलवार की पूरी रात वजन कम करने की कोशिश की, लेकिन 100 ग्राम वजन कम करने में असफल रहीं और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

17 को भारत लौटेंगी विनेश: विनेश फोगाट 17 अगस्त शनिवार को भारत लौटेंगी। विनेश अपने पैतृक गांव बलाली में आएंगी और मां प्रेमलता सहित अन्य स्वजनों से मुलाकात करेंगी। विनेश सुबह 10 बजे दिल्ली में आइजीआइ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी।

क्या है यूडब्ल्यूडब्ल्यू का नियम

यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियम के अनुसार, ओलिंपिक में दो बार वजन लिया जाता है। एक बार शुरुआती बाउट से पहले और दूसरा पदक की बाउट से पहले। अगर कोई खिलाड़ी पहले और दूसरी बार वजन कराने के समय उपस्थित नहीं होता या उसका वजन ज्यादा है तो उसे अयोग्य बताकर अंतिम स्थान पर रखा जाता है। उसे कोई रैंक नहीं दी जाती। यही वजह है कि विनेश को अब पदक नहीं मिलेगा।

गौतम गंभीर को मिला अपनी पसंद का गेंदबाजी कोच

नई दिल्ली, जेएनएन: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोर्कल को भारतीय क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। बीसीसीआइ सचिव जय शाह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के पसंदीदा सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। मोर्कल को 2027 वनडे विश्व कप के अंत तक नियुक्त किया गया है। 39 वर्षीय मोर्कल पारस म्हांब्रे की जगह लेंगे और सितंबर में बांग्लादेश के विरुद्ध सीरीज से भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। बांग्लादेश के विरुद्ध पहला टेस्ट 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा।

गंभीर के सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्य सहायक कोच अभिषेक नायर और क्षेत्ररक्षण कोच रेयान टेन डोएशे हैं। मोर्कल नए मुख्य कोच गंभीर की पहली पसंद थे। दोनों ने आइपीएल टीम लखनऊ सुपर जाइंट्स में साथ काम किया है। मोर्कल अगले महीने की शुरुआत में बेंगलुरु स्थित एनसीए में रिपोर्ट करेगा और उनके इयान नेपोमनियाच्ची 12 में से आठ अंक लेकर संयुक्त बढ़त बनाए हैं। टूर्नामेंट के नियम के अनुसार रैपिड में एक जीत के लिए दो जबकि ड्रा के लिए एक अंक मिलता है।

मोर्ने मोर्कल ● फाइल फोटो, एक्स

बीसीसीआइ ने मोर्ने मोर्कल को नियुक्त किया, 2027 वनडे विश्व कप तक होगा कार्यकाल

कुछ दलीप ट्राफी मैच देखने की उम्मीद है। मोर्कल को लक्ष्मीपति बालाजी और आर विनय कुमार जैसे विकल्पों पर तरजीह देकर गंभीर की सिफारिश पर सीधे नियुक्त किया गया है।

बीसीसीआइ के सूत्रों ने बताया, क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का काम मुख्य कोच के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना था, लेकिन जब सहायक स्टाफ के चयन की बात आई तो गंभीर की पसंद को प्राथमिकता देना जरूरी था।

विदाई पर श्रीजेश को याद आए सचिन

नई दिल्ली, प्रेट्र : बचपन से हम सचिन तेंदुलकर का नाम ही सुनते आए हैं और मैदान में सचिन-सचिन का शोर सुना है, जब ओलिंपिक में अंतिम चार मैचों में मुझे श्रीजेश-श्रीजेश सुनाई दिया तो मुझे उनकी क्रिकेट से विदाई याद आ गई। यह कहना है भारतीय हाकी के महान गोलकीपर पीआर श्रीजेश का।

श्रीजेश ने पेरिस ओलिंपिक में देश को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद खेल को अलविदा कह दिया। केरल के इस अनुभवी खिलाड़ी के सम्मान में समारोह में उपस्थित खिलाड़ियों ने एक जैसी लाल जर्सी पहनी हुई थी जिसके पीछे श्रीजेश का नाम लिखा हुआ था। श्रीजेश ने बुधवार को सम्मान समारोह के बाद कहा, जैसे सचिन ने कहा था कि मैदान में 'सचिन सचिन' का शोर वह कभी भुला नहीं पाएंगे तो ओलिंपिक में आखिरी चार मैचों से मुझे भी यह सुनाई दे रहा था 'श्रीजेश श्रीजेश'। उस पल मुझे एकबारगी लगा कि मैंने भी देश के लिए कुछ किया है। मैं मैदान में उतरते समय पैड पहनने को बहुत मिस करूंगा।

राष्ट्रपति ने ओलिंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में पेरिस ओलिंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं ● एएनआइ

हाकी इंडिया ने रिटायर की श्रीजेश की 16 नंबर जर्सी

नई दिल्ली : हाकी इंडिया ने बुधवार को दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का निर्णय किया। हाकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, भविष्य में किसी भी सीनियर टीम के खिलाड़ी को 16 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी, हालांकि जूनियर स्तर पर यह जर्सी मिलेगी।

पीआर श्रीजेश ● प्रेट्र

आर प्रगनानंद रैपिड वर्ग में दौड़ से बाहर

सेंट लुइस, प्रेट्र : ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंद सेंट लुइस रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज के रैपिड वर्ग के दूसरे दिन तीन बाजियों में केवल दो ड्रा ही खेल सके। प्रगनानंद के महज तीन अंक हैं जिससे रैपिड में उनका सफर निराशाजनक रहेगा, लेकिन अगर उन्हें फाइनल में स्थिति में सुधार करना है तो उन्हें ब्लिट्ज वर्ग में काफी अच्छा स्कोर बनाना होगा। प्रगनानंद पहले दिन एक ही ड्रा खेल पाए थे और उन्हें दो बाजियों में हार मिली थी।

फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लागरेव और अलीरेजा फिरौजा के साथ रूस के इयान नेपोमनियाच्ची 12 में से आठ अंक लेकर संयुक्त बढ़त बनाए हैं। टूर्नामेंट के नियम के अनुसार रैपिड में एक जीत के लिए दो जबकि ड्रा के लिए एक अंक मिलता है।

इशान, पंत और राहुल खेलेंगे, विराट-रोहित को छूट

दलीप ट्राफी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीनियर खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन को बेंगलुरु में पांच सितंबर से शुरू होने वाली दलीप ट्राफी में खेलने से छूट मिली है जबकि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने इस प्रतियोगिता के लिए चार टीम का चयन करते हुए घरेलू मुकाबलों में प्रदर्शन करने वाले और संभावित प्रतिभाओं के बीच बढ़िया संतुलन बनाया है। इस टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्टार जैसे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, आलराउंडर रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी चुना गया है जिन्होंने 2023 में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक टेस्ट खेला था।

भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य विकेटकीपर रिषभ पंत भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। 2022 में हुई कार दुर्घटना के बाद यह उनका पहला लाल गेंद वाला टूर्नामेंट होगा। इशान किशन भी इसमें खेलेंगे जिन्हें पिछले सत्र में रणजी ट्राफी टूर्नामेंट में नहीं खेलने के लिए केंद्रीय अनुबंधित सूची से हटा दिया गया था। शुमन गिल, रुतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन और श्रेयस अय्यर को चार टीमों का कप्तान बनाया गया है।

भारत ए: शुभमन गिल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तनुष कोटियान, कुलदीप यादव, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, विद्वत कावेरप्पा, कुमार कुशाग्र, शाश्वत रावत।

भारत बी : अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, रिषभ पंत, मुशीर खान, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, मुकेश कुमार, राहुल चाहर, साई किशोर, मोहित अवस्थी, एन जगदीशन।

भारत सी : रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, अभिषेक पोरेल, सूर्यकुमार यादव, बी इंद्रजीत, रितिक शौकीन, मानव सुतार, उमरान मलिक, वैशाख विजयकुमार, अंशुल कंबोज, हिमांशु चौहान, मयंक मार्कंडेय, आर्यन जुयाल, संदीप वारियर।

भारत डी : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अथर्व ताइडे, यश दुबे, देवदत्त पडिक्कल, इशान किशन, रिकी भुई, सारांश जैन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश सेनगुप्ता, केएस भरत, सौरभ कुमार।

राष्ट्रीय फलक

मप्र में हाथी दांत के चार तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मप्र के ग्वालियर जिले में पुलिस ने हाथी दांत के चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें तीन आरोपित उप्र के निवासी हैं।

पुलिस के अनुसार ग्वालियर निवासी दवा कारोबारी हुकुमचंद गुप्ता व उप्र के आगरा निवासी हिमांशु कुकरेजा हाथी दांत की बिक्री में दलाली का काम करते हैं। एक सिपाही को ग्राहक के रूप में उनके पास भेजा गया। दो हाथी दांत का सौदा 25 लाख रुपये में तय हुआ। हाथी दांत लेकर प्रयागराज से कृष्ण कुमार गुप्ता और महेंद्र कुमार सेठ पहुंचे। इसी दौरान पुलिस टीम ने छापा मारकर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद चारों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिए गए। पुलिस का कहना है कि संभवतः जंगली हाथी का शिकार कर दांत प्राप्त किया गया होगा। शिकार कब, कहां और कैसे किया गया, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

गोवा में दिल्ली के पर्यटक की हत्या, तीन गिरफ्तार

- समुद्र तट पर एक सुनसान स्थान पर बैठा था पर्यटक
- लूटपाट का विरोध करने पर पर्यटक को घोंपी चाकू

पणजी, प्रेट्र : गोवा में दिल्ली के पर्यटक की हत्या कर दी गई। यह घटना बागा समुद्र तट पर हुई। कहा गया है कि पर्यटक से तीन लोग लूटपाट का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी। घटना रविवार रात की है। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कलंगुट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान दिल्ली निवासी बीस वर्षीय हरीश तंवर के रूप में हुई है। तंवर उत्तरी गोवा जिले के बागा समुद्र तट पर एक सुनसान स्थान पर बैठे थे, इसी समय तीनों आरोपितों ने उसका बैग लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपितों में से एक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने समुद्र तट से सोमवार सुबह शव बरामद कर लिया।

पुलिस ने साहिल कुमार, नूर खान व सुशील विश्वकर्मा को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। कलंगुट गांव में दर्जी का काम करने वाला नूर मूलरूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, उत्तराखंड निवासी साहिल और नेपाल निवासी सुशील विश्वकर्मा पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। तीनों को मंगलवार शाम मापुसा में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपितों को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

तीन राज्यों में साइबर ठगी के 15 मामलों में झारखंड से साला-बहनोई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धनबाद : महाराष्ट्र, ओडिशा व बंगाल में साइबर अपराध की 15 घटनाओं को अंजाम देने वाले साला-बहनोई को झारखंड के धनबाद की साइबर व बरवाअड्डा थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में बुधवार को गिरफ्तार किया। दोनों को धनबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इन दोनों के पास से छह स्मार्ट फोन व नौ सिम कार्ड भी मिले हैं।

उपाधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस के प्रतिबिंब एप पर पांच मोबाइल नंबर जांच के लिए आए थे। इनकी लोकेशन बरवाअड्डा इलाके में मिली। इसी के आधार पर दोनों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि वे बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर उन्हें केवाइसी अपडेट करने एवं इंटरनेट बैंकिंग चार्ज के नाम पर उनसे ओटीपी प्राप्त कर उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कर लेते थे।

****

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर ईडी से मांगा जवाब

- मऊ से विधायक अब्बास अंसारी अभी कासगंज जेल में बंद हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी से जवाब मांगा है। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गयी थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी किया और अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर उसका जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने नौ मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सुबूत पेश किए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आगाज के साथ

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ दायर किए याचिका

अंसारी द्वारा धन का लेनदेन साबित होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने मनी लांड्रिंग के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया। ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर सुभासपा के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अंसारी पर चार नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मऊ से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में हैं।

वाईएसआर कांग्रेस के सांसद से जुड़े वीडियो हटाने का आदेश

जागरण, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कई समाचार और यूट्यूब चैनलों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य वेणुमबका विजय साई रेड्डी के खिलाफ विवाहेतर संबंधों के आरोप लगाने से जुड़े वीडियो और लेखों को हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने छह समाचार चैनलों और कई इंटरनेट मीडिया हैंडल को भी वीडियो व लेख हटाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोप महज अफवाहों पर आधारित हैं।

अदालत ने कहा कि अगर संबंधित समाचार प्लेटफार्म सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं, तो रेड्डी इसे हटाने के लिए गूगल, एक्स और फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों से संपर्क कर सकते हैं। अदालत ने एबीएन आंध्र ज्योति और वाइल्ड वुल्फ टीवी जैसे चैनलों के खिलाफ आदेश पारित किया।

गुरुवार, 15 अगस्त, 2024

टेक अपडेट

इंस्टाग्राम में आने वाला है नया फीचर

इसके जरिये यूजर रियल टाइम लोकेशन के साथ टेक्स्ट, फोटो व वीडियो को साझा कर पाएंगे। बता दें कि इंस्टाग्राम का यह नया फीचर स्नैपचैट के स्नैप मैप की तरह ही है। हालांकि यह फीचर प्राइवेसी सेटिंग के साथ आएगा। यूजर के पास यह विकल्प होगा कि वे जिन्हें चाहेंगे, वही उनकी लोकेशन को देख सकेंगे। इसमें यूजर अपनी लोकेशन के लिए क्लोज फ्रेंड्स या ओनली फालोअर्स के विकल्प को चुन सकेंगे। इंस्टाग्राम का यह फीचर फिलहाल टेस्टिंग चरण में है। आम लोगों के लिए इसे कब तक लांच किया जाएगा, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

यूट्यूब में आएगा स्लीप टाइमर फीचर

स्लीप टाइमर फीचर की टेस्टिंग चल रही है। यह वीडियो देखते-देखते सो जाने की स्थिति में प्लेबैक को स्वयं ही रोक देगा। यूट्यूब ने एक पोस्ट में इस फीचर के बारे में कहा है कि स्लीप टाइमर एक निश्चित समय के बाद प्लेबैक को स्वचालित रूप से रोकने के लिए टाइमर सेट करने की सुविधा देगा। यूजर्स वीडियो चलाते समय वीडियो इंटरफेस के ऊपर दाएं कोने में गियर आइकन पर क्लिक करके सेटिंग मेन्यू तक पहुंच सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यूजर्स को अपने अकाउंट में लागइन करना होगा। सेटिंग मेन्यू के भीतर स्लीप टाइमर 10, 15, 20, 30, 45 या 60 मिनट के बाद प्लेबैक को रोकने का विकल्प देगा। वीडियो खत्म हो जाने पर आटो प्लेबैक बंद करने का विकल्प भी है। यूट्यूब का यह फीचर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, जो रात को सोने से पहले यूट्यूब पर वीडियो देखना पसंद करते हैं।

टेक सिक्योरिटी

डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने में नई तकनीक की बड़ी भूमिका होती है। आरबीआइ का डेलिगेटेड पेमेंट सिस्टम भी कुछ ऐसे ही फीचर्स के साथ यूपीआइ सिस्टम में जुड़ने जा रहा है। इसके बारे में बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र

फोटो : फ्रीपिक

सुरक्षित होगा यूपीआइ पेमेंट!

यूपीआइ की लोकप्रियता हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। शहरों से लेकर गांवों तक यह आनलाइन त्वरित भुगतान का सबसे आसान साधन बन गया है। केंद्र सरकार की पहल इसे लगातार आसान बना रही है, ताकि हर वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें। हालांकि जिस तरह से इस तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, साइबर अपराधियों द्वारा इसका दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ा है। सरकार और वित्तीय संस्थान इससे बचने के लिए लगातार लोगों को सतर्क और जागरूक करते रहते हैं। हाल में आरबीआइ ने यूपीआइ के तहत 'डेलिगेटेड पेमेंट' सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है, ताकि देश के अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का उपयोग कर सकें।

क्या है डेलिगेटेड पेमेंट सिस्टम: इसके तहत आप किसी अन्य व्यक्ति को यूपीआइ ट्रांजैक्शन के लिए अनुमति प्रदान कर सकेंगे, साथ ही ट्रांजैक्शन यानी भुगतान की सीमा भी स्वतः तय कर सकेंगे। वह व्यक्ति आपके स्वजन, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी आदि हो सकते हैं। देशभर में डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ने के साथ-साथ ऐसे लोगों को भी सुविधा हो जाएगी जो फिलहाल आनलाइन भुगतान करने में स्वयं को सहज नहीं पाते या तकनीकी जानकारी के अभाव में ऐसा करने से डरते हैं कि कहीं उनका पैसा गलत हाथों में न चला जाए। इस पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआइ जल्द ही व्यापक दिशा-निर्देश जारी करेगा। डेलिगेटेड पेमेंट सिस्टम से वर्तमान यूपीआइ यूजर बेस (42.2 करोड़) में निःसंदेह और अधिक वृद्धि होगी। आथराइजेशन फीचर के जुड़ जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग यूपीआइ पेमेंट को लेकर सहज होंगे, जहां अपेक्षाकृत वित्तीय साक्षरता अभी कम है। खास बात यह है कि इसमें दूसरे यूजर के लिए यूपीआइ लिंक बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी यानी आप जिसे भी भुगतान के लिए अधिकृत करेंगे, उसका बैंक एकाउंट होना आवश्यक नहीं होगा।

डेलिगेटेड पेमेंट के लाभ

भुगतान में सहजता: डेलिगेटेड पेमेंट की सुविधा आरंभ हो जाने से परिवार के अन्य सदस्य या आश्रित को खर्च का प्रबंधन करने की सुविधा मिलेगी। खास बात है कि यह सुविधा प्राथमिक यूजर के पूरे बैंक अकाउंट पर पूर्ण नियंत्रण के बगैर मिल जाएगी।

सुरक्षित लेनदेन: भुगतान की सुविधा प्रदान करने के बावजूद प्राथमिक यूजर ट्रांजैक्शन को नियंत्रित कर सकता है। वह दी गई अनुमति को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है।

भुगतान सीमा: प्रत्येक यूपीआइ भुगतान की कितना सीमा हो, यह प्राथमिक यूजर अपना अकाउंट एक्सेस देने के बावजूद तय कर सकता है यानी वह हर गतिविधि की निगरानी कर सकता है। इससे अकाउंट के दुरुपयोग की आशंका नहीं होगी।

अधिक तकनीकी बाध्यता नहीं : असिस्टेड पेमेंट माडल उन लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा जो तकनीक और डिवाइसेज के प्रयोग में सहज नहीं होते। आरबीआइ की मंशा भी यही है कि लोग यूपीआइ का बेझिझक उपयोग करें। उन्हें आनलाइन भुगतान करने में किसी तरह का भय न हो।

हालांकि यह सुविधा आरंभ हो जाने के बाद ही वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा कि इसमें कोई व्यावहारिक परेशानी तो नहीं आ रही है। ऐसा होने पर उसे दूर करने का प्रयास भी होगा।

ध्यान रखें इन बातों का

- आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर बैंक रिकार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- यूपीआइ पिन हमेशा भुगतान करने के लिए दर्ज करना होता है न कि भुगतान प्राप्त करने के लिए।
- यूपीआइ एप से ट्रांजैक्शन करते समय हमेशा एप के नोटिफिकेशन को जांचना चाहिए।
- बैंक से संपर्क व विवरण हेतु बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ही देखें।
- अगर कोई शिकायत दर्ज करानी है तो ऐसा केवल बैंक या पुलिस से ही करें।

...ताकि न हो किसी तरह की ठगी

- बैंक या सरकारी अधिकारी होने का दावा करने वाले अनजान व्यक्ति के मैसेज को फारवर्ड न करें।
- थर्ड पार्टी के साथ कभी डेबिट कार्ड क्रिडेंशियल और यूपीआइ पिन को साझा न करें।
- साइबर रिमोट एक्सेस/स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए ठग ट्रांजैक्शन में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे एप्स से बचें।
- अपनी शिकायत से संबंधित ट्रांजैक्शन डिटेल्स को इंटरनेट मीडिया पर साझा करने से बचें।
- थर्ड पार्टी काल के दौरान किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन न करें।

वर्ग पहेली - 2722

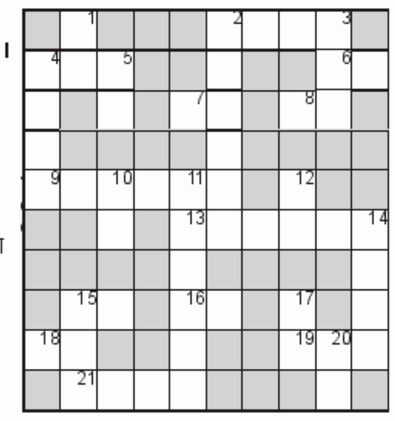

बाएं से दाएं
2. बिना प्रयत्न के, सरलता से (4)। 4. व्यवहार, कर्म, आचरण (3)। 6. भीगा (2)। 7. बद्दुआ, श्राप (2)। 8. खाता, नशा, गर्व (2)। 9. ऋणी होना, बहुत उधार ले लेना (2,1,3)। 13. लपलपाने का भाव (6)। 15. तला, पेंदा (2)। 16. पेड़ का जमीन के ऊपर का भाग (2)। 18. माला, पराजय (2)। 19. गबन, पाचन क्रिया (3)। 21. इधर-उधर हिलाना (4)।

ऊपर से नीचे
1. शोक, दुख (2)। 2. आलतू-फालतू (3,3)। 3. प्रमाण पत्र (3)। 4. शासन को नहीं मानने वाला (4)। 5. जटा (2)। 10. खेत की हदबंदी (2)। 11. शिकन दूर होना (2,4)। 12. होश, बड़ी बहन (2)। 14. तांगा को यह भी कहते हैं (4)। 15. ओर, पार्श्व (3)। 17. राजा, शतरंज का एक मोहरा (2)। 20. दुनिया, संसार (2)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

स[1]	मा	हा	र[2]		क[3]	ढ़ा		सा[4]	स[5]
ब			च		हा				म
		आ[6]	ना	का	नी		ओ[7]		र्थ
श[8]			का		ब[9]	ल	व	र्ध	क
कु[10]	च	क्र[11]	र	चे[12]	ना		स		
		म		म[13]	ना	क[14]	र	दे	ना[15]
क[16]	था	वा	च	क		स			क
ला		र		द[17]	म	क	ल		
त्म				म		हो			था[18]
क[19]	म		ना[20]	क		ना[21]	ला	य	क

जागरण सुडोकू-2722

9		7		1		3		2
				2			7	
1		3	6			9		5
	3		5					
7						5		4
			7	9				
3					2		8	6
	4		3		6	1		
2		1		4			5	

कल का हल

1	2	3	4	7	9	5	8	6
8	9	4	1	6	5	2	3	7
7	6	5	8	2	3	1	4	9
4	5	2	9	8	7	6	1	3
3	1	8	6	5	2	9	7	4
9	7	6	3	1	4	8	5	2
5	3	1	7	9	6	4	2	8
2	4	9	5	3	8	7	6	1
6	8	7	2	4	1	3	9	5

आज का भविष्यफल- 15 अगस्त, 2024 गुरुवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशमी। आज का राहुकाल : दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक। आज का दिशाशूल : दक्षिण। आज की भद्रा : रात्रि 10:04 बजे से प्रारंभ 16 अगस्त को प्रातः 09:40 पर समाप्त।

कल 16 अगस्त, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : पुत्रदा एकादशी
विशेष : सूर्य सिंह राशि, मघा नक्षत्र में।
भद्रा : प्रातः 09:40 पर समाप्त।
विक्रम संवत 2081 शके 1946 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तत्पश्चात द्वादशी मूल नक्षत्र तत्पश्चात पूर्वाआषाढ़ा नक्षत्र धनु में चंद्रमा।

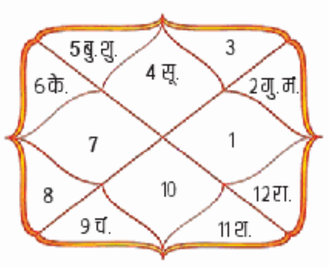

- **मेष :** सूर्य का परिवर्तन रोग और विरोधी को प्रभावित करेगा।
- **वृष :** किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- **मिथुन :** जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
- **कर्क :** स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
- **सिंह :** रिश्तों में निकटता आएगी। सूर्य का परिवर्तन आत्मविश्वास देगा।
- **कन्या :** सूर्य उदर विकार दे सकता है, लेकिन विरोधी परास्त होंगे।
- **तुला :** संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
- **वृश्चिक :** रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
- **धनु :** सूर्य का परिवर्तन पिता या धर्म गुरु से सहयोग दिलाएगा।
- **मकर :** सूर्य का परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा।
- **कुंभ :** चली आ रही परेशानी में सुधार होगा। विरोधी परास्त होगा।
- **मीन :** संतान के कारण कष्ट मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

हेल्थ गैजेट्स

सेहत पर नजर बनाए रखेंगे ये डिवाइस

स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए आजके दौर में यह बहुत जरूरी नहीं है कि आप हर सप्ताह हेल्थ चेकअप करवाएं। आजकल बाजार में बहुत सारे ऐसे हेल्थ और फिटनेस गैजेट्स उपलब्ध हैं जो न सिर्फ आपकी सेहत पर नजर रखते हैं, बल्कि हार्ट रेट, ब्लड शुगर, ब्लड आक्सीजन लेवल, नींद लेने के पैटर्न आदि को भी काउंट करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हेल्थ-फिटनेस डिवाइस के बारे में, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं...

स्मार्टवाच

स्मार्टवाच डेली वर्कआउट और स्टेप को काउंट करती है और एनालाइज कर डाटा तैयार करती है। यह डाटा ब्लूटूथ की मदद से फोन पर भी देख सकते हैं। यह एक्सरसाइज के गोल्स के साथ हार्टबीट, हार्ट रेट, आक्सीजन लेवल आदि को भी ट्रैक करती है। यह पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर कार्य करती है जो आपको व्यापक हेल्थ मैनेजमेंट भी प्रदान करती है। स्मार्टवाच में आपको कई तरह के हेल्थ फीचर मिलते हैं।

एक्टिविटी ट्रैकिंग: इसकी मदद से स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी बर्न को ट्रैक करना आसान हो जाता है।
हेल्थ मानिटरिंग: एपल वाच ईसीजी जैसे हेल्थ फीचर से लैस होती है, जो इमरजेंसी की स्थिति में बेहद उपयोगी साबित होते हैं।
इसके अलावा स्मार्टवाच में हार्ट रेट मानिटरिंग, ब्लड आक्सीजन लेवल, स्लीप पैटर्न ट्रैकिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सैमसंग स्मार्टवाच में ब्लड शुगर मानिटरिंग जैसे फीचर्स भी आ रहे हैं। स्मार्टवाच की कीमत 2000 रुपये से शुरू हो जाती है।

वियरेबल फिटनेस ट्रैकर

जो लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं, उनके लिए वियरेबल फिटनेस ट्रैकर एक बेहतरीन डिवाइस है। इसकी मदद से डेली एक्टिविटीज, नींद के पैटर्न, हार्ट रेट आदि की निगरानी आसान हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप लगातार इस डिवाइस का उपयोग करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी चीजों को ट्रैक करने में मदद मिलती है। हेल्थ ट्रेकर डिवाइस में आपको ये फीचर मिलते हैं :
एक्टिविटीज मानिटरिंग : स्टेप्स, दूरी और बर्न की गई कैलोरी पर नजर रख सकते हैं।
हार्ट रेट मानिटरिंग: यह रियल टाइम में हार्ट रेट मानिटर करता है।
स्लीप ट्रैकिंग: अच्छी नींद ले रहे हैं या नहीं, इसकी मदद से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही नींद की गुणवत्ता की जांच भी कर सकते हैं।
स्मार्ट नोटिफिकेशन : हेल्थ फीचर के अलावा काल, टेक्स्ट और एप नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसकी कीमत 1500 रुपये से शुरू हो जाती है, पर ब्रांडेड गुणवत्तायुक्त होते हैं।

स्मार्ट रिंग्स

अगर आप हेल्थ मानिटरिंग के लिए फिटनेस बैंड या फिर स्मार्टवाच से अलग विकल्प की तलाश में हैं तो स्मार्ट रिंग्स भी बाजार में मौजूद हैं। इसे भी विभिन्न हेल्थ ट्रैकिंग सुविधाओं के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इस हेल्थ गैजेट की मदद से स्लीप पैटर्न, हार्ट रेट और एक्टिविटीज के लेवल को ट्रैक किया जा सकता है।
स्लीप पैटर्न : स्मार्टवाच की तरह स्मार्ट रिंग्स भी स्लीप साइकिल पर नजर रखती है और विस्तृत डाटा प्रदान करती है।
हार्ट मानिटरिंग : हार्ट रेट पर नजर रखने के साथ स्ट्रेस लेवल को भी मानिटर करती है।
एक्टिविटीज ट्रैकिंग: स्टेप्स, बर्न की गई कैलोरी के साथ एक्टिविटीज को भी रिकार्ड करती है।
स्मार्ट रिंग भी एप के जरिए मोबाइल के साथ पेयर होती है। एक बार डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद हेल्थ से संबंधित विस्तृत डाटा देख सकते हैं। स्मार्ट रिंग की कीमत लगभग 3000 रुपये से शुरू होती है।

स्मार्ट वाटर बाटल

अगर आप अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं तो चिंता की बात नहीं। बाजार में स्मार्ट बोतल मौजूद है। यदि निश्चित समय में आपने इससे पानी नहीं पिया है तो यह पानी पीने के लिए सूचित करेगी। बोतल का ढक्कन या बाडी पानी पीने की याद दिलाने के लिए रोशनी कर सकती है। यह स्मार्टफोन से पेयर हो जाती है। इसमें एलईडी इंडिकेटर होता है जो तय समय तक पानी नहीं पीने पर विजुअल रिमाइंड की तरह काम करता है। इसकी कीमत 1500 रुपये से शुरू होती है। इन स्मार्ट डिवाइसेज के बारे में गार्मिन इंडिया के बी2बी प्रमुख जुहा विलान्नेन का कहना है कि ये हमारे जीवन में उल्लेखनीय रूप से बदलाव ला रही हैं साथ ही ये स्वस्थ जीवनशैली के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं।

संतोष आनंद

राष्ट्रीय फलक

मथुरा के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ से बिगड़े हालात

वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव से बिगड़ते हालात। जागरण

जागरण संवाददाता, मथुरा

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में बुधवार को भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी तो परिसर के अंदर ही नहीं बाहर भी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आईं। भीड़ नियंत्रण के प्रशासन के हर प्रयास विफल नजर आए।

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली-एनसीआर के हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए चुनौती भरा होगा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचने लगे। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने बैरियर पर श्रद्धालुओं को रोक-रोककर आगे बढ़ाया। गर्मी और भीड़ के दबाव में व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थीं। श्रद्धालु एक-दूसरे को धकियाते हुए मंदिर के अंदर पहुंचने की कोशिश करते रहे। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

एनएसजी के डीजी नलिन प्रभात एजीएमयूटी कैडर में लाए गए

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक नलिन प्रभात के कार्यकाल में कटौती कर उन्हें एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश) कैडर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। इसके साथ ही उन्हें जम्मू कश्मीर का अगला पुलिस महानिदेशक बनाए जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मौजूदा महानिदेशक आरआर स्वैन इसी वर्ष 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। वर्ष 1992 बैच के आइपीएस नलिन प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और वह सीआरपीएफ में रहते हुए लगभग छह वर्ष तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।

यहां बता दें कि तीन वर्ष में जम्मू क्षेत्र में जिसक तरह आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे में केंद्र नलिन प्रभात को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के मूड में है। इसके अलावा केंद्र अब जम्मू कश्मीर के भीतरी भागों में सेना की भूमिका को सीमित करते हुए सीआरपीएफ व पुलिस की भूमिका को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

अमरनाथ धाम में दर्शन के लिए दशनामी अखाड़े से छड़ी मुबारक रवाना

पवित्र गुफा में दर्शन के लिए प्रस्थान होने से पहले श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में छड़ी मुबारक का पूजन करते अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरि (सबसे आगे) समेत संत-साधु। जागरण

- 52 दिन से चल रही बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से छड़ी मुबारक पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गई। यह श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन वाले दिन पवित्र गुफा के दर्शन करेगी। इसके साथ ही 52 दिन से चली आ रही बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा संपन्न हो जाएगी।

दशनामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरि जी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पारंपरिक रूट पहलगाम से अमरनाथ धाम के लिए जाएगी। गत 29 जून से शुरू अमरनाथ यात्रा में अब तक 5.10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। फिलहाल यात्रा को पहलगाम मार्ग से छह अगस्त और बालटाल मार्ग से 12 अगस्त से स्थगित रखा गया है।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने पहलगाम मार्ग पर यात्रा बंद करने का कारण मार्ग पर आवश्यक मरम्मत कार्य बताया है। वहीं, बालटाल मार्ग पर बारिश को कारण बताया है।

श्रद्धा का महासावन

सावन में शिव स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाती हैं सिद्धियां

सावन सभी महीनों में श्रेष्ठ और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि मेरी प्रिया सती ने प्रजापति के दक्ष यज्ञ में अपनी देह का त्याग कर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में श्रावण मास में ही मुझे प्राप्त किया था। अतः सावन प्रिय होने के साथ इस मास में की गई पूजा भगवान शिव को साक्षात प्राप्त होती है। सावन में पृथ्वी जल, धान्य, हरियाली से संतृप्त हो जाती है। भगवान शिव सनत कुमारों से कहते हैं कि सावन मास में जो भी मानव नियम-संयम से रहते हुए मेरी पूजा-अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन, शिवलिंग पूजन आदि करता है, शिव महिमा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, अमोघ शिव कवच व पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का श्रद्धानुसार पाठ व जप करता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होते है। साथ ही शक्ति-भक्ति व पुण्य में वृद्धि होती है। समस्त पापों का क्षय हो जाता है। शिवजी के शीर्ष में गंगा विराजमान होने से गंगा जल से अभिषेक सर्वोत्तम है। इस पूरे माह शिव स्मरण मात्र से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्रावण पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र होने से व इस मास का महात्म्य श्रवण करने से भी श्रावण मास कहा जाता है। इस मास में शिवजी को गंगा जल, बिल्व पत्र, धतूर पुष्प, धूप-दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि अर्पण कर पूरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए।

डा. हरिहर कृपालु त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद, वाराणसी

सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र को चेतावनी, मुआवजा नहीं दिया तो रोक देंगे मुफ्त की योजनाएं

- छह दशक पहले गैरकानूनी रूप से अधिग्रहीत की गई थी जमीन
- कोर्ट ने कहा, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसा है, मुआवजा देने को नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि छह दशक से अधिक पहले गैरकानूनी रूप से अधिग्रहीत की गई जमीन के निजी पक्षकार को अगर उसने मुआवजे का भुगतान नहीं किया तो वह उसकी मुफ्त रेवड़ियां बांटने की योजनाएं स्थगित कर देगा। महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन जमीन गंवाने वाले निजी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र का आचरण आदर्श राज्य की तरह नहीं है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि राज्य ने मुआवजे के तौर पर 37.42 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है, जबकि आवेदक के वकील ने दलील दी है कि यह करीब 317 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र के वकील निशांत आर. कटनेश्वरकर ने पीठ से तीन हफ्ते का समय मांगते हुए कहा कि मामले पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है और मुआवजे की गणना के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। इस पीठ ने कहा, 'हम आपको तीन सप्ताह का समय देंगे और अंतरिम आदेश पारित करेंगे कि जब तक हम अनुमति नहीं देते महाराष्ट्र में कोई भी मुफ्त की योजना लागू नहीं होनी चाहिए। हम लाडली बहन और लड़का भाऊ को रोक देंगे।' सुनवाई के दौरान कटनेश्वरकर ने कहा कि वह अदालत के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से सुर्खियां बन जाती हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, 'शायद, हमें इसकी परवाह नहीं। हम अखबार नहीं पढ़ते। हम नागरिकों के अधिकारों के प्रति चिंतित हैं।' पीठ ने कहा कि वह ऐसी टिप्पणियां करने को मजबूर है। शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेशों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि उसने इस मामले में स्पष्ट तथ्य रिकार्ड किए हैं। चूंकि अदालत नौ अगस्त को राज्य की ओर से दाखिल हलफनामे से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने राज्य के वकील से मुख्य सचिव से चर्चा करने और तार्किक प्रस्ताव पेश करने को कहा था। पीठ ने कहा कि आवेदक की जमीन को गैरकानूनी रूप से राज्य ने अधिग्रहीत किया था और बाद में आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट को आवंटित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट तक से मुकदमा जीतने के बावजूद आवेदक को अपना वैध हक पाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। पीठ ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त निर्धारित की, ताकि राज्य सरकार उचित मुआवजा प्रस्ताव ला सके।

ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा आरामदायक बेड रोल

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: ट्रेन में यात्रियों को आरामदायक कंबल, तकिया व चादर मिलेगी। रेलवे ने परीक्षण के तौर पर नए प्रकार के लिनन की शुरुआत रांची राजधानी एक्सप्रेस में की है। बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को भी जल्द यह उपलब्ध होगा।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पहली बार प्रीमियम अल्ट्रा साफ्ट बेड रोल तैयार कराया है। भारतीय मानक ब्यूरो और अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श के बाद इसे यात्रियों यात्रियों को देने का निर्णय लिया गया है। कंबल, चादर, तकिया की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ ही इसे साफ करने में पानी भी कम लगेगा। तकिया आरामदायक होने से यात्रियों को बेहतर अनुभव होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रांची राजधानी के यात्रियों को यह दिया गया है। 17 अगस्त से बिलासपुर राजधानी में भी इसकी सुविधा शुरू होगी। बेड रोल को लेकर यात्री अक्सर शिकायत करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए बेड रोल से शिकायत में कमी आएगी।

स्वतंत्रता दिवस पर ओलंपिक दल, बीआरओ कर्मी, लखपति दीदी होंगी विशेष मेहमान

- इस साल के स्वतंत्रता दिवस की थीम '2047 में विकसित भारत' है
- लालकिले में आयोजित समारोह में छह हजार विशेष मेहमान शामिल होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को लाल किले पर आयोजित समारोह में छह हजार विशेष मेहमान आमंत्रित किए गए है। इसमें पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाला भारतीय दल, अटल नवाचार मिशन से लाभ उठाने वाले विद्यार्थी, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के कर्मी और ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस साल के स्वतंत्रता दिवस की थीम '2047 में विकसित भारत' है। यह समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

उसने कहा कि राष्ट्रीय उत्साह के इस पर्व में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष लाल किले पर होने वाले समारोह का अवलोकन करने के लिए देश भर से लगभग 6,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जिनमें युवा, जनजातीय समुदाय, किसान, महिलाएं और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं, पहलों की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

मंत्रालय के अनुसार, 'अटल नवाचार मिशन और पीएम श्री योजना से लाभान्वित होने वाले छात्र और 'मेरी माटी मेरा देश' के तहत मेरा युवा भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।'

रक्षा मंत्री करेंगे पीएम मोदी का स्वागत

लाल किले पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने करेंगे। रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल आफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का प्रधानमंत्री से परिचय कराएंगे। इसके बाद दिल्ली क्षेत्र के जीओसी प्रधानमंत्री मोदी को सलामी मंच पर ले जाएंगे, जहां संयुक्त अंतर-सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड प्रधानमंत्री को सामान्य सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान मेजर अर्जुन सिंह संभालेंगे, नौसेना की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर गुलिया भावेश एनके संभालेंगे और वायु सेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर अक्षरा उनियाल संभालेंगी। लेफ्टिनेंट संजीत सैनी झंडा फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता करेंगे।

****

थामस एडीसन ने गढ़ा टेलीफोन अभिवादन के लिए 'हैलो' शब्द

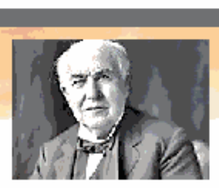

1877 में आज ही के दिन थामस एडीसन ने टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष को फोन का जवाब देने के लिए पहली बार हैलो शब्द बोला था। इसी के बाद यह शब्द पूरी दुनिया में प्रचलन में आ गया। अभी तक हो रहा है। इससे पहले अलेक्जेंडर बेल द्वारा सुझाए गए 'अहोय, अहोय' शब्द का इस्तेमाल होता था।

पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाली मानव निर्मित वस्तु बनी वायजर-1

2006 में आज ही नासा का अंतरिक्ष यान वायजर 1 पृथ्वी से 15 अरब किमी दूर सौर मंडल के बाहरी किनारे हेलियोशीथ तक पहुंच गया था। 1977 में अध्ययन के उद्देश्य से लांच वायजर-1 प्रतिदिन दस लाख मील की गति से यात्रा करता रहता है और फिलहाल पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है।

आजादी के दिन जन्मे स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना

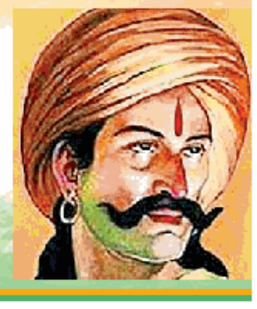

स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना का जन्म 1798 में आज ही कर्नाटक में हुआ था। रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख रहे संगोली शुरू से ही ब्रिटिश विस्तार की नीति व भारतीयों से सत्ता हथियाने के विरुद्ध थे। कित्तूर सेना की हार के बाद स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। इसके बाद जगह-जगह ब्रिटिश कार्यालयों को लूटकर उसमें आग लगा दी। साथी के विश्वासघात की वजह से पकड़े गए एवं 26 जनवरी, 1831 को उन्हें फांसी दे दी गई।

शरीर में 40 व 60 साल में होता है नाटकीय परिवर्तन

अध्ययन ▶ 40 वर्ष के बाद अणु और सूक्ष्मजीवों में होता है तेजी से बदलाव, जो पूरे मेटाबोलिज्म को करता है प्रभावित

नई दिल्ली, प्रेट्र : शरीर में 40 और 60 साल में नाटकीय परिवर्तन होता है। इस कारण इस समय स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। एक नए अध्ययन में पाया गया कि 40 साल के बाद मध्य में और 60 साल की शुरुआत में व्यक्ति को अणुओं और सूक्ष्मजीवों में नाटकीय वृद्धि या गिरावट का अनुभव होता है, जो हृदय और इम्यून कार्य, मांसपेशियों को प्रभावित करता है।

शोधकर्ताओं ने 25 से 75 वर्ष की आयु के लोगों में 1,35,000 से अधिक विभिन्न अणुओं और सूक्ष्मजीवों में उम्र बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक किया गया। इसके दौरान पाया गया कि अणुओं और सूक्ष्मजीवों की संख्या में वर्षों से धीरे-धीरे बदलाव नहीं हुआ। अल्जाइमर रोग और हृदय संबंधी स्थितियों जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों का जोखिम 60 वर्ष से कम आयु के लोगों में धीरे-धीरे बढ़ने की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है।

अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि इसके बजाय हम अपने जीवनकाल के दौरान तेजी से बदलाव के दो दौर से गुजरते हैं, औसतन 44 वर्ष की आयु और 60 वर्ष की आयु के आसपास। यह निष्कर्ष नेचर एजिंग पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स के अध्यक्ष और वरिष्ठ लेखक माइकल स्नाइडर ने कहा कि हम समय के साथ धीरे-धीरे नहीं बदल रहे हैं। इसमें कुछ वास्तव में नाटकीय परिवर्तन हैं। यह पता चला है कि 40 के मध्य में नाटकीय परिवर्तन का समय होता है, जैसा कि 60 साल की शुरुआत में होता है। यह सच है चाहे आप अणुओं के किसी भी वर्ग को देखें। शोधकर्ताओं ने 40 साल के लोगों में अल्कोहल, कैफीन और लिपिड (वसा) के मेटाबोलिज्म में शामिल अणुओं की संख्या में बदलाव देखा। साथ ही हृदय रोग, त्वचा और मांसपेशियों से संबंधित बदलाव भी देखा गया। 60 साल के लोगों में कार्बोहाइड्रेट और कैफीन मेटाबोलिज्म, इम्यून और किडनी के कार्य से संबंधित बदलाव देखा गया। साथ ही हृदय रोग, त्वचा और मांसपेशियों से जुड़े अणुओं की संख्या में भी बदलाव देखा गया।

25 **से 75 वर्ष के लोगों में 1,35,000 से अधिक विभिन्न अणुओं व सूक्ष्मजीवों में उम्र बढ़ने से होने वाले बदलावों को ट्रैक किया गया**

40 के दशक में शरीर में होता है नाटकीय परिवर्तन। फाइल

कई वर्षों तक हर कुछ महीनों में 108 प्रतिभागियों से लिए गए रक्त और अन्य जैविक नमूनों से लेखकों ने विभिन्न अणुओं जैसे आरएनए और प्रोटीन के साथ ही उनके माइक्रोबायोम में बदलावों को देखा। इसमें शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस और फंगस शामिल हैं। कुल लगभग 250 अरब अलग-अलग डाटा के बिंदुओं का विश्लेषण किया गया। लेखकों ने लिखा कि इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए 81.03 प्रतिशत अणुओं ने आधार रेखा की तुलना में कम से कम एक आयु चरण में बदलाव को प्रदर्शित किया। अध्ययनों में देखा गया कि उम्र बढ़ने के साथ विभिन्न अणु कैसे बढ़ते या घटते हैं और जैविक आयु कालानुक्रमिक आयु से कैसे भिन्न होती है। बहुत कम अध्ययनों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हम किस दर से जैविक रूप से बूढ़े होते हैं। स्नाइडर ने कहा कि 60 साल की शुरुआत में इतने सारे नाटकीय परिवर्तन होना शायद आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जीवन के उस बिंदु पर कई आयु संबंधी रोग का खतरा और अन्य आयु संबंधी घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, प्रतिभागियों में उनके 40 के मध्य में देखे गए बदलावों का समूह टीम के लिए आश्चर्यजनक था। शोधकर्ताओं ने शुरू में माना था कि ये परिवर्तन रजोनिवृत्त या रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में होते हैं। लिंग के आधार पर अध्ययन समूह को तोड़ने पर ये परिवर्तन 40 के मध्य के पुरुषों में भी होते देखे गए। शोधकर्ताओं ने कहा कि उम्र से संबंधित बदलावों का समूह लोगों को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है, खासकर 40 और 60 साल के बाद।

फिल्म रिव्यू

वेदा

प्रमुख कलाकार : जान अब्राहम, शरवरी, अभिषेक बनर्जी, तमन्ना भाटिया
निर्देशक : निखिल आडवाणी
अवधि : दो घंटा 31 मिनट

एक्शन में आगे, संवेदनाओं में पीछे

ऊंचनीच, जातपात, आनर किलिंग और स्त्री उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों को हिंदी सिनेमा हमेशा से ही कहानी में पिरोता आया है। कई सत्य घटनाओं पर फिल्म निर्देशित कर चुके निखिल आडवाणी की फिल्म वेदा भी सच्ची घटना से प्रेरित है। हालांकि असीम अरोड़ा लिखित इस कहानी में रिसर्च का अभाव स्पष्ट नजर आता है। फिल्म न तो आनर किलिंग को समुचित तरीके से दिखा पाती है ना ही असमानता का सामना करने वालों की पीड़ा।

कहानी यूं है कि पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारी अभिमन्यु कंवर (जान अब्राहम) खास मिशन के तहत पाक अधिकृत कश्मीर जाता है। वह अपने मिशन में कामयाब रहता है पर वरिष्ठजनों का निर्देश न मानने को लेकर सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है। वह बाड़मेर (राजस्थान) आता है, जहां ससुर की मदद से कालेज में बाक्सिंग का सहायक कोच बन जाता है। उसकी पत्नी (तमन्ना भाटिया) की आतंकियों ने हत्या कर दी होती है। इसी कालेज में पढ़ने वाली वेदा वंचित वर्ग से है। गांव के प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह (अभिषेक बनर्जी) का छोटा भाई सुयोग प्रताप सिंह (क्षितिज चौहान) दोस्तों के साथ उसे अक्सर परेशान करता है। प्रधान गांव के मामलों को लेकर फैसला व कार्रवाई खुद ही करते हैं। वेदा का भाई ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता है। उसकी कीमत उसे जानकर देकर चुकानी पड़ती है। उसके बाद प्रधान का कहर टूटता है वेदा और उसकी बहन पर। अभिमन्यु से बाक्सिंग की ट्रेनिंग लेने वाली वेदा उससे मदद मांगती है। वह अधिकारों के लिए अदालत पहुंच पाती है या नहीं, कहानी इस संबंध में है।

फिल्म का असल दारोमदार जान अब्राहम के कंधों पर है। चित्र सौ. : फिल्म टीम

फिल्म का असल दारोमदार जान अब्राहम के कंधों पर है। उनके हिस्से में संवाद कम, एक्शन भरपूर हैं। फिल्म देखते हुए लगता है कि कालेज में वेदा अकेली है, जिसे इस प्रकार छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह कालेज में होली के गाने होलिया में उड़े रे गुलाल... देखकर लगता ही नहीं वहां पर असमानता है। दरअसल, लेखक और निर्देशक उस परिवेश, सामाजिक विषमता को विश्वसनीय बना पाने में नाकाम रहे हैं। यदि थोड़ा रिसर्च किया जाता, तो क्लाइमेक्स को बेहतर करने की संभावना थी। एक्शन डायरेक्टर अमीन खतीब की एक्शन कोरियोग्राफी प्रशंसनीय है। जान अब्राहम सिक्स पैक ऐब्स में एक्शन करते हुए जंचते हैं। खलनायक जितेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका में जान के सामने किसी कद्दावर अभिनेता की कमी खलती है। जितेंद्र के रुतबे और मिजाज से अभिषेक मेल नहीं खाते। शरवरी ने किरदार की मासूमियत और पीड़ा को अंगीकार किया है। छोटे प्रधान की भूमिका में क्षितिज चौहान का अभिनय प्रभावी है। तमन्ना भाटिया मेहमान भूमिका में हैं। वेदा के पिता की भूमिका में राजेंद्र चावला का काम उल्लेखनीय है। मौनी राय पर फिल्माया गया आइटम सांग मम्मी जी... थिरकाने वाला है।

-स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

अपनी राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

इधर-उधर की

चीन में 37 वर्ष बाद खोए हुए बेटे से मिले माता-पिता

एक दिन के बच्चे को दादी ने बेच दिया था। इंटरनेट मीडिया

बीजिंग, एजेंसी: चीन में एक माता-पिता का 37 साल बाद खोए हुए बेटे से मिलने की घटना सुर्खियों में है। 1986 में जब बच्चा एक दिन का था तब उसकी दादी ने बिना उसके माता-पिता को बताए उसे बेच दिया था। दादी का मानना था कि दंपती की पहले से दो संतान हैं, ऐसे में वह तीसरे बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हैं। दंपती ने बच्चे की खोज में कई साल बिता दिए। इसी वर्ष फरवरी में, दंपती के रक्त के नमूने शेडोंग प्रांत के पैंग नाम के व्यक्ति से मेल खा गए।

पेट की जांच कर ओवरी कैंसर का लगाया जा सकता है पता

अनुसंधान

एक शोध में कहा गया है कि पेट में सूजन, दर्द या खाना शुरू करने के तुरंत बाद पेट भरा लगने जैसे लक्षणों की जांच से ओवरी (डिंबग्रंथि) कैंसर के एक चौथाई मामलों का शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि सिंपटम ट्रिगर टेस्टिंग माडल से शुरुआत में पता लगने के बाद लगभग 60 प्रतिशत मामलों में सर्जरी के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से हटाना संभव हो पाया। हालांकि, पिछले साक्ष्यों से पता चला है कि ओवरी कैंसर के लक्षण तीन महीने से तीन साल के बीच दिखने शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि ये लक्षण अक्सर अस्पष्ट होते हैं, जिससे जल्दी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह शोध इंटरनेशनल जर्नल आफ गायनोकोलाजिकल कैंसर में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में 1,700 से अधिक महिलाओं को शामिल किया था। इनमें सात प्रतिशत (119) महिलाओं में उच्च ग्रेड सीरस ओवरी कैंसर का पता चला, जो बीमारी का सबसे आम, आक्रामक व घातक रूप है। इनमें से अधिकतर महिलाओं में कैंसर ने उनके दैनिक जीवन में कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया था। वह पूरी तरह से सक्रिय थीं और अधिक मेहनत वाले कार्य के अलावा सब कुछ करने में सक्षम थीं। इनकी उम्र 32 से 89 वर्ष के बीच थी। इन सभी को ब्रिटेन में रिफाइनिंग ओवेरियन कैंसर टेस्ट एक्यूरेसी स्कोर्स से शामिल किया गया था। आइएएनएस

किराए पर ई-स्कूटर हुआ प्रतिबंधित

आस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में बुधवार को बिना हेलमेट लगाए ई-स्कूटर से गुजरता व्यक्ति। हेलमेट न पहनने, फुटपाथ पर सवारी करने, एक से अधिक यात्री ले जाने जैसे कृत्यों के दृष्टिगत द सिटी आफ मेलबर्न काउंसिल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर शहर में किराए पर ई-स्कूटरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लार्ड मेयर निकोलस रीस ने कहा कि ई-स्कूटर चालकों की हरकतों ने अस्वीकार्य सुरक्षा खतरा उत्पन्न किया है। ऐसे में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। इससे जनित सैकड़ो दुर्घटनाओं के कारण आक्रोश उत्पन्न हो गया था। एएफपी

स्क्रीन शाट

आस्ट्रेलिया में मना स्वतंत्रता दिवस रित्विक के लिए यादगार

यह स्वतंत्रता दिवस भी आस्ट्रेलिया में मना रहे हैं रित्विक। इंस्टाग्राम - @rithvikk_dhanjani

देशभक्ति की भावना वैसे तो लगभग हर हिंदुस्तानी में होती है, लेकिन जब विदेशी धरती पर अपने तिरंगे, अपने देश का सम्मान देखते हैं, तो वह भावना और भी ज्यादा सुर्ख रंगों में निखरकर सामने आती है। फिलहाल कामेडी शो आपका अपना जाकिर से जुड़े अभिनेता रित्विक धनजानी के लिए दो साल पहले आस्ट्रेलिया की धरती पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह अविस्मरणीय है। रित्विक बताते हैं, 'पिछले दो वर्षों से मेरा स्वतंत्रता दिवस विदेश में बीत रहा है। इस बार भी मैं एक टूर के सिलसिले में आस्ट्रेलिया में रहूंगा। देश से बाहर रहकर मैंने एक चीज देखी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हिंदुस्तानी तो हर जगह है। आप दुनिया के हर कोने में 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाते देख सकते हैं। देश के बाद लोगों का राष्ट्रप्रेम देखना और प्यारा लगता है। दो साल पहले मैं एक फिल्म फेस्टिवल के लिए आस्ट्रेलिया गया था। वहां 15 अगस्त के दिन एक स्टेडियम में भारतीय लोगों द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में करीब 15-20 हजार हिंदुस्तानी एकत्रित हुए थे। वो मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव था। विदेश में तो इस दिन छुट्टी नहीं होती है, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना और एक साथ राष्ट्रगान गाना मैं कभी नहीं भूल सकता हूं।

शिक्षा और नौकरी के अवसर हमें बनाएंगे और मजबूत : शरवरी वाघ

आजादी के 78 वर्षों में देश ने तरक्की की है। आम आदमी हो या कलाकार हर कोई अपनी तरह से देश से जुड़े अपने प्रेम को जाहिर करता है। जो खूबियां हैं, उनका जिक्र करता है, जो खामियां हैं उसमें बदलाव कैसे लाए उस पर भी बात करता है। वेदा और मुंजा फिल्म अभिनेत्री शरवरी वाघ अपने देश पर गर्व करती हैं। वह कहती हैं कि मेरा देश महान है। हम बहुत अच्छी राह पर हैं। लेकिन और बेहतर बनने के लिए हमें कुछ चीजों पर और ध्यान देने की जरूरत हैं। वह है शिक्षा और नौकरी। एक इंसान तभी अपने लिए कुछ कर सकता है, जब उसे इसमें मजबूत बनाया जाए। दोनों पाकर वह पैसे और इज्जत दोनों कमा सकते हैं। पूरी जिंदगी बन सकती है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि हमारा देश यह करने का प्रयास नहीं कर रहा है, हम दूसरे देशों के मुकाबले इसमें बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर हर नागरिक शिक्षित हो और नौकरी करके अपना घर संभाल पाए, तो उसके साथ देश भी तरक्की करेगा। मैं बेहद खुश हूं कि जो मैं सोचती हूं, वैसी ही कहानी का हिस्सा बनी हूं फिल्म वेदा में जो आज रिलीज हुई है। इस फिल्म में भी न्याय और बराबरी की बात के लिए मेरा किरदार लड़ाई लड़ रहा है।

बराबरी की बात करेगी शरवरी फिल्म वेदा में। इंस्टाग्राम - @sharvari

फिल्म के सेट पर निर्देशक को होनी चाहिए पूरी स्वतंत्रता : तुषार कपूर

अपनी अभिनय कला के विविध पहलुओं को प्रस्तुत करने और अपनी भूमिकाओं में कुछ नया प्रयोग लिए कलाकार भी कुछ मामलों में स्वतंत्रता चाहते हैं। हालांकि, अभिनेता तुषार कपूर कलाकार के साथ सेट पर निर्देशक की भी पूर्ण स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं। शूटिंग के सेट पर किस चीज में पूरी आजादी चाहते हैं? इस पर तुषार कहते हैं, 'मैं चाहता हूं कि किसी भी फिल्म या शो के सेट पर कलाकारों के साथ निर्देशक को भी पूरी आजादी होनी चाहिए। मैं स्वयं निर्देशक की बात मानने वाला एक्टर हूं। निर्देशक जब अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, तो वो कलाकार की बेस्ट परफार्मेंस निकलवाते हैं। वह कलाकार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब निर्देशक स्वतंत्र नहीं होते, किसी दबाव में होते हैं, तो शो या फिल्म का बेस्ट निकल कर सामने नहीं आता है। मेरे हिसाब से कलाकार को सेट पर आजादी तब होती है, जब वह अपने पात्र की पूरी तैयारी करके आते हैं, बराबर रिहर्सल करके आते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि सीन का ढांचा क्या है, उसका मतलब क्या है। जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं, तो आप अपनी तरफ से काम में थोड़ा सुधार भी कर सकते हैं।' तुषार इन दिनों फिल्मों के साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर भी सक्रिय हैं।

अभिनय के साथ प्रोडक्शन में भी सक्रिय हैं तुषार। फाइल

जिम्मेदारियां न समझने वालों से आजादी चाहते हैं नील

धारावाहिकों की शूटिंग के दौरान कई बार छुट्टी वाले दिन भी कलाकारों को काम करना पड़ता है। इन दिनों कलर्स चैनल के धारावाहिक मेघा बरसेंगे शो में काम कर रहे नील भट्ट भले ही कितने ही व्यस्त क्यों न हो, वह ध्वजारोहण का हिस्सा बन ही जाते हैं। नील कहते हैं कि हम कलाकार हैं, अगर छुट्टी ले लेंगे, तो एपिसोड प्रसारित नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ घंटे के लिए शूट करना पड़ता है। हालांकि मैं ध्वजारोहण का हिस्सा बनने से कभी पीछे नहीं रहता हूं। कई बार सेट पर झंडा फहराया है। सेट पर नहीं होता हूं, तो अपनी सोसाइटी में फहराता हूं। देश की किन समस्याओं से नील आजादी चाहते हैं? इस पर वह कहते हैं कि हमारे देश ने इन 78 वर्षों में काफी विकास किया है। मुझे लगता है कि हर बात शिक्षा से जुड़ी है। यहां मेरा मतलब केवल स्कूल से जुड़ी शिक्षा की नहीं है। जीवन जीने के तरीकों की है। नागरिकता का भाव होना जरूरी है। कई लोग हैं, जिन्हें यह सब जानने में दिलचस्पी नहीं होती है, वह अनजान बने रहना चाहते हैं। मैं ऐसे सोच वालों से आजादी पाना चाहूंगा। मुझे 17 वर्षों के करियर में ऐसे धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जिसमें कई सामाजिक मुद्दे उठाए गए हैं। मैं कोई ढोंग नहीं करना चाहता हूं कि ऐसे शोज बदलाव लाते हैं, लेकिन बातचीत शुरू करते हैं, जिससे समाज सतर्क होता है, शिक्षित होता है।

ध्वजारोहण का हिस्सा बनते हैं नील।

केवल देश सेवा मायने रखती है : कीर्ति कुल्हारी

देश के प्रति प्यार, जिम्मेदारी और एकता की भावना 'मिशन मंगल' फिल्म की अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी के मन में बचपन से ही रही है। उनके पिता भारतीय नौसेना में रहे हैं। बहन इस समय आर्मी में हैं। कीर्ति ने अभिनय का माध्यम चुना। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वह कहती हैं, 'आज वह हम जिस आजाद देश में स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, उसे संभाले रखने का काम हमारे सशस्त्र बलों ने बखूबी किया है और कर रहे हैं। इसके लिए कितनों ने अपने खून बहाए हैं। भले ही मैं सेना में नहीं हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां बचपन से समझती हूं।'

सेना का परिवेश घर जैसा: कीर्ति कहती हैं, 'मेरे पापा नौसेना में रहे हैं, बहन आर्मी में हैं। बहन की जहां पोस्टिंग होती है, कई बार मैं वहां उनसे मिलकर आती हूं। मेरे लिए सेना का परिवेश घर जैसा है। मैंने अपनी जिंदगी का अहम समय वहां बिताया है। पापा के नौसेना में होने के कारण मेरी जिंदगी बहुत अलग रही है। मैंने करीब से देखा है, कैसे मेरे पापा देश को पहले रखते हैं। उनके लिए ऐसे में जो भावनाएं अपने देश और जवानों के प्रति होती है, वह दूसरों से अलग होती है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए, अपने देश से प्रेम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर किसी को बराबर समझें। सेना में वह माहौल मिलता है।'

सबसे पहले देश है

बचपन का जिक्र करते हुए कीर्ति कहती हैं, 'मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूं। वहां हर जाति और धर्म के बच्चे मिल जुल कर रहते हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले किस जाति या धर्म से हैं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। न ही कभी यह पूछा कि तुम्हारे माता-पिता किस स्तर पर काम करते हैं। वहां की परवरिश ही ऐसी थी। वहां बस यह सिखाया जाता है कि सेना आपका सबसे बड़ा परिवार है। कोई भाषा और राज्य मायने नहीं रखता है। केवल देश सेवा मायने रखती है। यही अहसास मुझे अपने देश और लोगों से जोड़े रखता है। आप सबको एक बराबर समझते हैं। जब मैं डिफेंस के माहौल से बाहर निकली तो देखा कि आम दुनिया का माहौल अलग है। मेरे लिए सब बहुत अजीब था। फिर भी मैं अपनी जड़ों को नहीं भूली, प्रयास किया आसपास भी लोगों को वैसे ही बना सकूं।'

बचपन से ही कीर्ति को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का है अहसास @iamkirtikulhari (इंस्टाग्राम)

खुद के लिए नहीं पहले देश के लिए सोचें: खुद में आए बदलावों को लेकर आगे कीर्ति कहती हैं, 'सैन्य माहौल ने मुझे अच्छा इंसान बनाया है। छोटी-छोटी चीजों से आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं। आप हर चीज को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लोगों के अनुसार देखते हैं कि सबके लिए क्या अच्छा होगा। मैं खेल में आगे थी। जब प्रतियोगिता होती थी, तो देश भर के बच्चों से मिलती थी। इंसानी भावनाएं बहुत ही जल्द समझ जाती थी। पापा रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो चीजें मेरे भीतर बचपन में डाली गई हैं, वह गहराई से भीतर ही हैं। पहले देश के बारे में सोचना सिखाया गया है, वहीं सबको कहती हूं।' कीर्ति आज (14 अगस्त) जिओ सिनेमा पर रिलीज वेब सीरीज शेखर होम में नजर आई हैं।

तीनों खानों को निर्देशित करना चाहती हूं

कुछ साल पहले एक साक्षात्कार के दौरान अभिनेता शाह रुख खान ने कहा था कि सिनेमा जगत के तीनों खान (सलमान खान, शाह रुख खान और आमिर खान) इसलिए एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक साथ उनका खर्चा उठाना मुश्किल है। अब अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने तीनों खानों को निर्देशित करने पर अपनी राय व्यक्त की है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर उनकी फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर लांच किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू इमरजेंसी पर आधारित इस फिल्म में अभिनय के साथ-साथ कंगना ने इसे निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया है। तीनों खानों को निर्देशित करने पर उन्होंने कहा, 'मैं तीनों खानों के साथ किसी फिल्म को प्रोड्यूस और उसे निर्देशित करना पसंद करूंगी। मैं उनके प्रतिभाशाली पहलुओं को भी दिखाना पसंद करूंगी, जहां वे तीनों अभिनय कर सकें, अच्छा दिख सकें और कुछ ऐसा कर सकें जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। तीनों बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। तीनों के अलग-अलग कलात्मक पहलू भी हैं, कुछ फिल्मों को छोड़कर उन्हें अभी तक नहीं दिखाया गया है। मैं उस पहलू को भी दिखाना चाहूंगी।' आगे कंगना ने दिवंगत अभिनेता इरफान को निर्देशित न कर पाने का मलाल भी जताया। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना ने अभिनय और राजनीति में प्राथमिकता को लेकर कहा कि यह लोग तय करेंगे।

फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी कंगना ● मिडडे

स्वतंत्रता दिवस पर पिताजी से खादी टोपी लेकर पहन लेता था : पंकज त्रिपाठी

आजादी का जश्न अपने देश के साथ विदेश में भी मनाने के लिए उत्सुक हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। वह 18 अगस्त को अमेरिका में होने वाली 42वें वार्षिक भारत दिवस परेड में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, 'वहां का माहौल देखना है कि प्रवासी भारतीय यह उत्सव मनाने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं।' आगे पंकज कहते हैं, 'बचपन में मैं इस दिन पर अपने पिताजी से खादी से बनी गांधी टोपी लेकर पहना लेता था। वो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर खादी से बनी गांधी टोपी पहनते थे। मैं आज भी खुद खादी और हैंडलूम के कपड़े पहनता हूं। खादी से बने वस्त्र का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी खास जुड़ाव रहा है।' अब देश से जुड़ी किन समस्याओं से उन्हें आजादी चाहिए? इस पर पंकज कहते हैं, 'ट्रैफिक से बहुत समस्या होती है। पर्यावरण को लेकर भी चिंता रहती है। मैं अपने गांव में दो-तीन ऐसी संस्थाओं से जुड़ा हूं, जो वृक्षारोपण करती हैं। मैं खुद जब गांव जाता हूं, तो पेड़ लगाकर आता हूं।' यादगार ध्वजारोहण का जिक्र करते पंकज ने बताया, 'कुछ साल पहले लेह में मैं शूटिंग कर रहा था। हमने लेह मिलिट्री बेस से कहा था कि मैं आना चाहता हूं। उन्होंने हमें खुशी-खुशी परेड देखने के लिए बुलाया था।'

इस साल अमेरिका में भारत दिवस परेड में शामिल होंगे पंकज @pankajtripathi (इंस्टाग्राम)

****